खण्ड-302, अंक-5
बुधवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1894
(14 मार्च, 1973 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 302 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 14 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मंडल, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोबिन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 356

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुरहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री (उर्फ भया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
काजी मसूद, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णाकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री

गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर,
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैश्य,
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नर्नासिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यार लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री

बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगती सिंह बिशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महाबीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वर दत्त सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल दहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
राम गोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम जियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनगीना मिश्र, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी

रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़—रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबिलास पाण्डेय, श्री
रामरतन पान्डेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
रामहर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
बिजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
बिजय बहादुर सिंह, श्री
बिजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
बीर बहादुर सिंह, श्री
बीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शान्ती चरण पिन्डारा, श्री
शान्ती देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पाण्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिव शकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकुरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उफ छुन्नू बाबू)
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
संयद मुतजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती

सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नबाव
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट—पंचायती राज मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य एवं राज्य सूचना मंत्री, श्री पी० डी० टन्डन भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 14 मार्च, 1973

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

**1—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

(श्री शीरेन्द्र वर्मा का नाम लिये जाने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

वे बीमार हैं ।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

उन्होंने मुझे अधिकृत किया है ।

श्री अध्यक्ष—

बाद में ले लिया जायेगा।

श्री निरंजानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन् ट्रेजरी बेंचेज के हाल देखिये। श्री महमूद अली खां के सिवाय और कोई मंत्री नहीं है। सदन को कितना दुर्लक्ष करते हैं ।

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

हम तो हैं ।

[स्थगित]

सौरीपुर आगरा में डाकुओं द्वारा अपहृत तीर्थ यात्रियों की विमुक्ति

**2—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)—

क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1972 के अंतिम सप्ताह के आगरा जिले में सौरीपुर तीर्थ यात्रा के लिये आये हुए जैन तीर्थ यात्रियों की एक टोली को डाकू दल पकड़ कर ले गया और उसके लिये कई लाख रुपये की मांग की जा रही है ? यदि हां, तो इनके छुटकारे के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

क्या यह भी सही है कि इन तीर्थ यात्रियों के छुड़ाने के लिये चम्बल घाटी शांति मिशन की सेवाएं सरकार ने मांगी हैं ? और इस मिशन को कितनी सफलता मिली है ?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28-12-72 को सौरीपुर (बटेश्वर) थाना वाह, आगरा में आई जन तीर्थ यात्रियों की एक टोली में से 4 व्यक्तियों को डाकू पकड़ कर ले गये थे, और डाकुओं ने रुपये की मांग की थी। किन्तु पुलिस के परिश्रम एवं दबाव के फलस्वरूप इन अपहृत व्यक्तियों को बिना रुपया दिये डाकुओं ने मुक्त कर दिया और ये सकुशल अपने निवास स्थान को वापस गये।

2—अपहृत व्यक्तियों को मुक्त कराने के लिये आगरे की पुलिस ने शांति मिशन के एक सदस्य से सहयोग के लिये अनुरोध किया था। पुलिस के प्रयासों एवं शांति मिशन के सहयोग के फलस्वरूप अपहृत व्यक्तियों को मुक्त कराने की सफलता मिली।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इन शांति मिशन के लोगों जिन्होंने कि पुलिस की सहायता दी, के नाम क्या-क्या हैं ? क्या यह सही है कि इन जैन तीर्थ यात्रियों की टोली से डाकू लोग रुपया न लेकर लाखों रुपये के गहने लेकर चले गये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इस शांति मिशन के एक व्यक्ति तहसीलदार सिंह से पुलिस वालों ने बात की थी और उनसे सहायता की कामना की थी। इसकी सूचना नहीं है कि छूटने के बाद भी डाकुओं ने उनसे रुपया लिया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन डाकुओं ने उनका अपहरण किया था उनकी गिरफ्तारी की चेष्टा की गयी या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, डाकुओं के इस गैंग को गिरफ्तार करने का प्रयास चालू है और कुछ गिरफ्तारियां हुई भी हैं जिनकी सूचना मैंने सदन को दे दी है।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या यह सही है कि उसके बाद में भी आगरा में अपहरण की जो घटनायें हुई हैं, वे पहले से ज्यादा हैं। जहां तक सौरीपुर तीर्थ यात्रियों को छोड़ने का सवाल है वह शांति मिशन के लोगों ने उन्हें छुड़ाया है। माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि पुलिस के दबाव से ये लोग छटे हैं, बिलकुल गलत है। अगर पुलिस उन्हें छुड़ाती तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता था। इसलिये यह सचना गलत है। शांति मिशन के लोगों ने उन्हें छुड़ाया है और फिर भी लाखों रुपये के गहने डाकुओं के पास ही छूट गये थे।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर तो आपने स्वयं ही दे दिया ।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

मान्यवर, यह पूछ रहा हूं कि यह सही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, माननीय सदस्य किस रूप में अपनी भावना व्यक्त करते हैं, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन यह निश्चित है कि पुलिस के भयंकर दबाव के कारण डाकुओं ने उन्हें छोड़ने के लिये बाध्य होना पड़ा और वे छूट गये ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है और जैसा कि हमारे माननीय सदस्य परिहार जी ने कहा कि शांति मिशन के लोगों की एक मीटिंग राजा साहेब की अध्यक्षता में हुई थी, उसी के अनुसार ये तीथ यात्री लोग छोड़े गये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

शांति मिशन के लोग जो मिले तो उन की सहयोग की कामना की गई । उनकी कोई इस तरह की मीटिंग हुई, इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मान लिया जाय उनके ही उत्तर को सही मान लिया जाय कि पुलिस के भयंकर दबाव के कारण तीर्थ यात्री छूटे हैं, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि किस स्थान पर दबाव डाला गया और किस प्रकार से वे छोड़े गये और किस स्थान पर छोड़े गये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, उसी आगरा के समीप ही उनको छोड़कर वे चले गये थे । उनको लेकर वे भागने में सफल नहीं हो सके । उत्तरोत्तर उनका पीछा होता रहा और चारों तरफ पुलिस दबाव करती रही और इनको लेकर भागने में कठिनाई होने लगी तो वे छोड़कर चले गये ।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक इस संबंध में कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जी हां, करीब 6 गिरफ्तारियां हुई है ।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

जिस डाकू ने उनका अपहरण किया उसका नाम बतलाने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण —

डाकू तो आगरा के ही हैं, उनका नाम मैं नहीं जानता हूं । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो आगरा के हैं, वे ही इसकी सही सूचना दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र बिक्रम—

मान्यवर, ये पुलिस मिनिस्टर हैं और इनको डाकू का नाम तक नहीं मालूम है, ये बिलकुल निकम्मे हैं, कुछ नहीं जानते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप इस चीज को अपने खयाल में रखें कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर शार्ट नोटिस में जितना दे सकते थे उन्होंने दिया । आप जल्दी में मांग करते हैं कि वे उत्तर दें तो सब चीजों को डिटेल में वे नहीं बतला सकते ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भयंकर दबाव डालने की जो बात उत्तर में कही गयी है, तो वह भयंकर दबाव किस पर किसने डाला ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

हमारे यहां का डाकू उन्मूलन स्क्वाय, आगरे की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस, राजस्थान की पुलिस, इन सब ने इकट्ठा होकर जहां से वे लोगों को भगाये थे, उसके आसपास सौरी क्षेत्र में उनका पीछा किया जिससे उनको बाध्य होना पड़ा कि वे उन आदमियों को छोड़कर चले जायं ।

जिला परिषद्, झांसी द्वारा संचालित विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था

**3—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, झांसी जिसके अध्यक्ष जिलाधीश हैं, द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 10वीं तक 5 कक्षाओं और सेक्सनों आदि को पढ़ाने के लियें3–4 अध्यापक ही प्रत्येक स्कूल में हैं । विषय व कक्षा के हिसाब से अध्यापक न होने के कारण विद्यार्थियों में घोर असंतोष और चिंता व्याप्त हो रही है ? यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा को केवल दो माह ही रह गये हैं विद्यार्थियों के हित के लिये शीघ्र ही पढ़ाई की समुचित व्यवस्था करने की कृपा की जायगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जिला परिषद्, झांसी द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था कर दी गई है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह व्यवस्था कब कर दी गयी थी, इनकी वांट कब निकली थी, इनकी नियुक्ति किस तारीख को की गयी और अध्यापकों ने कब चार्ज लिया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

16–12–72 को इन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया। लालबहादुर शास्त्री उच्चतर विद्यालय में 4 अध्यापकों की मांग थी, उसे पूरा कर दिया गया। जिला परिषद् उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पाली में एक अध्यापक की मांग थी उसे पूरा कर दिया गया, जवाहर लाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नाराट में पूरा स्टाफ था इसलिये वहां देने की आवश्यकता नहीं ह।

श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

जब जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी शिक्षा को सरकार नें अपने हाथ में ले लिया है तो ऐसे हायर सेकेन्ड्री स्कूल जिनको जिला परिषदें चला रही हैं उनको सरकार अपने नियंत्रण में लेने की कृपा करेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि परिधि से ऊपर उठ कर हायर सेकन्ड्री स्कूल खोले गये, इसलिये शासन को उनके लेने का कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने अपना स्कूल खोला है और उनको चलाने के लिये भी वही जिम्मेदार हैं।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

माननीय, मैं माननीय मन्त्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं। आपने कहा है कि 16 दिसम्बर, 72 को फैसला ले लिया गया लेकिन जुलाई में एक भी अध्यापक नहीं रखा गया। जनवरी में मैंने प्रश्न दिया, फिर फरवरी में वहां एक अध्यापक की नियुक्ति की गयी। 6 महीने पहले जिनके इंटरव्यू लिये गये थे उनमें से एक भी नहीं लिया गया। आज भी वहां नटारा, पाली और बबीना में एक भी अध्यापक नहीं पहुंचा है। मेरी इस सूचना को सही मान कर क्या आप इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय, जो सूचना मेरे पास है उसके बारे में माननीय सदस्य ने संदेह किया है, मैं उसकी तत्काल जांच करा लंगा।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह सिद्धांत माना जाता है कि जितनी कक्षायें हों उससे ड्योढ़े अध्यापक प्रिंसिपल के अतिरिक्त रखे जाते हैं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

केवल ड्योढ़े को ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों की संख्या और सेक्शन्स का कंसीडरेशन होता है। लेकिन जो निश्चय हुआ और आवश्यकता बताई गई उसके अनुसार नियुक्ति का निश्चय करके सूचना मुझे ी गई है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन तीनों विद्यालयों में कब से अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं और जिलाधीश को प्रधानाचार्यों के कब प्रार्थना-पत्र दिये और कब नियुक्तियां की गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय, जुलाई से स्थान रिक्त थे। उसके बाद 16 दिसम्बर को सारे प्रधानाचार्य जिलाधीश से मिले। इससे पहले जिला परिषद् को स्थानान्तरित हुए, उसका रिकार्ड नहीं मिल पाया। इसलिये कार्यवाही नहीं हो सकी।

श्री रामगोपाल सण्ड—

माननीय, जुलाई से विद्यालयों में अध्यापकों के स्थान रिक्त थे और जिलाधीश महोदय को लिखा गया और रिकार्ड न मिलने की ुहाई दी गई और कोई इंतजाम नहीं किया गया। 3–3 विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई जिससे हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हुआ तो क्या मंत्री जी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार कर रहे ह ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर देखा जा रहा है कि किन-किन परिस्थितियों में वे नियुक्ति करने में सफल नहीं हुए। अगर उनकी लापरवाही होगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने में किसी को संकोच नहीं है।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि झांसी के समान प्रदेश के जिन माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं उनकी शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, सूचना दे दी देखा जायगा और जो कार्यवाही की जा सकती है करने का प्रयास किया जायगा।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पाली, नाराट और बबीना के विद्यालयों में कितने अध्यापक काम कर रहे हैं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इस समय नियुक्त अयापकों की संख्या बबीना में 4, छत्रसाल माध्यमिक विद्यालय नाराट में 3 और पाली में एक की मांग थी उसकी नियुक्ति हुई है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

मैंने पूछा है कि कितने अध्यापक काम कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप जोड़ लें।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

श्रीमन्, नाराट में केवल तीन अध्यापक हैं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, आपकी सूचना को देखूंगा। जो सूचना मेरे पास है, उसको मैं दे रहा हूं आपकी सूचना की जांच कराकर ही जवाब दे सकूंगा।

ग्राम पीपर, (बांदा) के ललुआ धोबी को जिन्दा जलाया जाना तथा भजुवा डाकू को गिरफ्तारी का प्रयास

**4—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़), श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़), श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री रूप नाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि बांदा जिले के थाना बयांसा के ग्राम पीपर के निवासी पिछड़ी जाति के धोबी, श्री ललुआ को 28-1-73 को गांव में ही पड़ से बांध कर कुछ सवर्णों द्वारा जिन्दा जलान की लोमहर्षक घटना हुई है जिससे भयानक रोष व डर गरीबों में व्याप्त है? यदि हां, तो सरकार ने तुरन्त क्या कार्यवाही इस विषय में की और क्या यह भी सही है कि यह पिछले छः महीनों में अत्याचार और मारने व जलाने की 7वीं घटना है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22-1-73 को ललुआ निवासी ग्राम बुधुआ पुरवा मजरा पियार, बांदा ने थाना बबौसा पर इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी कि दिनांक 21-22-73 की रात में जब वादी उसका भाई, मामा व एक और व्यक्ति घर के ओसारे में अपनी-अपनी चारपाई पर घरेलू बात कर रहे थे चार अज्ञात बदमाश आये और उन्होंने चारों व्यक्तियों को बंदूक दिखाकर रस्सियों से बांध दिया व जान से मारने की धमकी दी। दरवाजा खुलवाकर अन्दर घुसे। बदमाशों ने वादी से माल के बारे में पूछा। न बताने पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिससे वादी की सारी खाल जल गई। शोर करने पर और लोग आ गये। बदमाश सामान लूट कर भाग गये।

उक्त सूचना पर थाना बबौसा पर एक मुकदमा धारा 394/397 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत कायम हुआ व विवेचना प्रारम्भ हुई। वादी की बाद में मृत्यु हो जाने पर मुकदमा धारा 394/397/302 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया। मृतक के परिवार को सुरक्षा हेतु व्यवस्था करा दी गई है।

इस घटना के अतिरिक्त ऐसी कोई और घटना घटित होने की सूचना नहीं है। इस घटना से क्षेत्र में किसी प्रकर का आतंक नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

माननीय, एक लोमहर्षक यह घटना हुई, मंत्री जी ने कहाकि सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है लेकिन मन्त्री जी कृपया यह बतायें कि यह जो लोमहर्षक घटना घटी है उसके सम्बन्ध में पुलिस ने कितनी गिरफ्तारियां की हैं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

एक भुजवा डाकू का गैंग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बोर्डर पर कार्य कर रहा है, ऐसा शुब्हा है कि उसी के द्वारा यह घटना हुई है। उसके दल को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। एफ0 आई0 आर0 में किसी का नाम नहीं दिया गया है कि उन बदमाशों ने हमला किया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मन्त्री जी ने कहा कि किसी का नाम एफ0 आई0 आर0 में नहीं दिया गया। पुलिस तलाश करती रही है, अभी तक किसी का पता नहीं लगा है, यह जरूर है कि उस क्षेत्र में भुजवा डाकू का गैंग आपरेट कर रहा है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी भी की गई या नहीं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उस गैंग के लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास है। इसी सम्बन्ध में बांदा में एक बदमास मारा गया है जिस पर 2000 रुपये का इनाम था और एक और बदमाश मारा गया है जिस पर 1500 रुपये का इनाम था, उनको पकड़ने का प्रयास हो रहा है, उनका भी ठिकाना जल्द हो जाय।

श्री [illegible]गोविन्द सिंह नेगी—

मन्त्री जी कहते हैं कि यह कयास है फला डकैतों के गिरोह ने मारा होगा, अभी तक पुलिस को मालूम नहीं हो सका कि किस ने मारा। इसको देखते हुए क्या मन्त्री जी इसकी इन्क्वायरी सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द करने की कृपा करेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सी0 आई0 डी0 तो सम्बन्ध में पहले से ही जांच कर रही है लेकिन अभी तक कोई तथ्य मालूम नहीं हो सके हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मन्त्री जी ने बताया कि भुजवा डाकू का गैंग वहां आपरेट कर रहा है तो क्या एफ० आई० आर० में किसी गैंग का नाम लेकर शुब्हा जाहिर किया गया है या प्रत्यक्षदर्शी ने ऐसी कोई सूचना दी है कि उसमें किसी विशेष गैंग का हाथ है या केवल यह कयास मात्र है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

एफ० आई० आर० में किसी तरह का कोई सन्देह नहीं किया गया था, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि न मालूम किन बदमाशों ने बन्दूक, लाठी और फरसों से घातक हमला किया और यह हरकत की । अब अनुमान है कि उस क्षेत्र में भुजवा डाकू का गैंग आपरेट कर रहा है, यह कार्य उसका हो सकता है ।

श्री राम बिलास पांडेय—

रात में कितने बजे यह वाक्या हुआ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

रात के लगभग 11–12 बजे यह दुर्घटना हुई है ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

इस विषय को ध्यान में रखते हुए कि पिछले 2–3 मास में झांसी, बांदा, आगरा, वाराणसी और इलाहाबाद में ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश के लगभग सभी जिलों में डकैती, हत्या और लूटपाट तेजी से बढ़ रहा है । तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इसके उन्मूलन के लिये कोई विशेष कदम उठाने जा रहे हैं या विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, विशेष प्रबन्ध तो हमेशा जहां दुर्घटना होती है, कर ही दिया जाता है । इसमें उन्हें यह भी सतर्क कर दिया गया है कि ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम और बदमाशों के पकड़ने की भी व्यवस्था की जाय ।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—

मुझे बोलने का क्यों नहीं मौका देते ? क्या मेरे अधिकार खतम हो गये ? एक दर्जन बार खड़ा हो चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो सबको मौका देता हूं । पहले उनका नाम ले रहा हूं जिनका प्रश्न है ।

श्री बलवीर सिंह—

क्या गृह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आदमी जलकर मरा था, उसका डाइंग-डिक्लेरेशन हुआ था? क्या इनवेस्टीगेशन की किसी स्टेज पर यह बात आई है कि इनको सवर्ण लोगों ने जलाया है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, उसने स्वयं अपने आप एफ० आई० आर० लिखवाई है थाने में आकर और तब उसको हास्पिटल भेजा गया है । उसने कहा कि सम्पत्ति नहीं जलाई । उसके शरीर में मिट्टी का तेल डालकर डराया-धमकाया जा रहा था । बाद में दियासलाई से आग लगा दी गयी थी, जिससे यह जला था ।

श्री बलवीर सिंह—

मेरा मतलब, मान्यवर, सवर्णों ने हरिजनों को जलाया, से है। क्या सवर्णों ने जलाया या हरिजनों ने जलाया ?

श्री अध्यक्ष—

वह जो पूरी रिपोर्ट लिखी है, उसका जिक्र कर दिया उन्होंने। सवर्णों ने नहीं उसमें तो यह लिखा है कि वह सो रहा था और अज्ञात बदमाश आये। अब वे किस जाति के थे, यह बात पूछना गलत है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, एक प्रश्न पर इतना समय न दें। बाकी सूची पड़ी रह जाती है, इस पर भी ध्यान दें।

श्री चिरंजी लाल (जिला एटा)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सी० आई० डी० को इन्क्वायरी करने के लिये यह मामला कब दिया गया और उसका नतीजा क्या निकला ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

घटना के बाद इन्क्वायरी के लिये दे दिया गया। जांच रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर और बांदा में ही क्यों हमले और आगजनी के केसेज हो रहे हैं, उसके क्या कारण है और सरकार ने क्या ठोस कदम इनको रोकने के लिये उठाये हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि केवल बांदा और हमीरपुर में हो रहे हैं, तो मैंने कई बार इस सदन में कहा है कि वहां पर पत्रकार बन्धु ऐसे हैं जो एक विशेष पार्टी से सम्बन्धित हैं और उनकी कृपा से कुछ खबरें उलटी-सीधी आ जाती हैं। जहां तक अत्याचार न होने देने का प्रश्न है शासन इस ओर सक्रिय है और बड़े ठोस कदम उठा रहा है। शासन ने वहां के जिलाधिकारी को भी इस सम्बन्ध में निर्देश दे दिये हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पिछले छः माह में कितनी मारने की, अत्याचार करने की और जलाने की घटनायें हुई हैं जिनकी रिपोर्ट थाने में लिखाई जा चुकी है ? यह बात मैं बांदा के लिये पूछ रहा हूं। मैंने इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रश्न भी पूछा है, लेकिन उसका कोई निश्चित जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो प्रश्न पूछा है वह उस क्षेत्र के बारे में है और उसका जवाब भेज दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, जो प्रश्न के उत्तर मिलते हैं वह निश्चित नहीं मिलते हैं। आप इसको पोस्टपोन कर दीजिये..... (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह श्री सुरेन्द्र विक्रम कथावाचक कह रहे हैं तो क्या यह सही है और इनके कहने का क्या कारण है और यह क्यों कह रहे हैं ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि मृतक को शारीरिक परीक्षण जब हुआ था तो क्या उसका कारण आग लगना बताया गया था या चोट लगना बताया गया था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जो पोस्ट मार्टम हुआ था उसमें चोट लगने से मृत्यु का कारण बताया गया था।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

आदरणीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो शिकायतें बांदा जिले के बारे में कही गयी हैं वह यह कि वहां हरिजनों के प्रति ज्यादा ज्यादती होती है। मन्त्री जी का कहना है कि नहीं। कुछ अखबारनवीस बढ़ा चढ़ाकर अतिरक्ति बातों को लिख दिया करते हैं। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह बांदा का प्रतिनिधित्व करते हैं वह कब-कब वहां पधारे और वहां की स्थिति का अध्ययन किया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, मैं बादा तो प्रायः ही जाता रहता हूं और उन्हें यह शंका होनी भी नहीं चाहिये कि कोई अपने घर नहीं जायगा। वह न जाते हों तो बात दूसरी है क्योंकि वह वयोवृद्ध हैं। मान्यवर, मैंने इन घटनाओं के स्थानों को भी व्यक्तिगत रूप से देखा है। श्रीमती चन्द्रशेखर भी वहां गयीं थीं और उन्होंने भी जानकारी हासिल की। ऐसी बात नहीं है कि हम इन घटनाओं के प्रति उदासीन हैं और जागरूक नहीं हैं। जहां ऐसी घटनायें होती हैं वहां हम कोई कदम नहीं उठाते तो यह शंका निर्मूल है।

श्री महीलाल—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बबायं)—

जब महीलाल खड़े ही नहीं हुए तो आपने उनका नाम क्यों बुलाया ? वह बल बबलू हैं। उन्हें कैसे इजाजत दी ?

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब आपने महीलाल जी को प्रश्न पूछने के लिये बुलाया तो वह प्रश्न पूछ सकते हैं या व्यवस्था का प्रश्न भी उठा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न पूछ सकते हैं। व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री महीलाल—

क्या आप जिस दल के प्रश्न होंगे उन्हीं को मौका देंगे और दूसरे दल वालों को मौका नहीं देंगे ? मैं दस बार खड़ा हुआ और आपने मुझे मौका नहीं दिया।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

व्यवस्था का सवाल पूछने का अवसर तो सवालों के बाद मिलना चाहिये। अभी यह दूसरों का समय भी नष्ट कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

इन्होंने बांदा में डकैत और बदमाश पाल रखे हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बरेली नलकूप मंडल में हरिजन क्टीन ग्रेड क्लर्कस

*1—श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री राम बचन यादव (जिला आजमगढ़), श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर) तथा श्री सैयद मुर्तजा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नलकूप मण्डल, बरेली के अन्तर्गत नैत्यिक कोटि लिपिक (क्टीन ग्रेड क्लर्क) की कितनी संख्या है और उनमें से कितने (शिड्यूल्ड कास्ट) अनुसूचित जाति के हैं और यदि अनुसूचित जाति के 18 प्रतिशत आरक्षण से कम हैं तो सरकार ने उनकी पूर्ति के लिये क्या कायवाही की है और क्या करने जा रही है?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

बरेली नलकूप मंडल के अन्तर्गत नैत्यिक कोटि लिपिकों की सख्या 62 है जिनमें से 3 लिपिक अनुसूचित जाति के हैं।

18 प्रतिशत आरक्षण मण्डलीय या खण्डीय स्तर पर नहीं किया जाता है वरन् आरम्भ में ही विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के समय यह किया जाता है। कमी पूरा करने के लिये अगली परीक्षा के समय 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित किये जाते हैं।

*2—श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री राम वचन यादव, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री सईद मुतजा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण लिपिकों (डिपार्टमेंटल इम्तहान पास) के प्रविष्ट (आने पर) होने पर वर्ष 1972 में कितने विभाग में कार्यरत बिना परीक्षा उत्तीर्ण नैत्यिक कोटि लिपिकों को उनकी सेवाओं से अलग कर दिया गया है और उनमें से कितने अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के हैं तथा कितने समय की सेवा करने के उपरान्त उन्हें सेवाओं से अलग किया गया है?

श्री राजबिहारी सिंह—

219 नैत्यिक कोटि लिपिकों को उनकी सेवाओं से अलग किया गया है। इनमें से 29 अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के हैं। इन 29 में से 20 की सेवा अवधि 1 साल से कम की थी और 9 की सेवा अवधि 1 साल से अधिक थी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि 18 प्रतिशत का खण्डीय और मंडलीय स्तर पर किन कारणों से अब तक लागू नहीं किया गया?

श्री राज बिहारी सिंह—

जो परीक्षा होती हैं वह प्रान्तीय स्तर पर होती हैं। उसमें 18 प्रतिशत या 25 प्रतिशत हरिजनों के लिये रिजर्व की जाती है। उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होता है उनकी नियुक्ति मण्डल और खंडीय स्तर पर होती है। वहां पर 18 प्रतिशत रिजर्व [illegible] है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन जगहों पर सुपरिन्टेंन्डिग इजीनियर परीक्षा लेकर नियुक्ति करेगा। जब इम्तिहान शुरू में हो गया तो उसके बाद प्रान्तीय स्तर का सवाल ही नहीं है। सर्विस रूल्स सन् 1970 में बने और 31-7-71 के गजेट में यह साफ लिखा है कि एस० ई० नियुक्तियां करेंगे। उसके अलावा सब स्तरों पर कोई नियुक्ति नहीं करेगा। जब उन्होंने नियुक्ति कर दी तो फिर दूसरी नियुक्ति का क्या सवाल है और 219 आदमी क्यों निकाले गये ?

श्री राज बिहारी सिंह—

वे 219 आदमी इसलिये निकाले गये थे क्योंकि वे परीक्षा पास नहीं थे। उनकी जगह वे आदमी रख दिये गये जो परीक्षा में उत्तीर्ण थे।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या माननीय मन्त्री जी की यह जानकारी में है कि अगर शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों का 18 प्रतिशत आरक्षण पूरा नहीं होता है तो उन्हें नहीं निकाला जाता है चाहे उन्होंने अल्प-काल के लिये ही सेवा क्यों न की हो ?

श्री राज बिहारी सिंह—

यदि उनके आरक्षण में कमी होती है तो अगले साल के इम्तिहान में उनकी पर्सेन्टेज बढ़ा दी जाती है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

प्रश्न संख्या 2 में निकालने की बात कही गयी है। मेरा कहना यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोग उस स्थिति में नहीं निकाले जाते हैं यदि उनका 18 प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं होने वाला है। इस नियम का पालन क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

मुझे यह मालूम नहीं है, इसकी जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार को यह मालूम है कि सर्विस रूल और आई० एम० ओ० के हिसाब से सुप-रिन्टेंडिग इन्जीनियर एम्लाएमेन्ट एक्सचेंज से दरख्वास्त मांगते हैं और उसके बाद वे इम्तिहान लेते हैं ? जब वे नियुक्ति करने की फाइनल अथारिटी हैं तो दूसरी नियुक्ति के लिये इम्तिहान किस आधार पर लिया गया ?

श्री राज बिहारी सिंह—

सालाना प्रतियोगिता होती है और जो पास होते हैं उन्हें काम चलाने के लिये भेज देते हैं। सुपरिन्टेंन्डिग इन्जीनियर को अधिकार कि वे नियुक्ति कर लें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

चीफ इंजीनियर ने यह ताकत किस आधार पर अपने हाथ में ली है ? सन् 1950 और सन् 1971 के रूल्स में यह साफ था कि सुपरिन्टेंन्डिग इजीनियर इम्तिहान लेंग और जो फिट केन्डीडेट्स होंगे उन्हें वे स्वयं नियुक्त करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इम्तिहान हो गया और नियुक्तियां हो गयीं तो वह कौन सी अथारिटी है जिसके आधार पर इम्तिहान लेकर उन्हें निकाला जा रहा है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

जो कुछ मोहम्मद अतरार अहमद साहब ने कहा है मैं उसकी जांच करा लूंगा कि उसमें क्या सत्यता है।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि राज्य स्तर पर संरक्षण के प्रतिशत को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। मंडलीय स्तर पर और जिला स्तर पर उनके पर्सेन्टेज को पूरा करने के बारे में माननीय मन्त्री जी को क्या कहना है?

श्री राज बिहारी सिंह—

माननीय नेता विरोधी दल की बात सही है। जहां उनको अधिकार है उनकी नियुक्तियां करते होंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इधर भी हम बार-बार खड़े हो रहे हैं।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

जो लोग निकाले गये हैं उनकी क्या योग्यता थी और वे किस आधार पर निकाले गये हैं? निकालने के समय उनकी लेंथ आफ सर्विस क्या थी?

श्री राज बिहारी सिंह—

मान्यवर, जहां तक योग्यता का सवाल है उसको तो कम नहीं किया जा सकता है। जिस सर्विस के लिये जो योग्यता निर्धारित है वह तो रहेगी लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार सचेत है और विभागों को लिख दिया गया है कि जब तक पूरा न हो उनका कोटा बढ़ा दिया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो कोटा 18 प्रतिशत पूरा होने की बात है इसलिये आपने इसको 25 प्रतिशत कर दिया है, तो जब तक 18 प्रतिशत पूरा न हो, मैं मंत्री जी की जानकारी के लिये बतला दूं कि संविद सरकार ने इसको 45 प्रतिशत किया था जब तक कि 18 प्रतिशत पूरा न हो जाय और जो प्राथी रिजेक्ट कर दिया जाय, यदि वह हरिजन है, तो राज्य सरकार से उसको अयोग्यता के आधार पर न लेने की आज्ञा लेनी पड़ेगी, तो क्या आप इस बात पर विचार करेंगे?

श्री राज बिहारी सिंह—

इस जानकारी के लिये माननीय सदस्य को बधाई। अवश्य विचार कर लूंगा।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

जिन्होंने विभागीय इम्तहान पास नहीं किया है उनके लिये तो नियम यह है कि प्रमोशन रुक जाता है। उसको सर्विस से अलग नहीं किया जाता है। तो क्या मंत्री ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिन्होंने डिपार्टमेंटल इक्जामिनेशन पास नहीं किया है उनको पुनः मौका देकर कान्टीयू करायेंगे?

श्री राज बिहारी सिंह—

मैं माननीय सदस्य को समझा नहीं सका। आजकल हर सर्विस के लिये कोई न कोई विभागीय परीक्षा पास करना होती है। उसको पास करने के बाद ही आदमी सर्विस में आता

है । तो यह प्रमोशन के लिये परीक्षा नहीं थी । वह लोग एडहाक बेसिस पर रक्खे गये थे और जब परीक्षा में उत्तीर्ण लोग आ गये तो उनको हटा दिया गया ।

श्री राम गोपाल संड—

जो लोग निकाले गये उनमें हरिजन कितने थे और कितने दिन काम किया था ?

श्री राज बिहारी सिंह—

29 को निकाला गया था । यह लोग एक साल से कम की सर्विस के थे ···

श्री अध्यक्ष—

यह तो उत्तर में दिया गया है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि कर्मचारियों की छटनी करते समय सरकार ने सिद्धांततः इस बात को मान लिया है कि अगर किसी जगह हरिजनों का कोटा निश्चित अनुपात में नहीं है तो उनको कनिष्ट होते हुये भी न निकाला जाय । तो क्या इस सम्बन्ध में परिपत्र विभागों को भेज दिया गया है, यदि नहीं, तो क्या अब भेज देंगे ?

श्री राज बिहारी सिंह—

मान्यवर, सरकार ने निर्णय लिया है तो जरूर परिपत्र भेज दिया गया होगा । मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री राम वचन—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिला स्तर या मंडल स्तर पर जो चुनाव होते हैं, जो परीक्षायें होती हैं, उनमें प्रायः भेद भाव बरता जाता है, ऐसी स्थिति में क्या मंत्री जी यह आदेश देंगे कि जो योग्यता निर्धारित है उस योग्यता के आधार पर बिना परीक्षा लिये ही हरिजनों को जितनी रिजर्व सीट्स उनकी पूरी करना है उनको करने का प्रयास करें ताकि उनकी जगह पूरी हो जाय ?

श्री राज बिहारी सिंह—

यह सुझाव है, इस पर विचार कर लिया जायगा ।

अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई) द्वारा गुप्ता इन्जीनियरिंग वर्क्स गाजीपुर, के साथ अनुबन्ध

*3—श्री शम्भू नाथ चौधरी तथा श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार इस तथ्य की जानकारी करेगी कि गाजीपुर जनपद के लिफ्ट सिंचाई विभाग के अधिशासी, अभियन्ता श्री आर0 बी0 एल0 अग्रवाल ने माइल्ड स्टील के 48 इंच व्यास के पलेन बनाना और उसके साथ सम्बन्धित दूसरे कार्यों की जिसकी लागत करीब 98 हजार रुपये है बिना विधिवत् कार्यवाही और निवेदन सूचना को समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराये ही अवैध ढंग से गुप्ता इन्जीनियरिंग वर्क्स, स्टेशन रोड, गाजीपुर के साथ जून, सन् 1972 में कोई संविदा (एग्रीमेंट) किया है ? यदि हां तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उस समाचार-पत्र का विवरण जिसमें उक्त कार्य की पूर्ति के लिये सूचना प्रकाशित हुई है, प्रस्तुत करेगी ?

श्री राज बिहारी सिंह—

मेसर्स गुप्ता इंजीनियरींरग के साथ जून, 1972 में करीब 98,000 रुपये के लागत का माइल्ड स्टील के 48 इंच व्यास के फ्लेन्ज बनाने एवं तत्सम्बन्धी अन्य कार्य हेतु अधिशासी अभियन्ता, श्री आर0 बी0 एल0 अग्रवाल ने एक अनुबन्ध किया था ।

शासन को प्राप्त सूचना के आधार पर निविदा समाचार-पत्रों में छापने के लिये सूचना विभाग को भेजी गयी पर सूचना विभाग में इस सम्बन्ध में कोई कागजात उपलब्ध नहीं है ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

माननीय, दो चीजें हो गयीं । एक तो प्राप्त सूचना है कि ···

श्री चिरंजीलाल—

(व्यवधान) ···मेरा सवाल था ···

श्री अध्यक्ष—

आप उस पार्टी के अन्दर नहीं मालूम होते ह ?

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

आपकी सूचना के अनुसार निविदा समाचार-पत्रों में छापने के लिये समाचार पत्रों को भेजी गयी और सूचना विभाग ने उत्तर दिया है कि हमको प्राप्त ही नहीं हुई, तो क्या आप इस निर्णय पर नहीं आये हैं कि यह सूचना किसी समचार-पत्र में नहीं छपी ? और जब नहीं छपी तो खुली प्रतियोगिता नहीं हुई ? ऐसी हालत में क्या यह उचित नहीं होगा कि जो अनुबन्ध किया गया है उसको कैंसिल कर दिया जाय और उसकी पूरी जांच की जाय ?

श्री राज बिहारी सिंह—

यह बात सही है कि किसी समाचार-पत्र में विज्ञप्ति नहीं निकली, इसकी सूचना है । चूंकि अनुबन्ध हो चुका है और वह काम में लाया गया और उसका कैंसिल करना मुश्किल है तो इसकी जांच करायी जा सकती है कि किसकी गलती से ऐसा हुआ । यह जांच करा लंगा जरूर ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आमतौर पर सिंचाई विभाग में इस तरह की गड़बडियां होती हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि भविष्य में जब भी एग्रीमेंट किया जाय तो उसके पहले अखबार की प्रतिलिपि हाजिर कर दी जाय कि जिस में कि ऐडवर्टिजमेंट छपा हुआ हो ?

श्री राज बिहारी सिंह—

जी हां, ऐसी व्यवस्था की जायगी ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जो यह अनियमित अनुबन्ध हुआ है उसमें जो काम पूरा होने की अवधि थी गुप्ता इंजीनियरिंग बर्क्स ने वह पूरी नहीं की है और वह कैंसिल हो सकता है क्योंकि शर्त पूरी नहीं की गयी ?

श्री राज बिहारी सिंह—

जैसा कि मैंने कहा, इस सारे मामले की जांच करा लूंगा । उसमें जो बातें होंगी वह देख ली जायंगी ।

जनपद रायबरेली में सड़कों के निर्माण की मांग

*4—श्री शिव प्रसाद पान्डिया (जिला रायबरेली)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद राबरेली ब्लाक ऊचाहार व सलोन में किन-किन सड़कों के निर्माण कार्य का सन् 1971 व 1972 में करने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग, रायबरेली द्वारा शासन को स्वीकृति के लिये भेजा गया है और क्या जनपद रायबरेली के ब्लाक सलोन व ऊंचाहार के ऊंचाहार से सलेमपुर भैरों, अरबी से रसूलपुर, बघोल से पिछवार तथा करिहिया से कन्हापुर गांवों को राज्य सड़कों से जोड़ने पर भी विचार है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कोई नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बघोला से गोगनाघाट तक जो सड़क बनायी जा रही है वह किसक आदेश से बनायी जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सवाल यह पूछा गया था कि क्या कोई प्रस्ताव वहां से आया है, उसके लिये कहा गया है कि जी नहीं। वसे तो जो सड़कें 1971-72 के लिये स्वीकृत हैं व बन ही रही हैं। उन पर काम हो रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह तो श्रीमन्, शब्दों का खेल होने लगा। इनसे आप कहें मान्यवर कि शब्दों के हेरफर में एसा उत्तर न दिया करे कि अर्थ का अनर्थ हो जाया करे।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है, आप प्रश्न पूछ लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

प्रश्न यह है कि क्या इन सड़कों को बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ?

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मैं बार-बार खड़ा हुआ, आपने मुझे समय नहीं दिया। आपके इस पक्षपातपूर्ण कार्य के विरोध में मैं 2 मिनट के लिये सदन त्याग करता हूं।

(श्री जगदम्बा प्रसाद सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या यह माननीय अध्यक्ष के लिये पक्षपातपूर्ण आदि शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं कर सकते।

श्री बीर बहादुर सिंह—

माननीय, प्रश्न में यह पूछा गया था कि क्या शासन के पास कोई प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग, रायबरेली, से इन सड़कों के बनाने के लिये प्राप्त हुआ है, उसका उत्तर दिया गया कि जी नहीं। वैसे शासन की ओर से 1971–72 के लिये जो स्वीकृत सड़कें हैं बनाने के लिये, उन पर तो काम हो ही रहा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या बिना सरकार की स्वीकृति के भी कोई सड़क बन सकती है? (व्यवधान) पहले कुछ उत्तर दिया अब कुछ और दे रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

शासन की ओर से कौन-कौन सी सड़कें बन रही हैं?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जगतपुर-ऊंचाहार, ऊंचाहार-सरोली तथा जगतपुर-सलोन मार्ग पर कार्य हो रहा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह सड़कें कब तक पूरी हो जायंगी?

श्री बीर बहादुर सिंह—

1974 तक।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार प्रश्नगत सड़कों को 5वीं योजना में शामिल करने के लिये आदेश करने की कृपा करेगी?

श्री बीर बहादुर सिंह—

माननीय, अभी पांचवीं योजना की रूपरेखा बन रही है। उसमें प्रायरिटी जैसे-जैसे फिक्स होगी उस पर विचार किया जायगा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी, 1971–72 के जो कार्य चल रहे हैं वह कार्य कौन-कौन से हैं और जो नयी मदें ली गयी हैं, रायबरेली जिले में, सड़कों को ऊंचा करना, नयी सड़कों को बनाना, पुल बनाना, सारी योजनाओं को बजट से पढ़कर सुनाएंगे?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

रायबरेली के लोग कम्बल लेते हैं, रजाई लेते हैं, धोती लेते हैं, शराब लेते हैं। उनको सड़कें नहीं चाहिए।

(मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया।)

देवरिया जिले में पुल निर्माण का प्रस्ताव

*5—श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के हाटा ब्लाक के अहिरौली पताया आदि गांवों के लोगों ने दिनांक 15 दिसम्बर, 1972 को वाराणसी कैनाल के शाखा जो अहिरौली बाजार के दक्षिण होकर जाती है उस पर पुल निर्माण हेतु कोई प्रार्थना-पत्र दिया है? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी हां। प्रेमपुर जबहे के मील 10-4-200 पर एक पुल बनवाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है।

श्री बांके लाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाएंगे कि यह जो बुल स्वीकार किया गया है इसका निर्माण कब प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री राजबिहारी सिंह—

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है।

श्री बांके लाल—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि पुल बनाते हेतु पताया और अहरौली और उसके अलावा पचीसों गांवों के लोगों ने जो प्रार्थना-पत्र दिया था, पताया से जो सड़क अहरौली बाजार होकर जाती ह, वहीं पर पुल बनाने की योजना है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

नहरों पर पुल बनाने की योजना होती है, जब कोई प्रार्थना-पत्र मिलता है। अभी एक प्रार्थना-पत्र आया है, विचार होगा अगर उपयुक्त माना जायगा तो उस पर भी देख लिया जायगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की भी जांच करा लेंगे कि जो पुल बनने वाला है इसके अलावा, कुछ दूसरी पर कोई स्थान ह, उससे कई बड़े बड़े गांव जुड़ जाते हैं ,उनको दूर से होकर जाना पड़ता ह, क्या इसी पुल के साथ और पुलों को उस क्षेत्र में देने का विचार कर रहे हैं ?

श्री राजबिहारी सिंह—

यह मान्यवर मैंने निवेदन किया, प्रत्येक नहर के दोनों तरफ जो गांव हैं उन्हीं को पुल दिया जाय यह योजना नहीं है। बहुत से गांवों के बीच में किसानों की आसानी के लिए पुल बनाया जाता है। प्रत्येक दो गांवों के बीच में पुल बनाने की कोई योजना नहीं ह।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि पुल बनाने के लिए शासन की स्वीकृति हो चुकी है। क्या वह बतलाएंगे कि शासन की स्वीकृति के बाद प्रायः कितने दिनों के बाद काम शुरू हो जाता है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

कोई नियम नहीं है कितने दिन में शुरू हो। स्वीकृति के तुरन्त बाद विभाग काम शुरू कर देता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नोटः—तारांकित प्रश्न 5 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

जिला गोण्डा, में सरजू नदी पर पुल निर्माण की मांग

*6—श्री राम जियावन (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा, तहसील तरबगंज, ब्लाक करनैल गंज-मौजा कवनापुर के अन्तर्गत सरजू नदी के घाट पर पुल बनाये जाने की मांग सन् 1967 में शासन से की गई थी? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है और उपरोक्त नदी पर पुल कब तक बन जायगा?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—

जी नहीं। और न ही इस पुल के निर्माण की कोई योजना है।

अतिरिक्त चीफ इन्जीनियर लखनऊ पर भ्रष्टाचार का आरोप

*7—श्री मंजर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का उनको पत्र 18 अप्रैल, 1972 का प्राप्त हुआ है जिसमें अतिरिक्त चीफ इंजीनियर कैनाल विभाग, लखनऊ के खिलाफ करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार के विवरण दिये थे? यदि हां, तो आरोपों की जांच किस से कराई गई और अब तक क्या कार्यवाही की गई?

सिंचाई मंत्री (श्री महमूद अली खां)—

जी हां। श्री पी0 एस0 योग के विरुद्ध पत्र प्राप्त हुआ था। उसमें वर्णित आरोपों पर जांच की गयी। आरोप सही न पाये जाने के कारण उस पर किसी कार्यवाही को आवश्यक नहीं समझी गयी।

सीतापुर, गोबरहिया नाला पर पुल का निर्माण

*8—श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में लहरपुर से तम्बौर जाने वाली सड़क पर 5वें मील के पास गोबरहिया नाला पर जो पुल स्वीकृत है उसे कब तक पूर्ण करने का विचार है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत पुल का निर्माण अप्रैल, 1973 में आरम्भ होने की आशा है। वह कब तक पूर्ण हो सकेगा, अभी बताना सम्भव नहीं है।

सीतापुर बहराइच सड़क पर पुल की मांग

*9—श्री कृष्णकान्त अवस्थी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में सीतापुर से बहराइच जाने वाली सड़क पर कैवानी ककरहिया व भानस नालों पर पुल न होने के कारण बरसात में यातायात बन्द हो जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इन पुलों का निर्माण सन् 1973–74 वित्तीय वर्ष में कराने की कृपा करेगी?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां। पर प्रश्नगत पुलों के निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है।

जिला गोरखपुर में लिंक-रोड की मांग

*10—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की सार्वजनिक निर्माण विभाग के मार्ग कोल्हई से बृजमनगंज व पुरन्दरपुर से फरेंदा कैम्पियरगंज और फरेंदा से धानी और उस्का तक पक्की सड़कों में किन-किन ग्रामों को लिंक-रोड से जोड़ा जायगा ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

इसका निर्णय पांचवीं पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा निश्चित होने के बाद ही सम्भव हो सकेगा।

(दिनांक 14 मार्च, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

पुल निर्माण प्रशिक्षणार्थियों का भत्ता

*1—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार को वर्ष 1971–72 में हिन्दुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के दौरान नदियों पर हैमलटन रीति की स्थायी पुल बनाने की शिक्षा देने हेतु कन्द्र सरकार से करीब 2 1/2 लाख रुपये प्राप्त हुये थे, जिसका ट्रेनिंग कैम्प, मुरादाबाद जनपद में रामगंगा नदी पर खोला गया और ट्रेनिंग कैम्प में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु एक निश्चित भत्ते और पारिश्रमिक पर अनेकों सहायक अभियन्ता तथा अधिदर्शक और सैकड़ों मजदूर लगाये गये, किन्तु उन्हें उनके प्रशिक्षण काल का भत्ता और पारिश्रमिक अब तक नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत प्रशिक्षण मरादाबाद में दिनांक 15–11–71 से 20–1–72 तक दिया गया। इस हेतु केन्द्र से 1,10,000 रुपये प्राप्त हुए। पारिश्रमिक वेतन सब प्रशिक्षणर्थियों को दिया जा चुका है। यात्रा भत्ता 3 को दिया जा चुका है और शेष को अविलम्ब दिये जाने के आदेश दे दिये गये हैं। प्रतिकर भत्ता किसी प्रशिक्षार्थी को अभी तक नहीं दिया गया है क्योंकि उन्होंने निर्धारित बाण्ड नहीं भरे हैं।

राज्य सम्पत्ति विभाग के लिपिकों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

*2—श्री रामगोपाल संड, श्री सर्वसुख सिंह तथा श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग में कितने ऐसे लिपिक एवं अधिकारी हैं जो 5 वर्ष से अधिक समय से इसी विभाग में कार्यरत हैं और स्थानान्तरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

केवल 18 लिपिक। यह जनहित में किया गया है।

बक्सर-उजियार घाट पुल के निर्माण की मांग

*3—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार की सहायता से बलिया और बिहार की सीमा पर नव-निर्मित होने वाले बक्सर उजियार घाट पुल का निर्माण-कार्य ठप कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं तो इस निर्माण की प्रगति 15 दिसम्बर, 1972 तक क्या है और पुल का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायगा तथा यह अवधि पूर्व निर्धारित अवधि से कितनी अधिक होगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इस पुल के निर्माण का उत्तरदायित्व बिहार सरकार पर है। अतः प्रश्नगत सूचना देना सम्भव नहीं है।

परिवहन निगम को डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड की रकम की वापसी

*4—श्री चन्द्र भान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परिवहन निगम के चेयरमैन ने सरकार को साढ़े तीन करोड़ रुपये की डेप्रीसिएशन की रकम निगम को वापस करने के लिये गत वर्ष कई बार लिखा है। यदि हां, तो सरकार ने रुपये की वापसी के लिये क्या कदम उठायें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री देवकी नन्दन विभव)—

परिवहन निगम के डैप्रिसियेशन रिजर्व फंड की रकम को वापिस दिये जाने के अवरोध पर विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 12 अक्तूबर, 72 द्वारा उन्हें 50 लाख रुपये दे दिये गये हैं। फंड की शेष धनराशि के विषय में निगम से पूर्ण औचित्य अपेक्षित है।

तहसील डेरापुर (कानपुर) में नलकूप निर्माण

*5—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

विधान सभा के द्वितीय सत्र के दूसरे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के संबंध में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1972–73 में कानपुर जिले में जो 20 नलकूप लगाये जाने की योजना है चूंकि डेरापुर तहसील में अभी तक कोई नलकूप नहीं है तो क्या वहीं नलकूप लगाने की व्यवस्था विशेष रूप से की जायगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

डेरापुर तहसील में नलकूप निर्माण के संबंध में अभी सर्वेक्षण ही किया जा रहा है। इसके पूर्ण होने पर ही इस क्षेत्र में राजकीय नलकूप लगाये जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

गंगेश्वरी (मुरादाबाद) में राजकीय नलकूप

*6—श्री जितेंद्र पाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले में वर्ष 1971–72 एवं 1972-73 में कितने राजकीय नलकूप स्वीकृत हुये हैं और उनमें से गंगेश्वरी क्षेत्र में कितने नलकूप लगाये गये है जबकि यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में उचित कार्यवाही कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

श्री महमूद अली खां—

जिला मुरादाबाद में वर्ष 1971–72 में 26 नलकूप लगाये गये। 1972–73 में 25 नलकूपों का लक्ष्य है। इसमें से गंगेशवरी क्षेत्र में एक नलकूप ग्राम उम्मारी में लगाया गया है। जिले में नलकूप लगाने के स्थान का चयन जिला स्थल चयन समिति द्वारा ही जिला सिंचाई सलाहकार समिति के परामर्श से किया जाता है।

मुरादाबाद में संगणकों में हरिजन कोटा

*7—श्री जितेंद्र पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 10 वर्षों में मुरादाबाद में कितने मान-चित्रकों को संगणक बनाया गया है और उनमें अनसूचित जाति के कितने सदस्य हैं ? यदि नहीं, तो अनुसूचित जाति के सदस्यों को 18 प्रतिशत संरक्षण न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री महमूद अली खां—

सिंचाई विभाग में पिछले 10 वर्षों में मुरादाबाद में 3 मानचित्रकारों को संगणक बनाया गया जिनमें से अनुसूचित जाति का कोई सदस्य नहीं है। 18 प्रतिशत आरक्षण के आदेश सीधी भर्ती पर लागू थे । संगणक के पद स्थायी मानचित्रकारों को पदोन्नति करके भरे जाते हैं ।

चेयरमैन, नगरपालिका प्रतापगढ़ द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा

*8—श्री रामकिंकर, (जिला प्रतापगढ़) श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद, श्री उदयनाथ (जिला वाराणसी) तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका प्रतापगढ़ के चेयरमैन ने इलाहाबाद-फजाबाद रोड पर शहर के अन्दर सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करके दीवालें खड़ी कर के लोहे के खम्भे गाड़ दिये और बाग लगा दिया है फलस्वरूप जीप दुर्घटनायें आदि हुई ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत अनधिकृत कब्जा तो किया गया है परन्तु लोहे के खम्भे नहीं गाड़े गये हैं और न ही उसके कारण किसी जीप दुर्घटना की सूचना मिली है । अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

*9—श्री अमरनाथ दुबे, श्री विश्वनाथ कपूर, श्री बंशीधर पांडेय तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

श्री विशम्भर दयाल अग्रवाल, अधीक्षक अभियन्ता, सिंचाई (नहर), तृतीय मण्डल आगरा का निलम्बन, स्थानान्तरण तथा वापसी

*10—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि दिनांक 11 अगस्त, 1972 को श्री विशम्भर दयाल अग्रवाल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई (नहर) विभाग, तृतीय मंडल, आगरा को निलम्बित किया गया था और लगभग डेढ़ माह उपरान्त उन्हें आई0 एम0 पी0, गोरखपुर के लिये स्थानान्तरित किया था ? यदि हां, तो निलम्बन और स्थानान्तरण के कारण क्या थे ?

श्री महमूद अली खां—

श्री विशम्भर दयाल को अगस्त, 1972 में आगरा में बाढ़ संबंधी सूचना एकत्र करके शीघ्र शासन को न भेजने के आरोप में निलम्बित किया गया था । उनके द्वारा प्रत्यावेदन देने पर उन्हें निलम्बन से मुक्त करके गोरखपुर में अनुसंधान एवं नियोजन मंडल में तैनात किया गया ।

*11—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या यह भी सच है कि उपरोक्त अधीक्षण अभियंता के गोरखपुर के स्थानान्तरण आदेशों को निरस्त करके आई० एम० पी० अलीगढ़ के लिये स्थानान्तरण किया गया किन्तु एक माह की अल्प अवधि के उपरान्त ही प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की विपरीत लिखित आख्या तथा टिप्पणी के बावजूद भी उन्हें मुख्य मंत्री के आदेशों के आधार पर पुनः आगरा के लिये स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं तथा आगरा मंडल में ही पुनः भेजे जाने के आधार क्या हैं ?

श्री महमूद अली खां—

ऐसा जनहित में किया गया ।

अधिशासी अभियन्ता नलकूप प्रखण्ड, बलिया के लापता रहने की शिकायत

*12—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियंता, नलकूप प्रखंड, बलिया 15 जुलाई से 15 अगस्त, 1972 तक बिना छुट्टी बलिया से लापता थे ? क्या इनके विरुद्ध टेक्नीकल सेल (सिंचाई) द्वारा जांच हो रही है ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं ।

टेक्नीकल आडिट सेल ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी है ।

रौनाही-ड्योढ़ी सड़क (फैजाबाद) का निर्माण

*13—श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिला में सोहावल क्षेत्र में रौनाही से ड्योढी तक सड़क पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों और क्या यह सड़क फैजाबाद-लखनऊ रोड से निकल रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

माननीय विधायकों के सुझाव के अनुसार पूर्व स्वीकृत संरेखण के बजाय प्रश्नगत सड़क के निर्माण का निर्णय हाल ही में हुआ है और आशा है कि इसका निर्माण-कार्य शीघ्र आरम्भ हो जायेगा। यह सड़क फैजाबाद-लखनऊ रोड से निकलती है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्रमिक संघ द्वारा भूख हड़ताल

*14—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ के कार्यकर्ताओं ने संघ द्वारा प्रेषित मांगों पर संतोषजनक कार्यवाही न होने के विरोध में 15 जनवरी से 23 जनवरी, 1973 तक क्रमिक भूख हड़ताल किया था जिसके फलस्वरूप दिनांक 17 जनवरी को संघ के प्रतिनिधियों तथा उप मुख्य अभियंताओं के बीच वार्ता भी हुई थी ? यदि हां, तो इस वार्ता में संघ द्वारा प्रेषित किन मांगों को उप मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकार किया गया और किन मांगों को शासन को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विधायक निवासों का विद्युत चार्ज तथा किराया

*15—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 71–72 तथा 1972–73 में विधायक निवासों में विद्युत प्रकाश पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ है और क्या विद्युत चार्ज विधायकों से वसूल करने का विचार सरकार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों और इस प्रकार सरकार को कितनी हानि प्रति वर्ष हो रही है ?

श्री महमूद अली खां—

	रु०
1971–72	.. 3,66,640-42
1972–73	.. 4,45,713-21

उत्तर प्रदेश राज्य विभाग मंडल के अधिकारियों, मंत्रियों, उप मंत्रियों, सभा सचिवों और सदस्यों (के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 1969 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7,1979) के अनुसार 16–4–69 से विद्युत व्यय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । अतः इस व्यय को विधायकों से वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*16—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विधायक निवास राष्ट्रपति शासन 1968–69 की अवधि में किराये पर उठाये गये थे ? यदि हां, तो कितने महीने तक और उससे कुल कितना धन किराये के रूप में वसूल हुआ ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां,

8 माह तक किराये पर उठाये गये थे । रुपये 3,01,790 वसूल हुआ ।

विकास खण्ड जसपुरा, (बांदा) में नलकूप की मांग

*17—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1972–73 में विकास खंड जसपुरा, जिला बांदा में किस-किस स्थान पर नलकूप लगाये और इस अवधि में कितने नलकूप लगाये जाने की योजना थी तथा यदि एक भी नलकूप नहीं लगाया गया है तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

1972-73 में जिला बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं था। शेष प्रश्न उठता ।

*18—सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

[5व मंगलवार के लिये प्र0सं0–39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर जनपद में सड़क निर्माण की स्वीकृति

*19—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जनपद के विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़क को सन् 1971–72 व 1972–73 के वित्तीय वर्ष में बेकारी योजना में ली गई तथा उसमें कौन-कौन सी सड़कें निर्वाचन क्षेत्र 194, फरेंदा, गोरखपुर में ली गई ? यदि इस निर्वाचन क्षेत्र में कोई सड़क नहीं ली गई तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

1971–72 में बेरोजगारी योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किसी सड़क का निर्माण स्वीकृत नहीं किया गया है । 1972–73 में इस योजना के अन्तर्गत गोरखपुर-जनपद के विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कों का निर्माण स्वीकृत किया गया:—

1—सहजनवा-बाखिरा मार्ग	5.0 किलोमीटर
2—राजपुर-इन्द्रपुर मार्ग	5.0 किलोमीटर
3—पीपीगंज-अकटहवा मार्ग	4.4 किलोमीटर
4—बादशाहपुर-लक्ष्मीपुर मार्ग	3.0 किलोमीटर
5—परशुरामपुर-लक्ष्मीनगर मार्ग	3.0 किलोमीटर
6—बड़हलगंज-मैसोली मार्ग	1.0 किलोमीटर
7—चिवटहा-निचलौन मार्ग	4.0 किलोमीटर

निर्वाचन क्षेत्र 194 फरेंदा-गोरखपुर में सीमित धनराशि होने के कारण उक्त योजना के अन्तर्गत कोई भी मार्ग स्वीकृत नहीं किया जा सका ।

*20—श्री रामधारी शास्त्री—

[9वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*21—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[9वें बुधवार के लिये स्थगित]

नानक सागर बांध टूटने में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*22—श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 8 व 9 सितम्बर, 1967 की रात्रि को नानक सागर बांध टूटने के कारणों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को कब प्राप्त हुई ? जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार कौन-कौन अधिकारी तथा कर्मचारी दोषी पाये गये ? दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध किस तरह की कार्यवाही की गई ?

श्री महमूद अली खां—

समिति की रिपोर्ट शासन को जनवरी, 1969 में प्राप्त हुई थी । दोषी समझे गये अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम की सूची संलग्न है । दोषी पाए गए राजपत्रित अधिकारियों को दंड देने का मामला अभी शासन के विचाराधीन है। अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रमुख अभियंता द्वारा की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 655 पर)

लखनऊ में चपरासियों के सरकारी क्वार्टर

*23—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद) तथा श्री रामबिलास पांडेय—

क्या यह सही है कि सरकार ने चपरासियों के लिये लखनऊ में नये क्वार्टर्स बनवाये हैं ? यदि हां, तो उन्हें न देकर दूसरे लोगों को एलाट किया गया है तथा उसमें बहुत से अनधिकृत लोग रहते हैं? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री महमूद अली खां—

सन् 1960 के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये कोई क्वार्टर नहीं बने ।

*24—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[प्रदेशीय सरकार से असबद्ध होने के कारण निरस्त]

सिविल ओवरसियरों के स्थान पर मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ओवरसियरों की नियुक्ति

*25—श्री जयराम वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिविल ओवरसियरों के अभाव के कारण उनके स्थान पर मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ओवरसियर की नियुक्ति शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका निर्णय कब तक हो जाने की आशा है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इस मामले में निर्णय हो गया है और शासनादेश जारी हो चुके हैं ।

*26—श्री रामनिहोर राय—

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

*27—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

(7वें मंगलवार के लिये प्रश्न सं0 18 के अन्तर्गत स्थगित।)

परिवहन विभाग (लखनऊ) के अधिकारियों का स्थानान्तरण

*28—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परिवहन विभाग के लखनऊ सम्भाग आर0 टी0 ओ0, जी0 टी0 ओ0, ए0आर0टी0ओ0, पी0टी0ओ0 कितने ऐसे हैं जो एक ही जिले में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और एक ही जिले में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य करने के कारण क्या हैं ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

लखनऊ सम्भाग में एक सम्भागीय परिवहन अधिकारी व एक माल-कर अधिकारी, 3 वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं। इसमें से सम्भागीय परिवहन अधिकारी को गत सामान्य स्थानान्तरण के समय तीन वर्ष पूरे नहीं हुए थे, तथा माल-कर अधिकारी को, उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों को देखते हुए, स्थानान्तरित नहीं किया गया था।

*29–30—श्रीमती मसाली देवी—

[9वें बुधवार के लिय प्रश्न सं0 16-17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*31—श्री के0 एस0 मेहरिया—

[9वें बुधवार के लिये स्थगित।]

अतारांकित प्रश्न

मऊ-सुल्तानीपुर सड़क (आजमगढ़) के निर्माण की मांग

1—श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि आजमगढ़ जिले में मऊ से सुल्तानीपुर आने वाली सड़क के निर्माण का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जायगा ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं ।

मिर्जापुर में लिफ्ट केनाल योजना

2—श्री उमा नाथ सिंह (जिला जौनपुर) तथा श्री राम सागर—(जिला ौनपुर)

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मिर्जापुर के पहाड़ी इलाकों में सिंचाई के जल की आपूर्ति के लिये सौन लिफ्ट कैनाल योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना का शुभारम्भ कब होगा ? इसकी क्या लागत होगी और किन-किन क्षेत्रों की सिंचाई होगी ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। योजना की स्वीकृति के उपरान्त ही यह बताया जा सकेगा कि इस पर कब निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायगा। योजना की लागत लगभग 17 करोड़ रुपए अनुमानित है और इससे मिर्जापुर जिले के पठारी क्षेत्र में 2.73 लाख एकड़ भूमि को सिंचन सुविधा उपलब्ध होने की आशा है ।

कनहर नदी पर पुल की मांग

3—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री राम निहोर राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बिन्दमगंज कौन सड़क के बीच पान्डु नदी तथा कोटा कोन के बीच कनहर नदी पर पुल निर्माण की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं ।

महमूदाबाद-तम्बौर सड़क (सीतापुर) का निर्माण

*4—श्री कृष्णकान्त अवस्थी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में महमूदाबाद से तम्बौर जाने वाली सड़क सा0नि0वि0 द्वारा तथा त्वरित योजना द्वारा पक्की बन रही है, वह केवल धानागांव से चन्दौसी घाट तक 8 किलोमीटर कच्ची रह जाती है ? यदि हां, तो क्या इस शेष भाग को सरकार इसी वित्तीय वर्ष में पक्का करने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां ।

जी नहीं ।

रेउसा चहलारी घाट मार्ग

5—श्री कृष्णाकान्त अवस्थी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर से बहराइच जाने वाली सड़क रेउसा तक पक्की बनी हुई है, शेष रेउसा से चहलारी घाट तक सा० नि० वि० द्वारा स्वीकृत भी हो चुकी है ? यदि हां, तो इसके कब तक पक्की बन जाने की सम्भावना है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

रेउसा से चहलारी घाट मार्ग का निर्माण बेरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था परन्तु कुछ प्राविधिक कठिनाइयों के कारण इस मार्ग के स्थान पर राम कोर्ट बजीर नगर मार्ग का निर्माण किया जा रहा।

श्री विद्यार्थी राय ठेकेदार (देवरिया) द्वारा भष्टाचार की शिकायत

6—श्री राम नगीना मिश्र (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री विद्यार्थी राय ठेकेदार ग्राम रोआरी पत्रालय सिगहा, जिला देवरिया ने एक भ्रष्टचार सम्बन्धी गम्भीर आरोप के जांच हेतु सितम्बर, 1971 में मुख्य मन्त्री तथा सिंचाई मन्त्री को एक आवेदन-पत्र दिया था और उसकी जांच मार्च, 1972 में सरकार द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार को जानकारी है कि स्थानीय विधायक ने भी इसकी जांच हेतु आवेदन पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री महमूब अली खां—

जी हां। 1972 में एक पत्र सिंचाई मन्त्री जी को प्राप्त हुआ था जिसकी जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक द्वारा जनवरी, 1972 में कराई गई थी। मुख्य प्राविधिक परीक्षक का जांच प्रतिवेदन शासन को प्राप्त हो गया है और उस पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

गोरखपुर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिदर्शक

7—श्री मती प्यारी देवी गुप्ता—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिदर्शकों को एक स्थान पर कितने समय तक रखने का प्राविधान है, एवं गोरखपुर जिले में विभिन्न अधिदर्शक एक ही स्थान पर कितने समय से है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

खण्ड में सामान्यतया 3 वर्ष और बल में 6 वर्ष।

*सूची संलग्न है।

गोरखपुर जिले में लिंक रोड की मांग

8—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी गोरखपुर जिले के कोल्हई लोटन मार्ग पर किन-किन ग्रामों कोलिक रोड से जोड़ रही है ?

---

†छापी नही गयी।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उन्युड नहर (अल्मोड़ा) की मरम्मत

9—श्री हरीसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंग कि जनपद अल्मोड़ा की पट्टी बिसौत में सिंचाई की कुन्युड़ा गूल का कार्य विभाग द्वारा प्रारम्भ हुआ? यदि हां, तो कब से और अब तक गूल निर्माण का कार्य कितना हो गया है तथा कितनी गूल बननी बाकी है और शेष कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

श्री महमूद अली खां—

कुन्युड़ नामक कोई गूल नहीं है जिसका निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। और प्रश्नकर्ता का उन्युडा नामक नहर से तात्पर्य है तो वर्ष 1970-71 तथा गत वर्षा के मौसम में अतिवृष्टि से भूस्खालन हो जाने के कारण यह नहर कई स्थान पर टूट गयी। इस नहर की कुल लम्बाई 6 मील 4 फर्लांग है, जिसमें हैड से मील 2 तक की मरम्मत की जा चुकी है। मील 2 से 3 की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जिसके इस माह के अन्त तक पूरा होने की आशा है। मील 30 के नीचे कार्य हेतु निविदा आमंत्रित किये गये हैं।

अल्मोड़ा बीनसर मार्ग के निर्माण की मांग

10—श्री हरीसिंह विष्ट—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा से बीनसर तक (अल्मोड़ा नारायण तिवाड़ी देवान, जोगी दल्ला कभड़खान होते) का मार्ग जो पर्यटन के लिए परमावश्यक है कब तक बन जायगी?

श्री लक्ष्मी .शंकर यादव—

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण अभी स्वीकृत नहीं है। अतः यह मार्ग कब तक बन जायगा इसका प्रश्न नहीं उठता।

11—श्री बसन्त लाल शर्मा तथा श्री रामबिलास पाण्डेय—

[पुनर्विचार पर अस्वीकृत]

हबर्टपुर विकासनगर मार्ग (देहरादून) का निर्माण

12—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें इसकी सूचना है कि मा0 मुख्य मन्त्री ने अपनी 19—21 अगस्त, 1972 की देहरादून में निवास अवधि के बीच विकास नगर (जिला देहरादून) में हबर्टपुर से बिकासनगर तक के मार्ग की जो बिल्कुल टूटा हुआ है, तुरन्त बनाये जाने की स्वीकृति दी थी? यदि हां, तो अब तक इस विषय में क्या कार्यवाही की गई?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं। वस्तु स्थिति यह है कि हर्बर्टपुर से कालसी गेट तक मार्ग के, जिस का प्रश्नगत मार्ग एक भाग है, पुनर्निर्माण तथा सुधार के लिए आगामी वित्तीय वर्ष की नई मांगों की अनुसूची द्वारा विधायी स्वीकृत प्राप्त की जा रही है।

13—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[9 वें बुधवार के लिये स्थगित]

14—श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)—

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

पी० डब्ल्यू० डी० (सीतापुर) के बेलदार व मेटों का भुगतान

15—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर के पी० डब्लू० डी० के लगभग 120 बेलदार व मेंट माह जुलाई एवं अगस्त 1972 की मजदूरी की बकाया न पाने के कारण 30 सितम्बर, 1972 को अधिशासी अभियन्ता सा० नि० वि०, प्रान्तीय वेड, सीतापुर के बंगले पर बैठ कर आन्दोलनात्मक रुख अख्तियार किया था ? यदि हां, तो मजदूरों की मजदूरी क्यों रोकी गई और कितने दिन का भुगतान कर दिया गया है तथा अभी कितना बकाया है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां ।

मजदूरी रोकी नही गई बल्कि उसके भुगतान में बिलम्ब हो गया था ।

11 कर्मचारियों के न मिलने के कारण उनका 133.87 रु० छोड़ कर बाकी को पूरे दिनों का भुगतान कर दिया गया है ।

16-17—श्री भरत सिंह चौहान—

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

18—श्री अनन्त राम जायसवाल—

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

19—श्री लालसा—

[9वें बुधवार के लिये स्थगित]

लखनऊ-गोंडा मार्ग पर सरयू नदी के पुल पर व्यय तथा पुल से आय

20—श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ गोंडा रोड पर जनपद गोन्डा के अन्तर्गत सरयू नदी पर नवनिर्मित पुल पर वर्ष 1970-71, 1971-72, 1972-73 प्रति वर्ष कर की वसूली से कितनी आमदनी हुई और उस पुल पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन इत्यादि पर प्रति वर्ष कितना व्यय हुआ ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

वांछित सूचना निम्नवत् है:—

वर्ष	आय	कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय ।
	रु०	रु०
1970-71	27,985	11,429
1971-72	24,074	12,707
1972-73 .. .. (फरवरी, 1973 तक)	17,894	14,948

विधान सभा के रिपोर्टरों से सम्बन्धित अ्रसरकारी विधेयक सदन में उपस्थित करने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आपने 26 तारीख को अपने विभाग से सम्बन्धित लिपिकों और रिपोर्टसं के विषय में एक नानआफिशियल बिल रखने के लिये समय निश्चित किया था । मगर उस दिन अवकाश हो गया । मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं । कांउसिल में भी अनुच्छेद 183(3) के अन्तर्गत विधान परिषद् की समस्या उठायी गयी, वहां के सभापति महोदय ने तिथि निश्चित की है । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उसके लिये समय दें जिससे नानआफिशल बिल रखा जा सके ।

श्री अध्यक्ष---

दो बिल हमारे पास आये थे, 26 तारीख को रखना था, पर 26 तारीख को कार्य मंत्रणा ब्र येगा ने छुट्टी दे दी । मैंने यह किया है । उसके लिये कार्यमंत्रणा समिति में विचार आमिति और कोई तारीख मुकर्रर करेंगे ।

श्री राम गोपाल संड---

आपसे प्रार्थना है कि उसको अप्रैल के पहले सप्ताह में जल्दी से जल्दी किसी दिन निश्चित कर दें ।

श्री अध्यक्ष---

वही करेंगे ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

अब, श्री हरिवंश सहाय जी का है– इलाहाबाद में समाजवादी युवजन सभा के अखिल भारतीय मंत्री के पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से छात्रों में असंतोष । इसको मैं ने अस्वीकृत किया है । आप इसमें अल्प सूचित तारांकित प्रश्न पूछ लें । बजट पर विवाद चलेगा उसमें भी जिक्र कर सकते हैं ।

दूसरा सर्वश्री राम कुमार दीक्षित, उपेन्द्र नाथ दीक्षित, सुरेन्द्र विक्रम तथा बंशीधर पांडेय का है । यह कानपुर जनपद के अन्तर्गत कल्याणपुर में पुलिस के ढिलाई के फलस्वरूप गश्त के सिपाहियों के राइफल छीन लेने से पुलिस अधिकारी द्वारा चारों ओर जुल्म के सम्बन्ध में है । इसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)---

पुलिस के लोग जबरदस्ती लोगों के घरों में घुस कर डकैती डालते हैं....

श्री अध्यक्ष---

काम रोको प्रस्ताव इसमें नहीं लाया जा सकता ।

श्री राम कुमार दीक्षित---

वक्तव्य तो आप दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष---

तीसरा सर्वश्री अब्दुल सलाम शाह, बंशीधर पांडेय तथा सुरेन्द्र विक्रम सिंह का है। फर्रुखाबाद जिले में बीडी के कर्मचारियों को शासन द्वारा की गई बढ़ोत्तरी को मालिकान द्वारा न देने से मजदूरों में असंतोष । इसे मैंने अस्वीकृत कर दिया है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

बड़ा आन्दोलन हो रहा है ।

श्री अब्दुल सलाम शाह (जिला फर्रुखाबाद)---

ये बीड़ी मजदूर भूखों मर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न पूछ लीजिये इसमें ।

चौथा सर्वश्री शम्भू नाथ चौधरी, राम प्रसाद देशमुख, शफीक अहमद खां, तथा मोहम्मद असरार अहमद का है । राशन की सस्ते गल्ले की दूकानों के सम्बन्ध में है । इसे मने अस्वीकार कर दिया है ।

कतिपय विषय

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)---

मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

उसके बारे में माननीय सदस्य से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

श्री पारस नाथ सिंह---

792 एकड़ जमीन हरिजनों के नाम पर हड़प ली गयी है । उनके साथ अन्याय किया जा रहा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मैंने आपको एक पत्र लिखा था । आपने जो व्यवस्था दी थी जनहित वाले प्रश्न पर उस पर सदन आज चर्चा करना चाहता है ।

श्री अध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । मेरे कमरे में आकर बातचीत कर लीजियेगा । मैंने फैसला दे दिया है । उस पर बहस नहीं हो सकती ।

1973-74 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष---

अब वित्तीय वर्ष 1973-74 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी । नेता विरोधी दल इस पर अपना भाषण शुरू करेंगे ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

मेरी तरफ से चौधरी चरण सिंह बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

चौधरी साहब बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कितना समय लेंगे ।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)---

तीन घंटे लूंगा ।

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि माननीय नेता विरोधी दल को 3 घंटे नहीं सवा तीन घंटे दिये जावें लेकिन उसी अनुपात से हम अन्य दलों के नेताओं को भी कम से कम डेढ़-डेढ़ घंटे का समय मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

नहीं डेढ़ घंटा तो नहीं, लेकिन समय बाद में आपके लिये निश्चित हो जावेगा । माननीय नेता विरोधो दल के लिये तो कोई समय निश्चित नहीं है लेकिन मैंने यों ही थोडी सी कटौती कर दी और अब उनके लिये तीन घंटे काफी है ।

श्री अनन्त राम जायसवाल---

हम तो उनके समय में बढ़ोत्तरी चाहते हैं लेकिन हम तो अपना हक मांगते हैं ।

*श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि मैं ज्यादा समय ले लेता हूं लेकिन वह अपने माननीय मित्रों की उदारता के बल पर ही ले लेता हूं। लेकिन जैसा कि आपने फरमाया कि नियमों में नेता विरोधी दल के लिये कोई सीमा ही नहीं है और पहली बार भी मैं पांच घंटे बोल चुका हूं । लेकिन अब जैसा मैंने अर्ज किया है, अपना भाषण अब 3 घंटे से पहले ही खत्म करने की कोशिश करूंगा ।

मेरी कठिनाई, श्रीमन्, यह है कि किधर से शुरू किया जाय। मैंने तो अपने दोस्तों से यह कहा था और बात कुछ निजी सी हो जाती है कि अब की बार बजट में भाग नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं बोल भी चुका हूं और इसके अलावा स्थिति अपने प्रदेश की इतनी बिगड़ गयी है कि किधर से शुरू किया जाय और किधर खत्म किया जाय यह समझ में नहीं आता है । परमात्मा, ने, कुदरत ने एक नियम बना रखा है कि जब किसी शख्स की तकलीफ बहुत बढ़ जाती है, दर्द बहुत बढ़ जाता है तो उसको कुदरत बेहोश कर देती है, या जो बहुत ऊंचा आदमी हो जाता है तो वह बोलना बन्द कर देता है । तो चाहे उधर बैठे हुये माननीय मित्र महसूस करते हो या न करते हों लेकिन देश और प्रदेश की स्थिति उससे भी ज्यादा नाकाबिले बयान है । किसी गांव में चले जाइये, किसी महकमें की बात ले लीजिये, किसी बार एसोसियेशन में चले जाइये, किसी बस में बैठकर सफर कर लीजिये, किसी-टी-स्टाल में, किसी कैफेटेरिया में, या कहीं भी जहां 5 आदमी बैठें हों चले जाइये आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा जो इस अपने प्रदेश की व्यवस्था, दुर्व्यवस्था पर अफसोस जाहिर करता हुआ न पाया जाय । मैं नहीं समझता कि दुनिया में किसी देश और प्रदेश की वह स्थिति हुई होगी जो आज हमारे प्रदेश और देश की है । तो ऐसी सूरत मैंने जो स्थिति है उसका बहुत थोड़ा सा अंश भी पूरी तरह से बयान नहीं कर सकता । मैं जैसा पिछली बार अर्ज किया था कि एक दिन के अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, गलतियां, बेइन्साफी जो हो रही है उसका बयान एक दिन के इन सब चीजों का एक दिन में मैं भी करना चाहूं तो मैं एक दिन के भ्रष्टाचार और गलतियां का बयान नहीं कर सकता । लेकिन मजबूरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चरण सिंह]
है, दोस्तों की मैजारिटी है, जिस तरह से वह चलाना चाहते हैं वह चलायेंगे ही, हमारी आवाज का कोई असर नहीं है, यह मैं जानता हूं लेकिन अपना जो कर्तव्य है उसको पालन करने के हेतु ही मैं जो कुछ यहां कहूंगा वह कहूंगा, बाकी मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है कि चाहे कितनी भी सही बात मैं कहूं अगर 50 गलत होंगी तो 5 सही भी हो सकती हैं लेकिन उनका भी असर माननीय मित्रों पर होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, अब इस बजट में 76 करोड पये का डेफीसिट है। यह घाटा कैसे पूरा होगा इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ इतना जिक्र है कि जो बाकी पड़ा है, गवर्नमेंट का ख्याल है कि उसमें से 20 करोड़ रुपया वसूल हो जाय। मुमकिन है इस साल वसूल हो जाय लेकिन पहली बात तो यह है कि बाकी कितना है उसका जिक्र नहीं है, कम से कम माननीय वित्त मंत्री जी का जो भाषण हुआ है उसमें होना चाहिये था कि बाकी आज कितना है, उससे पहले साल कितना था और उसमें आप 10 करोड़ इस साल वसूल करना चाहते हैं यह चीजें आनी चाहिये थीं। यह वसूली अब तक क्यों नहीं की गयी और मान लो वसूल भी आपने कर लिया इस साल तो भी यह मुस्तकिल आमदनी तो हुई नहीं। यह खर्च तो मुस्तकिल है, कम होने की उम्मीद नहीं है, बल्कि हर साल बढ़ता ही जायगा। 10 करोड़ मान लिया आपने एक साल में वसूल भी कर लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी 66 करोड़ का क्या होगा उसे आप कहां से लायेंगे? यह जो घाटा से है उसका मुख्य कारण है पे कमीशन की सिफारिशों को पूर्णतया मान लेना। अध्यक्ष महोदय, उसकी सिफारिशों के हिसाब से 70 करोड़ रुपया का इजाफा होता था लेकिन गवर्नमेंट तो एक कदम और आगे बढ़ गई और वह सिफारिशों को अमल करने के बाद साढ़े 74 करोड़ रुपये हो गया।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा नाजुक मामला है। इसके अर्ज करने से पहले मैं इस सिलसिले में अपनी राय जाहिर करना चाहता हूं और वह यह है कि यह होशियारी की गई है कि जितने राज्य कर्मचारी हैं वे खुश हो जायं ताकि अगले इलेक्शन में आपको मदद कर सकें। मुझे दोस्त माफ करें, यदि मैं ऐसा कहूं और यह चार्ज लगाऊं कि यह सरकार राज्य कर्मचारियों से मदद लेने में कभी गुरेज नहीं करती है। उन्हें खुश करने की यह एक चीज है। दूसरी तरफ जनता नाराज न हो, इसलिये कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। वह तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन के बाद। कहा जाता है कि अक्तूबर में इलेक्शन करने का इरादा है। एक साहब ने कहा कि सेन्सस के बाद कांस्टीट्यूशन में डीलिमिटशन न हो जाय तब तक इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन यह बात सही मालूम नहीं होती, वह हो सकता है। इसमें भावना यही है कि राज्य कर्मचारी खुश हो जायं और जनता नाराज न हो, हो सकता है मेरी राय गलत हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि हर आदमी को लिविंग बेजेज मिलनी चाहिये और इसके हिसाब से आप 165 रुपये की रकम पर पहुंचे है। आपने उसमें लेबर कमीशन का जिक्र किया है, मडिकल कान्फरेंस का जिक्र किया है और कोलेरीज का जिक्र किया है कि एक व्यक्ति को स्वस्थ्य रहन के लिय आपने खान-पीने के लिय कम से कम कितनी कोलेरीज होनी चाहिये। इस सब का हिसाब लगाकर 165 रुपये पर आप पहुंच हैं और 14 रुपये ऊपर से महंगाई भत्ता। लेकिन जिन आंकड़ों पर आप आज 73–74 में पहुंचे हैं वे आंकड़े तो सन् 1970–71 के हैं। पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जिन आंकड़ों का जिक्र किया है वह 1970–71 के प्राइसेज के आधार पर हैं। अगर आज के आंकड़े देखे जायं तो यह 165 रुपय और 14 रुपये नाकाफी हैं। 71–72 में प्राइसेज बढ़े हैं और 72–73 में तो बहुत तेजी से बढ़े हैं। लिहाजा जब आपने एक उसूल मान लिया है कि भावों में वृद्धि के साथ-साथ आप भी राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि करेंगे और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के आधार पर ही उसमें वृद्धि करते रहेंगे, तो आपको देना पड़ेगा। मान

लिया कल कोई स्ट्राइक करता है तो आपके पास कोई रुकावट नहीं है कि न द । फलस्वरूप यह 74 करोड़ का घाटा और बढ़ जायेगा । आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा । यदि राज्य कर्मचारी कल यह कहता है कि जो आपने दिया है वह 70–71 के प्राइस इन्डेक्स के हिसाब से दिया है या भावों के अनुसार दिया है और तब से आज 73–74 में भावों में काफी वृद्धि हो गई है, तब आपके पास क्या दलील रह जायेगी और तब आपके पास क्या लक्ष्य या मौरेल आब्स्ट्रक्शन होगा ? उस स्थिति में हम कहां पहुंच जायेंगे ? कोई सीमा ही नहीं रह गई । यह ठीक नहीं है । मैं चाहता हूं कि हर आदमी की लिविंग वेजेज बढ़ा दी जाय लेकिन प्रश्न यह है कि जहां सूबे के अन्दर त्रिपाठी जी, आपने एक जगह अपनी स्पीच में कहा भी है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत हमारे सूबे का है जहां लोगों को खाने को नहीं मिलता है । 1963–64 के नेशनल सेम्पुल सर्वे के मुताबिक सारे हिन्दुस्तान में 40–50 प्रतिशत आदमियों को दोनों वक्त भर पेट खाने को नहीं मिलता है । यह तो पहले की बातें हुई । अब तो पहले से कीमतें और भी बढ़ गयी हैं और मेरा अनुमान है कि आज कम से कम 50 प्रतिशत आदमियों को दोनों वक्त भरपेट खाना खाने को नहीं मिलता है । हमारे सूबे का हाल औसतन खराब है, फिर भी मैं 50 प्रतिशत ही मानता हूं ।

अभी आपने 6 लाख सरकारी कर्मचारियों को लिविंग बेज दे दिया लेकिन इस प्रदेश में जो 9 करोड़ लोग रह रहे हैं उनके वेज का क्या होगा ? आप लोगों पर टैक्स लगा देते हैं, बजट में आर्डर देकर, कानून बना कर लेकिन हम ट्रस्टी है 9 करोड़ आदमियों के, उनके लिये क्या प्रबन्ध है, उनके लिये क्या सोचा जा रहा है ? कुछ नहीं, इस बजट में उनके लिये कुछ नहीं सोचा गया है । सरकार का दृष्टिकोण केवल शहर में रहने वालों की तरफ है क्योंकि शहर के रहने वाले पढ़े–लिखे लोग हैं, प्रोपेगंडा कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं और यही नहीं कि हमारे यहां ही यह बात हो, सारे हिन्दुस्तान में अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है , प्राइस बढ़ती जा रही है और देश की आर्थिक अवस्था खराब होती जा रही है । पहले जो कुछ हुआ उससे तो देश ने सबक सीख लिया है । आपसे मैं कहना चाहता हूं कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो राज्य कर्मचारियों का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कीमतें बढ़ जायेंगी । बेशक आपने उनकी तनख्वाह बढ़ा दीं लेकिन सारी तनख्वाह व भत्ता इस मंहगाई में जज्ब हो जायेंगी और उनको कुछ फायदा नहीं हो पायेगा । आपको सारी जनता के फायदे की बात सोचनी चाहिये थी लेकिन यह देखकर मुझे तकलीफ हुई कि आपने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है । इसके लिये एक ही हल है कि आप प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दें वरना यह मसला हल होने वाला नहीं है । अगर तनख्वाह और भत्ता बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ती है । कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 1,250 रुपय तक तनख्वाह पाने वालों को ही केवल मंहगाई भत्ता मिलेगा । अब सरकार का कहना है कि जो कम तनख्वाह पाते हैं उनको कम, उनसे ज्यादा तनख्वाह पाने वालों को उनसे ज्यादा और जो उनसे ज्यादा तनख्वाह पाते हैं उनको उनसे भी ज्यादा मिलेगा ।

डी० ए० देने के जो सिद्धांत हैं वह यह कि छोटे राज्य कर्मचारी जिनको कम तनख्वाह मिलती है बेशक उनको धन एलाऊंस मिलना चाहिये । जितने गरीब कर्मचारी हैं जो कम तनख्वाह पाने वाले हैं वे अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च करते हैं । यदि बड़े आदमियों के खान पर खर्चा उनकी आमदनी का 25 प्रतिशत आता है तो गरीब आदमियों को अपनी आमदनी का 80 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है । तो जो लोग कम तनख्वाह पाते हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिये । मैंने अभी वेतन कमीशन की रिपोर्ट तो पढ़ी नहीं है और वह रिपोर्ट न तो अभी हाउस के सामने ही रखी गयी है और सदन में जो माननीय वित्त मंत्री का भाषण हुआ उसमें भी कोई जिक्र नहीं है । पहले भी मैं इस सदन में दो बार जिक्र कर चुका हूं कि यह एनोमली है, यह बिलकुल बेइन्साफी है और अक्ल से बईद बात है कि गरीबों को फायदा कम और बड़े आदमियों को फायदा ज्यादा मिले । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी

[श्री चरण सिंह]

और माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहताहूं कि आखिर यह कौन सा उसूल है, कौन सा सोशलिज्म है ? यह तो आपके उन उसूलों के भी खिलाफ है जिसकी आप अलाप रात दिन लगाते रहते हैं ।

दूसरी बात यह है कि कमीशन ने तो पहले 1,250 रुपये तक तनख्वाह पाने वालों को ही मंहगाई भत्ता देने की बात कही थी लेकिन आपने उनको बढ़ा कर 2,250 रुपये तक पाने वालों के लिये कर दिया है । डेढ़ हजार और दो हजार, सवा दो हजार तक पाने वाले कंचारियों को भी भत्ता मिले, मेरे पास शब्द नहीं हैं कि किस तरह से इस पर मैं अपनी तकलीफ का इजहार करूं, आखिर क्या माने हुआ इसका ? क्या डेढ़ हजार और सवा दो हजार तनख्वाह पाने वाले आदमियों के लिये भाव बढ़ जाने से कोई अन्न की कमी पड़ गयी ?

खाने की कमी है, कपड़े की कमी है, या मकान की कमी है । फिर हम कस्टोडियन होकर यहां बैठे हैं और हर चीज का जवाब हंसकर टाल दिया जायेगा । मैं जानना चाहूंगा कि क्यों इतने बड़े बड़े आफिसर्स को भत्ता देने की जरूरत ? इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर चुका हूं कि कहीं तो लाइन खीचनी होगी । मोटी सी बात है कि जिस कर्मचारी को इस योग्य समझा जाता है कि वह इनकम टैक्स दे सकता है, उसको भत्ता पाने का कोई हक नहीं है । गवर्नमेंट आफ इंडिया 5 हजार रुपये सालाना से ऊपर की आमदनी पर इनकम टैक्स लगाती है । वह चार हजार भी कर तो भी हक बजानिब होगी। एक तरफ तो उस कर्मचारी को इनकम टैक्स देना पड़ता है और दूसरी तरफ आप उसको मंहगाई भत्ता देंगे । एक तरफ तो आप उसको इस लायक समझते हैं कि वह अपना खर्च पूरा नहीं कर सकता है और दूसरी तरफ आप उसको इस लायक समझते हैं कि वह इनकम टैक्स दे । एक हजार, दो हजार तनख्वाह पाने वालों से तो काफी बड़ा टैक्स लिया जायेगा। आखिर इन दोनों व्यूज में क्या हारमोनी है ? लेकिन आपकी गवर्नमेंट है, आपकी मैजारिटी है लेकिन इससे बेहूदा बात और कोई नहीं हो सकती है जो की गई है । एक तरह से जनता के भविष्य को मारगेज करने की बात है ।

जब आज आदमी को खाने को नहीं मिल रहा है और जो आपके रायल होटल और गेडियो हाउस तथा कौंसिलर्स रेजीडेंस हैं, उनके पीछे जाकर क्या किसी ने देखा है कि किस तरह से वहां के लोग रह रहे हैं । न उनके पास खाने को भोजन है, न रहने को मकान है और न पहनने को कपड़ा है, क्या किसी ने देखा है कि उनके पीछे कितनी गरीबी छिपी हुई है, कितना दुख छिपा हुआ है ? आखिर आप लोगों को उनका ख्याल क्यों नहीं है ? आप देश के राज कर्मचारियों को दीजिये लेकिन इन लोगों के लिये आप क्या कर रहे हैं ? आप स्टेट के कमचारियों को मोरगेज कर रहे हैं । इसलिये कि आपकी स्टेट की रेवेन्यू 664 करोड़ रुपये है । 180 करोड़ रुपया स्टेट टैक्सों से वसूल करती है । 146 करोड़ रुपया दूसरे विभागों से प्राप्त होता है जिसको टैक्स नहीं कहा जा सकता है मसलन इर्रीगेशन डिपार्टमेंट से आबपाशी का मूल्य तथा फारेस्ट डिपार्टमेंट से आमदनी प्राप्त होती है । 180 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को टैक्सों से मिलता है और जो इनकम टैक्स से वसूल होता है और फायनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर सेन्ट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को तक्सीम करती है । 149 करोड़ रुपया गवर्नमेंट एड देगी । 180 करोड़ रुपया टैक्सेस से मिलेगा और 146 करोड़ रुपया दूसरे विभागों जैसे इर्रीगेशन और फारेस्ट विभागों से मिलता है । यह 65 करोड़ रुपये के करीब पंहुच जाता है और खर्चा 241 करोड़ गवर्नमेंट इम्पलाइज के इमोल्यूमेंट्स पर होता है और 137 करोड़ रुपया वह जो पहले कर्जे की मय सूद के अदायगी हो रही है, इस तरह से यह 241 करोड़ और 138 करोड़ मिलाकर हुआ 379 करोड़ । अब 250 करोड़ प्लान के लिये है, जो सोशल वर्क हैं, कृषि के, शिक्षा के, मेडिकल एड और स्वास्थ्य के, पब्लिक रोड्स के, पी0 डब्लू0 डी0 के और जो जनता की सहूलियत के कार्य होते हैं उन पर

खर्च होंगे इसमें कृषि भी शामिल है जो कि हमारी एकनामी की जान है। इन सब पर 250 करोड़ ही व्यय होगा। जबकि सब 660 करोड़ के करीब होता है। इस तरह से 250 करोड़ और 241 करोड़ यानी कुल 491 करोड़ और उसमें जोड़ दें 138 करोड़ तो यह कुल मिलाकर करीब 630 करोड़ हो जाता है। कुल आय 664 करोड़ है। मतलब यह हुआ कि 137 करोड़ रुपया तो वैसे ही कर्ज और सूद में चला गया। 250 करोड़ रुपया विकास के कार्यों के लिये है जिस में सोशल वेलफेयर और प्रोडक्शन के कार्य होते हैं। राज्य कर्मचारियों पर इतना बडा व्यय भी है, इन कार्यों के सम्पादन करने वालों को 241 करोड़ रुपया दे दिया जाय, दुनिया में इसकी कहीं मिसाल मिलेगी? बजट कैबिनेट में तय हुआ और तरह-तरह के भाषण उस पर होंगे। यह है देश की गरीबी और साधारण जनता की इनकी फिक्र और ख्याल, यह बजट आया है, यह इन की परफार्मेंस है।

आज देश की गरीबी का कारण क्या है? कारण एक ही है। वह प्रदेश के लिये और देश के लिये एक ही है, देश से प्रदेश को आइसोलेट नहीं किया जा सकता, सूबे की पालिसी पर भी पूरे देश का प्रभाव पड़ता है। जो पोलिटिकल लीडरशिप यहां की रही है वह दिल्ली में हो रही है और बिना किसी ब्रेक के उनकी नीतियां ही सारे देश में मानी जाती हैं सिवा चन्द 2 प्रदेशों में 8–10 महीने के लिये कुछ बदला है, उसको छोड़ दें बाकी केन्द्र में जिन के साथ हाथ में शक्ति रही है वही अधिकतर 90 प्रतिशत प्रदेशों में भी रही है। आप यह भी देखें कि हमारे प्रदेश की हालत क्या है। आप केन्द्र के आंकड़े देखें तो उसमें 3 प्रदेशों को छोड़कर हमारी पर कैपिटा इन्कम सब से कम है, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा और उनके अलावा जो अन्य 12–13 प्रदेश हैं उनकी हम से ज्यादा है। इन के इस भाषण में लिखा है कि सन् 60 से 71 तक 11 साल तक 2·5 प्रतिशत हर वर्ष सारे प्रदेशों की आय बढ़ी। सारे प्रदेश व देश का औसत है और उस पर ढाई प्रतिशत आबादी बढ़ जाती है और हमारे प्रदेश में भी 2 प्रतिशत बढ़ जाती है यह तो खुशी की बात है। अगर ढाई में से कम कर दें तो पर कैपिटा इनकम हमारी भी आधा प्रतिशत बड़ी है प्रति वर्ष। अब इधर 72–73 में वह बढ़ी 1·8 प्रतिशत। इसका अर्थ यह हुआ कि पर कैपिटा इनकम गत वर्ष में हमारी घटी है, पीछे चली गई है, यह हमारी गरीबी का हाल है। गरीबी का मुख्य कारण यह है कि न हमारे देश में और न हमारी स्टेट में कृषि को प्रधानता दी गई। जब अंग्रेज यहां पर मौजूद थे तो अगर आज 50 फीसदी लोगों को भर पेट अन्न नहीं मिलता है तो उस समय 1947 के पूर्व 25 फीसदी आदमी ऐसे थे जिनको भर पेट अन्न नहीं मिलता था और यह एक सर्व सम्मत बात है कि सिवाय कम्युनिस्ट लोगों को छोड़ कर सारी दुनिया मानती है कि देश का आर्थिक विकास तभी होगा जबकि खेती की पदावार बढ़ाने पर जोर दिया जाय। जब तक खेती का विकास नहीं होगा हमारे देश की गरीबी मिट नहीं सकती। प्लानिंग में खेती के विकास को पहली प्रायरिटी देनी चाहिये थी। लेकिन नहीं दी गयी। पहली फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में बेशक कुछ दी गयी। डा0 के0 एन0 राव, जो एक एकोनोमिस्ट हुए ह, उनकी मर्जी से वह प्लान बनाया गया था, उन्होंने बेशक कुछ ध्यान दिया था लेकिन फिर ट्रेन्ड बदल गया।

माननीय नेहरू जी का ख्याल था कि कारखाने पहले और बड़े कारखाने खास तौर से पूंजी हैं आर्थिक विकास की लेकिन उनका ख्याल क्या था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलोजी में खेती का गौण स्थान है और इन्डस्ट्री में भी बड़ी इन्डस्ट्रीज का। लेकिन 1961 में जब ख्रुश्चेव ने कहा था कि स्टील पैदा करने से क्या फायदा जब खाने के लिये लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है। वहां भी नहीं मिल रहा है, इसलिये वे अमेरिका से गल्ला ले रहे हैं। 1962 में माओं ने बदला। ली फार्वर्ड एक मूवमेंट चला था, आर्थिक कठिनाई बढ़ गयी थी। तीन हफ्त में सेशन होता है। 16 अप्रैल को जो रेजोल्यूशन होता है, उसमें कहा जाता कि एग्रीकल्चर को पहला स्थान दिया जायगा, छोटे

[श्री चरण सिंह]

रोजगारों को दूसरा और तीसरा हेवी इन्डस्ट्रीज को स्थान दिया। जब रूस ने और चीन ने मजबूर होकर अपनी पालिसी को बदला तो नेहरू जी ने भी 1963 में कहा था, जैसा कि नेशनल हराल्ड में छपा था कि न कारखाने, न इन्डस्ट्री, न छोटे और बड़े कारखाने बल्कि यह खेती है जो आर्थिक विकास की आधार शिला है। नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल के सामने स्पीच होती है। लेकिन 6 महीने बाद वे विदा हो गये। उस समय पंडित जी ने अपनी राय बदल ली। हेवी इन्डस्ट्रीज आदि के बारे में उन्होंने क्या कहा, उसे मैं छोड़ देता हूं।

हमारे प्रधान मंत्री और प्लानिंग मिनिस्टर, श्री डी० पी० धर ने एक स्पीच दी, हिन्दुस्तान टाइम्स में आप पढ़िये। एग्रीकल्चर के बारे में एक सेमीनार हुआ और उसमें एन० आर० मिर्धा और श्री डी० पी० धर ने कहा कि हम सोवियत टाइप की एकोनोमी चाहते हैं। सारी जमीन का कलेक्टीवाइजेशन हो जाय, बड़े-बड़े कारखानों का नेशनलाइजशन हो जाय और सारी चीजें पब्लिक सेक्टर में हो जायं। परसों ही कहा है कि खेती की पदावार में इन्स्टीट्यूशनल चेंज नहीं हुआ है। इसका स्टेचर बदला जाय, ज्वाइन्ट फार्मिंग, बड़े स्केल पर हो। आज योरोप के हर देश में रूस के मुकाबले में खेती की पदावार फी एकड़ ज्यादा है और आज जमीन ज्यादा अच्छी होते हुये भी एक साल के ड्राउड के कारण नहीं, तीन साल के लिये रूस अमेरिका से कर्ज ले रहा है और हमारे यहां ऐसे अन्धे लोग बठे हुये ह कि जिन्होंने गांव अपनी जिन्दगी में नहीं देखा होगा, काश्मीर से आये और प्लानिंग मिनिस्टर बना दिये गये। कुछ रिएलिस्टिक बात अगर की थी तो वह श्री सुब्रामनियम साहब ने की थी जिन्हें पोलीटिकल ग्राउन्ड्स के आधार पर हटा दिया गया।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

आप स्टेट की बात करें, केन्द्र की नहीं... (शोर)

श्री चरण सिंह—

मैं राम प्यारे जी से अर्ज करता हूं कि वे मेरी बात सुनने की कोशिश करें। हम केन्द्र के ढांचे से आईसोलेट नहीं हो सकते। एग्रीकल्चर की आधी स्कीम वे ही मंजूर करते हैं। उनके पास रुपया है। सन्ट्रल स्कीम के ढांचे पर जिक्र करना आवश्यम्भावी है। उनका जिक्र करना जरूरी है कि जिनके हाथ में प्लानिंग है। मि० मिजा जो नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन के चेयरमैन हैं, उनको एक सिम्पोजियम में बुलाया उसमें यह कहा कि कृषि पर कम ध्यान दिया गया है। केवल 70 अरब रुपये कृषि पर रखे हैं। उन्होंने सिम्पोजियम में प्लानिंग मिनिस्टर से यह कहा कि रुपये और भी ज्यादा रखने की जरूरत है। अखबारों में भी यह बात आई है। 4.7 तो फी वर्ष प्रोडक्शन में इजाफा हो सकता है। असल परफार्मेंस ला है। परफार्मेंस ला क्या है? इन्स्टीट्यूशनल चेंज नहीं है। तो खेती में उतना रुपया नहीं मिला जितनी उसको जरूरत है। क्या उसका असर एकानामी पर होगा? हमारे देश के जो लीडर हैं, जिनके हाथ में सन्ट्रल गवनमेंट की बागडोर है, वे आज भी उसे नहीं समझते हैं। मैं राम प्यारे जी को बता देना चाहता हूं कि खेती के लिये दो चीजों की जरूरत है। मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से श्री राम कुमार शास्त्री को बता देना चाहता हूं और वे जानते हैं कि खेती के लिये दो चीजों की जरूरत है। वह हैं पानी और खाद। मैं चाहता हूं शास्त्री जी मेरे आंकड़े नोट कर लें। सन् 51 में आंकड़े मिले हैं प्लानिंग के। 72 के नहीं मिले 67 के मार्च तक हैं। तो सन् 51 तक 115 मिलियन हेक्टर में से 11 करोड़ 87 लाख हेक्टर पर हमारे यहां खेती होती थी। 30 करोड़ एकड़ कुछ कम हुआ। उसमें 2 करोड़ 9 लाख हेक्टर में पानी का इंतजाम था। प्राइवेट या पब्लिक सासज थे। तो 12 करोड़ हेक्टर में से 2 करोड़ 10 लाख हेक्टर में 17.6 फीसदी सिंचाई थी। अब हमारे यहां खेती के जमीन में कुछ एक्सटेंशन हुआ है। अब रकबा कोई 14 करोड़ एकड़ हो गया है। उसमें 27.5 मिलियन हेक्टर में व 3 करोड़ हेक्टर में पानी

का इंजताम हुआ 20 फीसदी । अंगेज जब गये तब 17.6 फीसदी था । अब यह 20 फीसदी है । यानी 2.4 फीसदी सिंचाई का रकबा बढा है । 69 के इधर के आंकडे नहीं हैं । उसको मैं 3 फीसदी मान लेता हूं । साढे तीन फीसदी अधिक से अधिक मान लें । ऐसा क्यों है ? अगर आप 40 फीसदी भूमि पर आबपाशी कर देते तो यह हालत क्यों खराब होती ?

एक सदस्य—

(सरकारी पक्ष से) आप आंकड़े गलत दे रहे हैं ।

श्री चरण सिंह—

यह कौन साहब कह रहे हैं । मुझे खुशी होगी अगर वे सही आंकडे बता दें। अभी पांच दिन बहस होगी । अगर आप साबित कर दें तो मैं आपके आंकडे मान लूंगा। मेरे गवर्नमेंट के आंकड़े हैं । यह गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, प्राइवेट नहीं । अगर आप कहें तो नाम और टेबिल बता दूं । अध्यक्ष महोदय, 3 या साढे 3 प्रतिशत सिंचाई है, ऐसा क्यों ? जब कि 70 प्रतिशत आदमी खेती में लगे हुये हैं । लोग भूख से मर रहे हैं, खेती के बिना आर्थिक विकास नहीं हो सकता, फिर खेती की तरफ यह उपेक्षा ? फिर कहा जाता है आप लोगों की तरफ से, कि सूखा पड गया 3 सूबों में—महाराष्ट्र, गजरात और राजस्थान और चूंकि पैदावार कम हुई इसलिये भाव बढ़ गये, बंगला देश का भी नाम लिया जाता है । यही नहीं, मान्यवर, यह तो सी0 आई0 ए0 को भी कह रहे हैं । अब मैं माननीय दोस्तों से यह जानना चाहूंगा कि सन 1970 में 10 करोड 78 लाख टन फूड ग्रेन पैदा हुआ और सन 1971 में 10 करोड़ 40 लाख पैदा हुआ यानी 38 लाख टन 1971 में घट गया । क्यों ? जब कि सीजन नार्मल था, सूखा नहीं पड़ा था, कुछ इलाकों में ज्यादा वर्षा भी हुई थी । बावजूद ज्यादा बारिश के, प्लानिंग कमीशन का अनमान यह था कि 112 मिलियन टन पैदावार होगी 1971–72 में । यह बारिश होने के बाद की फिगर है, उससे पहले तो 113 मिलियन टन थी । और पैदावार हुई 104.6 मिलियन टन, जब कि बारिश नार्मल हुई । ऐसा ड्राट की वजह से नहीं हुआ । इसका क्या कारण था कभी यह जानने की कोशिश की ? पहला कारण यह था कि हाई ईल्डिग बेराइटी के लिये ज्यादा पानी की जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पानी का इन्तजाम नहीं हो सका और जो आपने पानी का इन्तजाम किया वह केवल 3 प्रतिशत किया । एक तो यह कारण है ।

दूसरा कारण था फर्टीलाइजर की कमी । जितनी खाद चाहिये उतनी खाद मिलती नहीं । अब म माननीय मित्र को, जिसके पास भी एग्रीकल्चर हो, यह बताना चाहूंगा कि जो खाद मिलती है उसमें 40 प्रतिशत मिक्सचर है। यह गवर्नमेंट आफ इंडिया की रिपोर्ट है और अगर आप कहें तो मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया की रिपोर्ट भेज दूं—40 प्रतिशत मिक्सचर होता है । यही नहीं, मैंने जो अखबारों में पढ़ा, आपके कानपुर रिसर्च इन्स्टीट्यूट के डा0 धर्मपाल सिंह के बयान में लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़े जबकि 40 प्रतिशत मिक्सचर है । उससे तो सारी की सारी खाद बेकार हो जायेगी । उसके लिये शिन्दे साहब ने कहा कि बजाय गवर्नमेंट और प्राइवेट लोगों के उसको कोआपरेटिव सोसाइटी करें तब तो और डूब जायेगा । फिर तो 40 प्रतिशत के बजाय 60 प्रतिशत मिक्सचर हो जायेगा । अब जो जो चीज खराब होती जायेगी या तो आप नेशनलाइजेशन करेंगे या कोआपरेटिवाइजेशन करेंगे । नेशनलाइजेशन अच्छी थ्योरी है, लेकिन जिन-जिन चीजों ने आपने नेशनलाइजेशन किया वह आपके सामने है सब फेल हो गई । यह तो आपके आंखों के सामने है, फिर इसका क्या हल है ? दूसरी बात यह है कि आप ही बताइये कि कौन सी कोआपरेटिव सोसाइटी आज ईमानदारी से चल रही है ? एक तो पानी नहीं मिलता, दूसरा फर्टीलाइजर जो मिलता है वह 40 प्रतिशत मिक्सचर के साथ और यह भी समय से नहीं मिलता, तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं जिसे आपको सुनकर हैरत होगी और वह यह है

[श्री चरण सिंह]

कि जैसा मुझे मालूम है कि कोई भी सरकार दुनिया में, फर्टीलाइजर पर टैक्स नहीं लेती, यहां कि मालदारी समाजवादी सरकार भी। सभी गवर्नमेंट यह चाहती है कि पैदावार बढ़े ताकि लोग निश्चित होकर रह सकें और इन्डस्ट्री का प्रोडक्सन बढ़े। इन्डस्ट्री का प्रोडक्शन तभी बढ़ सकता है जब फूड का प्रोडक्सन ज्यादा हो और लोग खाने से बेखबर हों। दो गवर्नमेंट, जैसा कि मुझको मालूम है—ब्रिटेन और पाकिस्तान सब्सिडी देती है, यानि उल्टे किसानों को अनुदान देती है। 20 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है किसानों को। और इस बदकिस्मत मुल्क में जहां कि किसान सबसे ज्यादा गरीब है यहां की गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। पहले टैक्स दस प्रतिशत था, अब पन्द्रह प्रतिशत कर दिया गया। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि यह मालूम ही नहीं और यह सरकार महसूस ही नहीं करती कि खेत की पैदावार बढ़ानी है और उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि खेत की पैदावार बढ़ने से ही यहां की इकानोमी डेवलप होगी। आप कितना टैक्स फर्टीलाइजर से वसूल करते हैं? अगर आप सब्सीडी म सौ करोड़ और मान लीजिय आपको 25 करोड़ टैक्स नहीं मिला तो इस सब्सीडी देने से जो इकनामी डेवलप होगी उससे कई गुना आपको टैक्स मिलेगा। हमारी गवर्नमेंट ने 3 परसेंट टैक्स सन् 69 में लगाया था जिसको सन् 70 में आकर हम ने एबोलिश कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जिनके हाथ में गवर्नमेंट है उन्होंने क्यों टैक्स लगाया है? सन् 1971–1972 का जो इकनोमिक सर्वे निकला है और उसमें जो दलील लिखी है कि हमने क्यों टैक्स लगाया फर्टीलाइजर पर, क्यों टैक्स लगाया ट्रैक्टर पर, क्यों टैक्स लगाया पम्पिग सेट्स पर वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं।

"The psychology of the ruling clique at the centre will be apparent from the following statement contained in the economic survey for 1972-73:

> "The increase in excise duty on fertilizers from 10 per cent to 15 per cent and the imposition of 10 per cent duty on power-driven pumps (in 1971-72 a duty on agricultural tractors had been imposed) was intended to tax high income groups in the rural sector, within the constraints of the Constitution".

क्या मेरे मित्रों का यह कंटेंशन है कि केवल मालदार किसान ही फर्टीलाइजर इस्तेमाल करता है। मेरे मित्र बतलायेंगे कि यू0 पी0 के अन्दर कितने बड़े किसान पहले थे और कितने आज हैं। उनकी इत्तिला के लिये मैं बतलाता हूं। सन् 58 में केवल 8 हजार होल्डिंग्स थीं जो 30 एकड़ से बड़ी थी और आज और कम हो गयी होंगी। अब तो 18 एकड़ ही रह गया और जब आप सीलिंग लगाने जा रहे हैं तो यह आर्गूमेंट बिल्कुल ही खत्म हो गया। लेकिन मान लीजिए आप सीलिंग न लगावें और उन्हीं 8 हजार को लें तो भी वह 4 हजार रह गयी होंगी। क्या मेरे माननीय मित्र और कृषि मन्त्री यह वायदा करेंगे कि वह गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखेंगे कि एक्साइज ड्यूटी फर्टीलाइजर पर खत्म कर दी जाय। लेकिन कहां है यह हिम्मत उन्हें, कहां है यह एहसास कि अर्थ व्यवस्था क्यों बिगड़ी और उसका इलाज क्या है? डी0 पी0 धर साहब पं0 जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं लेकिन उन्होंने भी अपनी पालिसी रिवाइज कर ली थी। गांधीनगर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें कहा गया कि कोई लफ्ज नहीं बदलेंगे बिकाज इट वाज फ्रेम्ड बाई दि आर्कीटेक्ट आफ इंडिया। लेकिन जिस लीडर का नाम लेते हैं तो यह नहीं मालूम कि उन्होंने भी अपनी पालिसी रिवाइज कर दी थी और अपने तजुर्बे से इस नतीजे पर पहुंचे थे कि खेती पर ज्यादा ध्यान देंगे। न कोई देहात से वास्ता है और न जनता से वास्ता है। यह तो रही दिल्ली की बात, अब यहां की लीजिए।

बिजली की कमी है और उसकी बहुत से आब्जेक्ट्स, बहुत से उद्देश्यों के लिए जरूरत है। जब उसकी कमी है और सबको नहीं दे सकते तो वह किसको दी जायगी जिसको हम अपनी इकानामी के लिए ज्यादा वाइटल समझते ह उसको दी जायगी। यह न भूल जाना

कि हम लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं जो 50 प्रतिशत भूखे हैं जिन्हें अन्न नहीं मिल रहा है (let alone fruit and milk) अल्यूमिनियम ज्यादा महत्व रखता है हमारी इकोनामी के लिए या एग्रीकल्चर । दिसम्बर में इस सम्बन्ध में यहां पर बहस हुई थी। तब हमने बिजली की कटौती का मामला उठाया था । मैं और बातों को भूल जाता हूं। मने 4 बातें कही थीं। फिर उनको दुहरा दूंगा। मैंने वित्त मन्त्री जी से यह जानना चाहा था कि वे यह जवाब देने को तैयार हैं कि बिरला को और बिजली नहीं देंगे। मैंने सुना है कि वे और एक्सपेंशन कर रहे हैं। क्या जब तक संकट है तब तक बिजली नहीं देंगे? दूसरी बात यह है कि 4 करोड़ रुपए का नुक्सान इस गरीब जनता को हो रहा है क्योंकि हमने एक गलत एग्रीमेंट कर लिया है सन् 1959 में कि दुनिया में बिजली का कोई भी दाम हो, बिजली पैदा करने का खर्च कितना ही हो जाय मगर हम आपको 2 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ही बिजली देंगे। मैंने तो इसको बहुत प्रोटेस्ट किया था और यह बात अपने इस्तीफे में भी लिखी थी। बीच में वह ला डिपार्टमेंट से पूछा गया। उन्होंने कहा कि इसमें चेंज नहीं हो सकता है। बाद में एक कमेटी भी बैठी जिसके श्री शिवराज सिंह चेयरमैन थे। वे तफसील में गए और इस नतीजे पर पहुंचे कि यह एग्रीमेंट कैंसिल किया जा सकता है क्योंकि वह एग्रीमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऐक्ट के प्रोविजन्स के खिलाफ है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस क्वेश्चन को स्टडी कराया गया या नहीं? अगर लीगल रिमेम्ब्रेंसर राजी नहीं है तो एडवोकेट जनरल से पूछिए ।

फिर मैंने पूछा कि क्या उस वक्त तक बिजली बन्द कर दी जायगी जब तक कि यह संकट है? उन्होंने कहा कि यह तो कनटीनुअस प्रोसेस है। बाद में यह तय हुआ कि आर्टिफिशियल रबड़ कम्पनी और सीमेंट सब चीजें जरूरी ह। तो सीमेंट भी ज्यादा जरूरी है, आर्टिफिशियल रबड़ कम्पनी भी ज्यादा जरूरी है, अल्यूमिनियम भी जरूरी है, अगर जरूरी नहीं है तो केवल खेत की पैदावार जरूरी नहीं है। हमने तो 30 परसेंट बिजली की कटौती कर दी थी जब कि संविद की सरकार थी। चारों में से एक बात नहीं की ।

अध्यक्ष महोदय, आपको और माननीय मित्रों को जानकर तकलीफ होगी कि यह जो पंच वर्षीय योजना बनने जा रही है इसमें 350 करोड़ रुपया टेलिवीजन और ब्रोडकास्टिंग के डेवलपमेंट के लिए रखा जा रहा है। मेरे पास श्री इन्द्र कुमार गुजराल की स्पीच है, और वैसे भी मुझे मालूम है। ऐसे टेलिविजन सेट्स तैयार किये जा रहे हैं जो छोटे हों और उनके लिए वे कहते हैं कि सब्सिडी देंगे। यह कमिटमेंट है कि सब्सिडी देंगे टेलिवीजन सेट्स पर ताकि अगले इलेक्शन में टेलीविजन सेट हर एक लड़के के पास हो जाय जिससे कि हमारे कांग्रेसी लीडरों की तस्वीर ही नहीं बल्कि उनके भाषण और उनके तर्ज भी सब जनता के सामने आ जायें और इस प्रकार वे दूसरी पार्टियों के खिलाफ प्रचार कर सकें। अध्यक्ष महोदय, यह साढ़े तीन अरब की सब्सिडी दे रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आज हमारे मुल्क की क्या हालत है? हम 150 अरब का अन्न बाहर से मंगा चुके है और 17 अरब की रुई बाहर से मंगा चुके हैं? (Euphoria) यूफोरिया हो गया था कि बड़ी पैदावार हो गयी है सन् 1970-71 में—बाहर से नहीं मंगायेंगे । आज हमें दर-दर से भीख मांगनी पड़ रही है। गुजराल साहब ने कहा है कि टेलिवीजन सेट्स की गांवों में जरूरत है। अन्न के लिए पानी की जरूरत नहीं है। 3 1/2 अरब रुपए को क्यों नहीं लगाते हों ट्यूबवेल और बिजली पहुंचाने में और नहरें बनवाने में? इन्द्रकुमार गुजराल का कोई रिश्तेदार गांव का रहने वाला नहीं है, कोई तकलीफ उनको नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, ऐसे लोग गांव वालों की समस्या हल नहीं कर सकते ह जिन्होंने गरीबी कभी देखी नहीं है या उसका तजुर्बा नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह तो मूर्ख विद्वानों का खेल है। जैसा कि जवाहर लाल नेहरू जी के केस में हुआ। अक्ल तभी आती है जब मौका हाथ से निकल जाता है।

श्री चरण सिंह---

मैं समझा नहीं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यह अर्ज कर रहा था कि टेलीविजन के सम्बन्ध में विचार किया जाय। टेलीविजन पर लक्ष्मीरमण आचार्य जी कुछ कह रहे थे। आपकी सरकार उसके लिए सब्सीडी देने जा रही है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)---

दो विद्वानों की बात...

श्री चरण सिंह---

मैंने वह वापस ले लिया है। आपकी सरकार को उसको रोकना चाहिए। टेलीबीजन सेट पर सब्सिडी ज्यादा जरूरी है या फर्टिलाइजर्स पर। म इस बात को यहीं छोड़ता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब स्टेट ट्रेडिंग इन फूडग्रेंस लीजिये। सरकार गल्ले का व्यापार खुद करेगी। अध्यक्ष महोदय, वह कहां से शुरू हुआ। पहले हवा यह चली कि बेसिक कन्जम्पशन की जितनी चीजें हैं सभी में स्टेट ट्रेडिंग होगी। कुछ दिन बाद यह हुआ कि नहीं फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर होगी। वह अब जाकर फूड ग्रेंस में रह गई है। गहूं और चावल पर होगी। इससे काम नहीं चला, तो गेहूं पर तत्काल हो गई और चावल पर अगली साल से होगी। इसी तरह से अरबन सीलिंग की बात कह दी लेकिन सोचा नहीं कि इसका क्या मतलब है। स्टेट ट्रेडिंग फूड ग्रेंस में हो, क्योंकि कम्युनिस्ट डिक्शनरी में इस समस्या का यही हल है कि इसे सरकार अपने हाथ में ले ले और खुद करे। महात्मा गांधी की टीचिंग के बजाय कि छोटे स्केल पर सभी चीजें होना चाहिए, हमारे जहन में यह आया है कि बड़े स्केल पर शान रहती है। उससे ज्यादा अच्छा रहता है। डा० बोरमा, डायरेक्टर जनरल, फूड, यू० एन० ओ० आये थे। उन्होंने कहा था कि गंगा कावेरी ग्रिड बन रहा है लेकिन यह स्कीम ठीक नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह कलयुगी भगीरथ बनना चाहते हैं।

श्री चरण सिंह---

डा० राव कलयुगी भगीरथ बनना चाहते हैं।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

चौधरी साहब बोल रहे हैं तो यदि जायसवाल साहब डिस्टर्ब न करें तो अच्छा हो। वह ठेके लेने का काम करते हैं, यदि चाहें तो इसका ठेका भी ले लें।

श्री चरण सिंह---

इसकी जरूरत नहीं है लेकिन आप उनसे क्यों घबड़ा रहे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

इसलिए घबड़ा रहा हूं कि आपकी स्पीच हो रही है तो उसको डिस्टर्ब क्यों करते हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कहा कि ताल-बद्ध हो तो कोई बात भी है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मुख्य मन्त्री जी चाहते हैं कि दाद भी न दी जाय!

श्री चरण सिंह---

मैं यह अर्ज कर रहा था कि गंगा--कावेरी ग्रिड योजना के बारे में बोरमां ने यह कहा है कि यह बहुत बड़ी स्कीम है। डेवलपिंग कन्ट्रीज, वह गरीब मुल्क जो अपने विकास के काय में लगे हुए हैं उनके लिए यह नामुमकिन है कि वह यूरोप और अमेरिका की नकल कर लें और अगर कर भी लें तो तजुर्बा यह साबित करता है कि उनमें नुक्सान होता है। उन्होंने कहा कि मैंने तो अध्ययन नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया को एडवाइस करूंगा कि वह इस स्कीम को छोड़ें। तो यह एक एक्सपर्ट बाहर का आकर कहता है, लेकिन कुछ ऐसी बदकिस्मती इस देश की कि प्रोग्रेस, सोशलिज्म, लार्ज-स्केल खेती, लार्ज इंडस्ट्री इन सब का कनफ्यूजन हो गया। प्रोग्रेस तभी मानी जायगी जबकि 10 अरब का तजवीज बन जायगी। जोकि छोटे स्केल पर भी हो सकती है और उससे ज्यादा लाभ देगा। वह उसके बजाय यह करते हैं कि बड़ी से बड़ी चीज बनाते हैं, बड़े देशों की नकल करते हैं।

जहां तक स्टेट-ट्रेडिंग का सम्बन्ध है, बहुत कम को मालूम होगा कि स्टेट ट्रेडिंग इन फडग्रेन कोई नयी ईजाद डी0 पी0 धर की या इंदिरा जी की नहीं है। पंडित जी स्वयं 1959 में नागपुर में लाये थे--एक सीलिंग, दूसरे कोआपरेटिव फारमिंग और यह स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रस और 1972 में उनकी बिटिया ने भी वही चीज उठा ली---सीलिंग, कोआपरेटिव फारमिंग और यह स्टेट ट्रेडिंग। वह स्वयं कुछ नहीं कहतीं। प्रेसीडेंट कह रहे हैं और उनके मिनिस्टर कह रहे हैं, डा0 शंकरदयाल शर्मा कह रहे हैं, पी0 सी0 सेठी कह रहे हैं, सिनहा साहब आसाम के कहते हैं। श्री सुब्रमणियम जो मिनिस्टर है शायद इंडस्ट्रीज के वह एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और मैं भी यहां मिनिस्टर ऐग्रीकल्चर का रहा। उनके बराबर बयान यह रहे कि नेसेसरी आर्गेनाइजेशन सेट-अप कर रहे हैं। लोगों ने मुझसे कहा कि तुम पर डिसिप्लनरी ऐक्शन हो जायगा, क्योंकि मैंने असेम्बली और कौंसिल में कहा कि वह नाकाबिले अमल है, डेमोक्रेसी में यह सम्भव नहीं है, फ्री इकोनामी में यह कभी नहीं हो सकता। हां, टोटलिटेरियन इकोनामी में हो सकता है। सुब्रमणियम कहते रहे और नहीं हुआ। अब फिर वही बात उठी है। आज तो जयप्रकाश नारायण ने भी यही कहा कि यह अव्यवहारिक चीज है, इसको छोड़ देना चाहिए। मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि ठीक यही बात रूस में कही गयी थी। मैं माननीय मित्रों की इत्तिला के लिए बताना चाहता हूं कि वहां तो सीलिंग क्या, रिडिस्ट्रिब्यूशन आफ लैन्ड हुआ। आधा-आधा एकड़, दो-दो और 3-3 एकड़ जमीन बांट दी गयी सबको। फिर यह हुआ कि लोगों से कहा गया कि इकट्ठी कर लो। तो पहले कोआपरेटिव फारमिंग, फिर कलेक्टिव फारमिंग और फिर स्टेट फारमिंग हो गयी। उसके करने के लिए यह कहा किसानों से कि गल्ला दो शहर के लिए और फार एक्सपोर्ट टु फारेन कन्ट्रीज जिससे फारेन एक्सचेंज मिले। तो विदेशों में भेजने के लिए किसानों से सस्ता गल्ला ले कर बढ़े हुए दामों पर विदेशों में भेजा गया फारेन एक्सचेंज प्राप्त करने के लिए जिससे बड़ी-बड़ी फैक्टरीज एस्टैब्लिश की जा सकें। तब किसानों ने कहा कि कम्युनिस्टों से कि तुम हमारे प्रोडक्ट्स तो सस्ते कर रहे हो और हमें अपनी जरूरियात के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है जोकि नान-ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंजीनियर्स पैदा करते हैं फैक्टरियों में उनके दाम आपने नहीं घटाए, तो उन्होंने गल्ला नहीं दिया। इसपर जमीन जब्त हुई, जाने क्या-क्या हुआ, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। 50 लाख किसान मारे गए या साइबेरिया में बरफ में गलने के लिए भेज दिये गये---स्टेलिन का स्टेटमेंट है। इनके सामने वही रूस की मिसाल थी, रिवोल्यूशन आफ 1917।

28 मार्च, 1959 को लोक सभा में जो 9---10 जनवरी में नागपुर से प्रस्ताव पंडित जी ने पास करा लिया था उसको स्वीकृति के लिए भेजा गया लोक सभा में।

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए)

[श्री चरण सिंह]

और पंडित जी ने उस स्पीच में यह कहा कि सीलिंग, कोआपरेटिव फार्मिग एण्ड स्टेट ट्रेडिंग आर पार्ट्स आफ दि सेम पिक्चर। और वह पिक्चर है सोशलिज्म या कम्युनिज्म की जहां आदमी को इंडिविजुअल और एकोनामिक फ्रीडम नहीं रहेगी। वह 13 साल में नहीं कर पाये, अब भी नहीं कर पायेंगे। स्टेट ट्रेडिंग इन फूडग्रेंस या ह्वीट का मतलब यह था कि सारा ह्वीट लें और आपकी रेस्पांसिबिलिटी यह कि सब को खिलाएं। टोटल प्रोक्योरमेंट करें और टोटल डिस्ट्रिब्यूशन करें। लिहाजा रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको लेना था। उसको इम्पासिबिल देख कर उसे छोड़ दिया। अब कह रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर दस क्विंटल गांव से ले सकता है। रिटेल ट्रेडर का तो गांव से कोई वास्ता था ही नहीं। वह तो बड़े आढ़ती से लेता था। आढ़ती इसको फाइनेंस भी करता था। 10 क्विंटल ले सकता है और 50 क्विंटल तक होर्ड कर सकता है। दाम उसकी वही लेने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट तय करे। अब मैं पूछना चाहता हूं खाद्य मन्त्री जी से या जो भी उन को रेप्रेजेंट कर रहे हों उनसे कि कितने लाख है रिटेल ट्रेडर्स? और वह ठीक दाम से दे रहे हैं और उसमें कोई एडस्ट्रेशन भी नहीं है यह कौन देखेगा? आपके पास मशीनरी है इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की? मुझे ठीक याद नहीं है, एक साहब ने बताया, पिछले साल आपने साढ़े 8 लाख टन प्रोक्योर किया था और अबकी 9 लाख टन प्रोक्योर करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बड़ा भारी काम कर रहे हैं, स्टेट ट्रेडिंग इन फूडग्रेंस कर रहे हैं। आपके जरिए माननीय मुख्य मन्त्री से मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार के पास गवर्नमेंट आफ इंडिया से कितनी कीमत वह गेहूं की देंगे इसका कोई सुझाव या आर्डर आया या कुछ लिखा है और लिखा है तो क्या लिखा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

गेहूं की कीमत तो निर्धारित हो चुकी है यद्यपि हमने इस बात की कोशिश की है गवर्नमेंट आफ इंडिया से कि हमको कुछ अधिक कीमत देने की इजाजत वह दे दें।

श्री चरण सिंह--

उन्होंने क्या कीमत तय की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वह तो ऐग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन का ऐलान हो चुका है।

श्री चरण सिंह--

आप उसमें तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? मुझे बता दीजिए।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

76, 74, 72 रुपए क्विन्टल।

श्री चरण सिंह--

छाछ5 से 74, तीन कीमतें मुझे मालूम हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह कीमत कम है। जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स के दाम बढ़ गए हैं उनको देखते हुए कम से कम 90 रुपए मेरी राय में होनी चाहिए। किसान को बिजली, फर्टिलाइजर, वर्कर्स वेजेज, सब बढ़ गए हैं, ट्यूबवेल्स की बिजली का हायस्ट रेट है, उसका ट्रैक्टर जो एक परसेंट भी आमद नहीं लेते 13 हजार के बजाय 27 हजार का हो गया, लेकिन उसकी इनकम जो पिछले साल और उससे पिछले साल थी वही है। इसलिए मेरा मुख्य मन्त्री जी से यही कहना है कि इस सिलसिले में वह गवर्नमेंट आफ इंडिया से और जोर के साथ लड़ें, उनके पीछे इस मामले में अपोजीशन पार्टीज भी हैं। यह बहुत अच्छी बात है अगर आप कामयाब हो जायं,

लेकिन एक बार जब यह उसूल तय कर लिए कि कोई राइवल परचेजर नहीं है तो क्या पता अगले साल गवर्नमेंट दाम कम कर दे, और कम कर दे फिर, करप्शन बहुत होगा। ओवरहेड एक्सपेंसेंज आपके दूने होंगे, बमुकाबले बनिए के, चाहे छोटा, चाहे बड़ा। इससे एक समस्या यह खड़ी हो जायगी कि लाखों आमदमी बेकार हो जायेंगे। बेकारी और बढ़ेगी ।

अब अमेरिका से जो लोग गेहूं मंगा रहे हैं, उसका नाम शायद 'माइलो' है या जो कुछ हो, उसके बारे में यह खबर छपी थी कि उसमें धतूरे के बीज मिले हुए हैं। आज यू0 एस0 ए0 में निकला हुआ एक बयान छपा है जिसमें यह कहा गया है कि वहां पर तो जो माइलो जानवरों को दिया जाता है उसमें धतूरे के बीज मिले रहते हैं और हमसे इंडियन गवर्नमेन्ट ने जो गल्ला मांगा वह जानवरों को खिलाने वाला मांगा था। आदमियों को खिलाने वाला नहीं मांगा था। अब यह चीज है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे आप सोच सकते हैं कि उनकी नजरों में आप क्या हैं।

डायरेक्टर, एफ0 सी0 आई0 के विरुद्ध अनेक करप्शन के चार्जेज थे। वहां पर 6 करोड़ का करप्शन था। बाद में उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। यह मिली सजा उनको। उनका जोर होगा। लिहाजा इस्तीफा मंजूर हो गया। जरा देखने की बात है कि 6 करोड़ के करप्शन का मामला और इस्तीफा मंजूर कर लिया गया? मैं पूछता हूं कि क्या माननीय त्रिपाठी जी की सरकार उनको कोई सजा दे पायेगी जो करप्शन करेंगे? नहीं दे पायेगी सिफारिशें आयेंगी क्योंकि हर आदमी का किसी न किसी से कोई एप्रोच निकल आती है, सिफारिश पहुंच जाती है।

अब एक बात जमाखोरी के बारे में कहना चाहता हूं। एक बड़े भारी उद्योगपति हैं मोदी साहब, उनके लड़के या भतीजे ने कोल्ड स्टोरेज में 4,133 क्विंटल या 4,133 बोरे गेहूं रखा। उनका खयाल था कि किसी का ध्यान इस ओर नहीं जायगा कि कोल्ड स्टोरेज में भी गेहूं रखा होगा। खर, किसी ने उसकी इत्तला कर दी। वह पकड़ा गया। नान-बेलेबिल वारेन्ट भी जारी हो गया क्योंकि ऐसे केसेज में ऐक्ट में गैर जमानती वारेन्ट का ही प्राविजन है। 2–3 आदमी पकड़ भी लिए गए। लेकिन जो मालिक था, जो साहबजादे साहब थे, वे गिरफ्तार नहीं हुए। 8–10 दिन वे मफरूर रहे, बाद को उनकी बेल हो गयी। उस पर राधारमन साहब से जो मैट्रापालिटन काऊंसिल के चेयरमैन हैं, जो कांग्रेसी हैं, उन्हीं से उनके ही आदमियों ने पूछा कि साहब, उनकी बेल कैसे हो गयी? इसमें तो नानबेलेबिल वारेन्ट है, यह कैसे स्वीकार हो गया? राधारमन साहब ने कहा मुझे नहीं मालूम . . .।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

ऐसी सेवाओं के लिए ही उनके बाप को पद्मश्री मिला था ।

श्री चरणसिंह––

वह मैंने दिया था, लेकिन इस काम के लिए नहीं, चोरी के लिए नहीं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

उनके बाप को मिला था, यह मैंने कहा। लड़के तो अब उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। उनके बाप को मिला था, अब उनके लड़के कोशिश कर रहे हैं ऐसी सेवाओं के जरिए ।

श्री चरणसिंह––

उद्योगों के सिलसिले में अवश्य उनकी बड़ी सेवाएं हैं। उस वक्त मुझसे एक आदमी ने कहा था कि ये बड़े उद्योगपति हैं, इनकी इस क्षेत्र में बड़ी सेवाएं हैं,आप सिफारिश कर

[श्री चरण सिंह]

दीजिए। और मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर कर दिया। किन्तु प्रेसीडेंट ने बाद में मुझसे यह कहलाया अपने सेक्रेटरी के जरिए कि आपकी पार्टी पर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट तरह-तरह के इल्जाम लगायेंगे, आप ऐसी रेकमेंडेशन क्यों करते हैं ? मैंने कहा बेशक उनका इंडस्ट्रयलिस्ट्स में विशेष स्थान है---ट्रुथ रिमेंस ट्रुथ, आप उनको दे दीजिए। लेकिन मेरी नालेज में किसी ने जुर्म किया हो या मोदी ने किया हो और मैंने सिफारिश किया हो तो मैं गिल्टी हूं। इस वक्त सवाल यह है कि वह छूट जाता है। उसके बारे में पार्लियामेंट में सवाल उठता है तो उससे मालूम क्या हुआ कि गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मिले थे और उसके बाद मैंटीनेंस आफ एन्टर्नल सिक्योरिटी ऐक्ट उठा लिया जाता है तथा एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट या जो अब लगा दिया जाता है जो काबिले जमानत है और उसे जमानत दे दी है, इतना ही नहीं आगे सुनिए तामिलनाडु के गवर्नर श्री के0के0 शाह को दिल्ली में एक पार्टी दी गई और मीटिंग हुई थी तो उसमें उसके भी दस्तखत हैं, जब वह मफरूर थे । अखबारों में छपा है जिसे मैंने भी पढ़ा है और भी मुझे मालूम हुआ है कि 20 लाख रुपए की रिश्वत दी गई तब वारन्ट कटा (वापस हुआ) । अब दीक्षित जी कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या दीक्षित जी ने गवर्नर से पूछा कि तुमने क्यों छोड़ा ? यदि रुपया नहीं लिया गया तो ऐसी कौन सी सिचुवेशन थी जिसमें उसे छोड़ा गया ? जब पूरे देश में फूड की स्केरिसिटी हो, फूड के सिलसिले में पूरे देश में ऐसी भयानक स्थिति हो और वह फूड के सिलसिले में सीरियस अपराध करता हो और जिसका वारन्ट भी इश्यू हो जाता है---गवर्नर छोड़ दे यह नामुमकिन है और उसने यदि छोड़ दिया है तो क्या उसका कोई जवाब तलब हुआ ? वाकिया यह है कि कोई अफसर यह गलती नहीं कर सकता है, ये कारनामे तो केवल पोलेटिकल लीडरशिप ही कर सकती है, या अफसर पोलेटिकल लीडरशिप के इशारे पर या उसके बल पर करता है। अब वह ग्रेन्स की स्टेट ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। होर्डिंग के खिलाफ कानून बड़ा सख्त किया जा रहा है। वह नाकाबिले जमानत रहेगा। अब जब इतना बड़ा जुर्म हो गया तो यह प्रोपेगंडा। तो आप इतने बड़े काम को कर सकेंगे ? इसके लिए इफीशिएट ऐडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो इसका नतीजा क्या होगा---नुकसान पर नुकसान होगा। गांधी नगर में भी कहा गया और कलकत्ता के सेशन में भी कहा गया कि कांग्रेसमैनों की कमेटी बनेगी हर मोहल्ले में यह देखने के लिए कि गल्ले का वितरण रिटेल-शाप पर ठीक से होता है या नहीं। त्रिपाठी जी की स्पीच मेरे पास मौजूद है, वह 17---18 तारीख को वाराणसी में बोले। उन दिनों मैं बलिया में था, मैंने उसकी कटिंग रख ली है। उन्होंने कहा---ब्यूरोक्रेसी का जहां तक सम्बन्ध है वह फेल हो चुकी है, ये गल्ला और शुगर समय पर जनता को नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए मैं कांग्रेसमैनों से अपील करता हूं कि वह उनकी मदद करें। मैं त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूं कि वह इस जनता को अफसरों की कृपा पर ही रहने दें, आप अपने आदमियों को तकलीफ न दें। नहीं तो गल्ले के दाम बहुत बढ़ जायेंगे और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जायेगा। जब राज्य कर्मचारियों से ठीक से काम नहीं करा सके, तो इनसे क्या आशा की जा सकती है---कम्पलीट फेल्योर आफ आनेस्टी ऐंड डिवटी। डी0 पी0 धर भी यही कह रहे हैं। मैं उनसे ही कहना चाहता हूं, आपसे नहीं कह रहा हूं। दुनियां में जैसे मानों वह रहते ही नहीं हैं। क्या आप समझते हैं कि वह कांग्रेसमैन बड़े ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ हैं कि वह बिना कमीशन के उसमें मदद कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, जो पावर डिपार्टमेंट है इसका मिसमैनेजमेंट। अध्यक्ष महोदय, इसके मुताल्लिक कोई अल्फाज नहीं है किसी के पास भी, मुझसे बहुत अच्छा बोलते हैं त्रिपाठी जी और जायसवाल जी, मैं उनके लिए छोड़े देता हूं, ज्यादा बात कहने के लिए। लेकिन मैं दो-तीन बाते कहूंगा इस सिलसिले में। उनका जो मेंटिनेंस हुआ है वह आल इंडिया

प्राबलम है। अभी सिंडिकेट में खबर निकली है। स्पेशलिस्ट्स को बिठाइए। मैंटिनेंस डिफेक्टिव है। केवल यह कि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिफेक्टिव है इससे काम चलने वाला नहीं है। गवर्नमेंट को खुद देखना है। माननीय राधाकृष्ण गोस्वामी जी अगर यहां पर हों तो मैं जानना चाहूंगा कि मैंटिनेंस के सिलसिले में कोई इंजीनियर्स की मीटिंग की है। क्या आर्डर दिया है? अगर नहीं बता सकते हैं आन दि स्पर आफ दि मोमेंट तो यह तो बता सकते हैं कि मीटिंग की है या नहीं। बाकी अपने जवाब में बतायेंगे या माननीय मुख्य मन्त्री को बतला दें। आपके सर पर है, पता नहीं आप महसूस करते हैं या नहीं, बोर्ड में 55 करोड़ रुपए का नुक्सान हो चुका है, दस करोड़ अभी हो चुका है। वह हम को देना है। तो जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाती है डिटेल्स में जायं। कारपोरेशन का एक्सपेरीमेंट फेल हो चुका है। आपने ट्रांस्पोर्ट में कारपोरेशन किया क्या नतीजा निकला? उनके लासेज आप भरेंगे। चुर्क सीमेंट आप करने जा रहे हैं वह भी भरेंगे। इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि जो इन्नोवेशन किया गया है, कारपोरेशन अप्वाइन्ट कर दिया, आपकी जिम्मेदारी कहां खत्म होती है? आपके अधिकार कम हो जाते हैं। इसपर भी विचार करने की जरूरत है।

ट्रांसमिशन लासेज 24 फीसदी। दुनिया में कहीं नहीं, हिन्दुस्तान के अन्दर किसी स्टेट में 24 परसेंट लासेज नहीं होते। 24 परसेंट में कम से कम एक तिहाई, आठ परसेंट थेफ्ट है। कितने आदमी पकड़े गए, कितनों को सजा दिया। कितने आर्डर्स हुए हैं चेयरमैन और आपके? उनके इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान दिया है? कितनों को सजा मिली है? कितनों का डिस्कनेक्शन हुआ है? मिनिस्टर हो गए। काफी है। और क्या करना है। अपना बल नहीं है तो दूसरों के बल पर हैं बेफिक्र हैं।

अब यह जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने स्ट्राइक की, गलती की। नहीं करना चाहिए था। लेकिन स्ट्राइक उन्होंने की। यहां रिवाज हो गया है। अगर उनकी एक बात मान लेते कि चेयरमैन कम से कम इंजीनियर होता जिसको मैंने कर दिया था तो आपने हटा दिया। एक आफिसर को ले आए। तो दोनों नान इंजीनियर्स हो गए। सेक्रेटरी मेरे जमाने में नान इंजीनियर था। आप उनको बुला कर उनसे बात कर लेते। मैंने तीन हठ सुनी हैं। राजहठ, त्रियाहठ, और बालहठ, यह राजहठ है।

त्रिपाठी जी का हठ है यह कि उनसे बात नहीं करेंगे। आप साइड कर रहे थे यह आपको याद होगा। यह सख्ती, कठोरता, रिजिडिटी और तानाशाही वाला एटिट्यूड आपका कब से हो गया। आप तो मुलायम आदमी थे शुरू में ही तय कर लेते। हमको सख्त व जालिम कहा जाता है माननीय टंडन जी ने भी कहा....

सूचना राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तम दास डन)—

आप तो बड़े मुलायम आदमी हैं

श्री चरण सिंह—

किसी वक्त मुलायमियत और किसी वक्त सख्ती की जरूरत होती है अगर इस स्टेट को चलाना है तो।

बहुत सख्ती करने की धमकी दी लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाये। आप सख्ती क्यों अख्तियार करते हैं आखिर को जब आप सरेंडर करेंगे, सब चीजें आप उनकी मानेंगे। एक डिमांड है उनकी जिस पर वे फिर हड़ताल करेंगे। नार्दर्न इंडिया एसोसियेशन इंजीनियर्स ने यह तय किया है कि जिन असिस्टेंट इंजीनियर्स को तरक्की दे दी वे लोग रिवर्ट किये जायं। अपनी पुरानी पोस्ट्स पर व भेज दिये जायेंगे यह आपने बयान दिया। यहां पर आपने कहा 15–1–1973 से यथापूर्व स्थिति (स्टेट्स को एंटे) बनी रहेगी जिसका अर्थ यह है कि उस तिथि

[श्री चरण सिंह]

के पश्चात जारी किये गये सभी सेवा समाप्ति, निलम्बन, नियुक्ति एवं पदोन्नति के आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे। या तो शुरू में ही नौबत न आती स्ट्राइक की। आ गई थी तो बुला कर बात कर लेते क्योंकि सख्ती आपकी रहती नहीं। आपने बातें मान लीं। मान ली थीं तो तकाजा यह है कि जो कुछ मान लिया उसको पूरा करो। हो यह रहा है कि पहले आर्डर कैंसिल किया प्रोमोशन का और उसी रोज से वह एस0डी0 ओ0 उसी तनख्वाह पर बना रहा एक्स केडर। सारे 30, 40 आदमियों के लिये यह सब हो रहा है। एक्स केडर उसी तनख्वाह की पोस्ट क्रियेट कर दी जो पदोन्नति पाकर वह पा रहा था। क्या मतलब हुआ? आखिर में इसी में आ जायेंगे हालांकि वे 60 पोजीशन जूनियर थे, आज सीनियर हो गये। उनकी यह बात पिंच करती है। जिन्होंने आपकी मदद की थी। आप राजी न होते लेकिन आप राजी हो गये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

पूरी रिपोर्ट आपको नहीं मिली। यह सारा मसला बहुत जल्दी ही तय हो जायगा।

श्री चरण सिंह—

आपने सारे ही मसलों के लिये यह कह रखा है और सब खटाई में पड़े हुए हैं। आप वायदा कर लेते हैं जल्दी में लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। आप बीमार हो जाते हैं और 15 दिन तक बनारस में रहते हैं। फिर यहां कौन सुनने वाला है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

भगवान न करे आप कभी बीमार हों।

श्री चरण सिंह—

आप बड़ी मीठी बात करते हैं। इससे स्टेट चलने वाली नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मीठी बात करना जुर्म है तो मैं अपना स्वभाव छोड़ नहीं सकता आप चाहे कितनी भी कड़वी बात कहें।

श्री चरण सिंह—

मेरा स्वभाव कड़वी बात कहना है लेकिन सही बात ही कहूंगा। बीमार हुए आप। बेशक यहां से एक डाक्टर गया। मैंने एक साहब से कहा कि आप बीमार हैं। उन्होंने कहा त्रिपाठी जी बीमार भी हैं लेकिन सारा काम भी कर रहे हैं। मीटिंग में भी जा रहे हैं। चुनाव में भी हिस्सा ले रहे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जो भी आपको खबरें लगती हैं वे सभी क्या सच होती हैं ?

श्री चरणसिंह—

वे सब गलत हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

तो गलत बातें न कहा करें।

श्री चरण सिंह—

मुझे इस सरकार की जितनी करप्शन की खबरें लगती हैं वे भी सब गलत ? इस तरह से आप बीमार हो गये। लेकिन जिस बात को मैं बाद में अर्ज करूंगा, इस बारे में आपने क्या किया है। किसी से आपने कुछ कहा है, किसी से कुछ कहा है, और पूरा किसी की बात को नहीं किया है। अगर दो क बात आप कर सकते हैं तो उतना ही कह दो और नहीं कर सकते हो तो कह दो कि नहीं कर सकते हैं। फिर जनता यह तो नहीं कहेगी कि आपने आश्वासन दिया था। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि यहां से दो लड़के प्राइममिनिस्टर से मिलने के लिये गये। चीफ मिनिस्टर ने उनसे वायदा किया था कि वे स्टूडेंट्स की प्रोबलम्स को दूर करने के लिये एक कमेटी को नियुक्त करने का इरादा रखते हैं। यह बात सबने अखबारों में पढ़ी होगी। वहां जाकर लड़कों ने यह कहा कि वहां पर चीफ मिनिस्टर ने हमसे यह वायदा किया था किन्तु 4 महीने का समय बीत गया है, अभी तक कुछ नहीं किया गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि गलत फहमी हो रही है तो अभी हाल ही मे 4/5 रोज हुए एक नार्दर्न इंडियन इंजीनियर्स एशोसियेशन की मीटिंग हुई थी उसके पहले या उसके बाद में उन लोगों को बुलाकर बात कर लेनी चाहिये थी कि तुम्हारी गलतफहमी हम दूर करेंगे, हमनें यह नहीं कहा था और यदि कहा था तथा उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कुछ नहीं किया गया।

एक बात मुझे और मालूम हुई है जिन इंजीनियर्स ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है उनको शीरनी बांटी गयी। ढाई हजार से 10 हजार रुपये तक नकद रिवार्ड दिया गया। एक साहब ने कहा कि ढाई हजार कम है, तो उसे ज्यादा दे दिया गया। मैं पूछता हूं कि यह क्या बात है। अगर किसी आफीसर ने स्ट्राइक नहीं की तो ही डिड हिज ड्यूटी। कैरेक्टर रोल में इन्ट्री करते वक्त आप यह कर सकते थे कि ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड एन्ड ओबीडियन्ट आफीसर। लेकिन आप नकद रुपया ढाई हजार से 10 हजार रुपया तक दें यह बिलकुल मुनासिब नहीं है। आप एक नई परिपाटी डालना चाहते हैं। इससे एडमिनिस्ट्रेशन खराब होता है वह चल नहीं सकता है। खैर, इस सिलसिले में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

अब मैं इंडस्ट्रीज के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय तिवारी जी बैठे हुए हैं वे मुझे बतायें कि जो इंडस्ट्रीज व सेट अप करने जा रहे हैं क्या वे सभी पब्लिक सेक्टर में होंगी। उन्होंने अपनी बजट स्पीच के पृष्ठ 9 पर जो इंडस्ट्रीज उल्लिखित की है। माइल्ड स्टील बिलट, स्कूटर, मुद्रण मशीनरी, सेफ्टी रेजर, बल्ब तथा फ्लोरेसेंट लैम्प्स, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, नाइलोन फ्लोमेंट, यार्न, लाइट कामर्शियल व्हीकिल्स, राइटिंग प्रिंटिंग एवं रैपिंग पेपर तथा रिफेक्ट्रीज क्या ये सब पब्लिक सेक्टर में लगेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जिन उद्योगों का मैंने शुरू में उल्लेख किया है उन्हें केन्द्रीय सरकार लगायेगी चाहे वह नई बनाये या पब्लिक जौइन्ट सेक्टर में चलाये लेकिन जो दूसरी परियोजनायें हैं ये उत्तर प्रदेश के लिये हैं और इसके लिये भारत सरकार से अनुज्ञा-पत्र अथवा आशय-पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम इन्हें या तो सीधे लगाय या ज्वाइंट सेक्टर में लगाये।

श्री चरण सिंह—

चाहे वह किसी भी सेक्टर में लगाये, लेकिन इस सिलसिले में मैं अर्ज कर चुका हूं कि वे इस पर विचार करें ताकि यह योजनाय प्राफिटेबुल हो सकें। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने 50 अरब से ज्यादे के अन्डरटेकिंग्स लगा दिये हैं जिनमें कि हर साल नुकसान हो रहा है। किन्हीं इडस्ट्रीज में नुगसान हो रहा है, किसी में लाभ हो रहा है लेकिन ओवर-आल रूप में नुकसान ही हो रहा है। भूपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स हैं उनमें अब तक 59 करोड़ पये का लास हो चुका है। यह आपके नेशनलाइजेशन का तरीका है। आज स्थिति बहुत खराब होती चली जा

[श्री चरण सिंह]

रही है। हमारा प्रदेश बहुत गरीब है। गवर्नमेंट आफ इंडिया तो बाहर से कर्जा लेकर काम चला रही है। जो चीज आप प्राइवेट सेक्टर में दे सकते हैं उसको दें, उस पर पूरा नियंत्रण रखें, यह देखते रहें कि वह जयादा मुनाफा न कमा सके और वह राष्ट्र के लिये ज्यादा कमाई बढ़ा सकें, इसके लिये आपकी भी ड्यूटी होगी कि आप लेबर की स्ट्राइकों को ज्यादा न एनकरेज करें लेकिन हर सूरत में वह बेहतर रहेगा बजाय इसके कि आप पब्लिक सेक्टर में ही वह काम करें।

पब्लिक सेक्टर का तो यह हाल देखिये। आपने अब कोल ले लिया अपने हाथ में और आज के ही पानियर में खबर यह है कि कानपुर में कोयला गायब हो गया, पहले भी कुछ कमी थी लेकिन जब से जनाब के हाथ में आया तब से कोल गायब हो गया फिर बिजली आपने अपने हाथ में ले ली। उसमें आपका कारपोरेशन है। जहां प्राइवेट चल रही है या चल रही थी, मार्टिन बर्न की थी या है वहां उनका इंटरनल मेन्टिनेंस भी ठीक है और सप्लाई भी ठीक है। लिहाजा उनके लिये भी क्वेश्चन नहीं उठता। मुझे जब मालूम हुआ कि बनारस में चौबीसो घंटे मिल रही है तब मैंने सोचा कि यह क्या बात है? यह क्या त्रिपाठी जी अपने जिले के लिये कर रहे हैं? लेकिन बाद में मालूम हुआ कि नहीं प्राइवेट कम्पनी के हाथ में है इसलिये वहां न तो बिजली की क्राइसिस है और न परेशानी जो हमारे यहां है। इसलिये ज्यादा तो इस पर मैं नहीं कहना चाहता लेकिन अगर कर सकते हों तो कैबिनेट में इस पर विचार करने की कृपा करें।

इस सारे बजट भाषण में कोई जिक्र काटेज इंडस्ट्री का नहीं है। जिससे इम्प्लायमेंट लोगों को मिलेगा वह इसमें है ही नहीं और इसलिये नहीं है कि हमारे सेन्टर का वही हाल है। थर्ड प्लान में इसके लिये नहीं था, फोर्थ प्लान में नहीं था, फिफ्थ प्लान में होगा या नहीं होगा लेकिन नहीं होगा क्योंकि दिमाग तो कहीं और है और काटेज इडस्ट्री का मार्ग तो गांधी जी का बतलाया हुआ था। हां, कुछ थोड़ा सा ध्यान है हैंडलूम का जो इसमें कहा गया है। बेशक वह काटेज इडस्ट्रीज है। लेकिन मैं तो यह कह रहा हूं कि चाहे वह हैंडलूम हो या और कोई काटेज इंडस्ट्री हो जब तक स्टेटुटरी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा उसको, मिकैनाइज्ड इंडस्ट्री के खिलाफ तब तक वह चल नहीं सकती। रोज क्राइसिस रहती है हैंडलूम की इंडस्ट्री में। गवर्नमेंट ने कहा है कि वह इसके लिये कदम उठाने जा रहे हैं लेकिन इसका इलाज कैसे हो जब आपने स्पिनिंग मिल्स हाथ में ले लिय तो क्या उससे काटेज इंडस्ट्री की प्राबलम हल हो जावेगी। गवर्नमेंट अब 34 करोड़ का कपड़ा खरीदने वाली है। गांधी जी नेकहा था कि जहां काटेज इंडस्ट्री से काम न चले वहां बड़ी इंडस्ट्री लगाई जावें। होना तो यह चाहिये था कि इन मिलों में जो कपड़ा बनता है वह विदेशों को सप्लाई हो और हडलूम का जो कपड़ा बनेगा वह हिन्दुस्तान में सप्लाई होगा तो इससे एक करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता और अनइम्प्लायमेंट का प्राब्लम हल हो जाता। अध्यक्ष महोदय, म यह अर्ज कर रहा था कि बेरोजगारी बढ़ती जाती है और हमारी गवर्नमट और यह स्टेट गवर्नमेंट भी सिर्फ फैक्टरीज का नहीं, मनुफक्चरर्स का नहीं बल्कि सर्विसेज का भी मिकनाइजेशन कर जा रही है। गांधी जी मिकैनाइजेशन, मशीनीकरण के खिलाफ इसलिये थे कि इस बेरोजगारी बढ़ जाती है। लेकिन आपने अपने बजट भाषण के प्रथम पेज पर ही कहा है—

"इस समय राज्य की प्राप्तियों एवम् व्यय के आंकड़े विलम्ब से प्राप्त होते हैं। इस कमी को दूर करने के लिये यह निश्चय किया गया है कि शासन के स्तर पर एक आधार सामग्री विधायन केंद्र (Deta Processing Centre) की स्थापना की जाय जिसके अन्तगत डेटा प्रोसेसिंग मशीनें रखी जायेंगी आदि आदि।" बड़ा भारी सूबा है, बड़ा भारी काम है, बड़े भारी आंकड़े और बड़ी भारी आमदनी ह। सबको एक आदमी नहीं कर सकता है इसलिये सूबे के अन्दर पढ़े लिखे नौजवानों की प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग के मान क्या

हुआ ? क्या आप गन्ने से चीनी बनाने जा रहे हैं जो उसकी प्रोसेसिंग करेंगे ? प्रोसेसिंग तो आंकड़े का होना है जिसमें जोड़, घटाव, जरब और तकसीम है, उसके लिये मशीन ।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर आपके सामने क्या नक्शा है समाज का ? हमारे यहां बेरोजगारी बराबर बढ़ती जा रही है । 30 लाख नौजवानों ने इम्पलायमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज कराये हैं जिनमें अधिकतर हाई स्कूल पास ह । यू0पी0 के अन्दर ही 35 प्रतिशत किसानों के परिवार हैं जिनके पास दो एकड़ से कम जमीन है । और न मालूम कितने लोग हैं, तो आखिर इनके लिये क्या नक्शा है ? आप कहते हैं कि एक स्कीम है जिसके अनुसार 5 लाख जाब्स का क्रीएशन हर साल होगा । क्या मतलब है, अब गवर्नमेंट जाब्स भी देगी ? आज भी जितने लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, खाली बैठे रहते हैं, अननेसेसरी हैं । गोपाल स्वामी आयंगर के जमाने में एक रिपोर्ट निकली थी, रफी अहमद साहब के जमाने में एक रिपोर्ट निकली और उसके बाद की एक रिपोर्ट है कि ऐटलीस्ट वन थाउजेंड लोग गवर्नमेंट आफ इंडिया की सर्विसेज में ऐसे हैं जो खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है । एक आफिसर जो इसी सेक्रेटेरिएट से गवर्नमेंट आफ इंडिया में गये, मुझसे दो दफा मिले तो मने उनसे पूछा कि बतलाइये यहां और वहां के काम में क्या फर्क है तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब वहां तो कोई आदमी काम ही नहीं करना चाहता है । मैं अपनी आदत के मुताबिक वहां आफिस में 10 बजे गया लेकिन वहां साढ़े 10 क्या साढ़े 11 बजे से पहले कोई नहीं आ सका । फिर मैंने भी साढ़े 11 बजे आफिस आना शुरू किया । जिस काम को एक आदमी कर सकता है उसी के लिये वहां तीन आदमी रखे जाते हैं । गवर्नमेंट सर्विस में रखने का मतलब तो यह हुआ कि जरूरत न हो तो भी जाब क्रीएट किया जायेगा । अक्तूबर, 70 में जब ए0 आई0 सी0सी0 की मीटिंग हुई थी तो उसमें भी 5 लाख जाब्स के क्रीएशन का उल्लेख किया गया था और लड़कों ने भी समाजवादी नारा लगाया था कि इससे सबको नौकरी मिल जायेगी । इसके बाद सुब्रामगयम साहब आये, उस समय भी ए0 आई0 सी0 सी0 की मीटिंग में एप्रोच पेपर में 5 लाख जाब्स देने का जिक्र आया यानी हर साल 5 लाख जाब्स का क्रीएशन करेंगे चाहे जरूरत हो या न हो । यानी इस तरह का प्रोबलम डेवलप करेगा कि लड़के अपने आप सर्विस में लिये जायेंगे । इसका क्या मतलब हुआ ? प्रोडक्टिव इम्पलायमेंट मिले तभी बेरोजगारी कम होगी वरना मुद्रास्फीति होगी । मैं उस सवाल में नहीं जाना चाहता कि पहले कितने नोट्स थे और अब कितने बढ़ गये हैं । प्रोडक्शन कम बढ़ा इसलिये भाव भी बढ़े । अन प्रोडक्टिव इम्पलायमेंट होने से जब प्रोडक्शन कम होगा तो कीमतें बढ़ेंगी और भी प्रोबलम्स पैदा होंगे । ऐसा नहीं है कि सरकार इसको जानती नहीं है लेकिन यह जान बूझ कर जनता को धोखा देना है कि हम हर साल 5 लाख जाब्स का क्रीएशन करेंगे और इससे हमारी इकोनामी में चेंज आ जायेगी । इसका इलाज यह है कि हर आदमी को इकोनामिक इम्पलायमेंट मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले ।

महात्मा गांधी ने भी बतलाया था कि काटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिये । प्रोफेसर गुन्नार जो अपने आपको सोशलिस्ट कहते हैं और वर्ल्ड फेम के इकोनामिस्ट हैं, उनको हिन्दुस्तान के सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं, उन्होंने भी कहा है कि अच्छा यही है कि काटेज इंडस्ट्रीज फार डिकेड चलें और साथ में बड़ी इंडस्ट्रीज भी चलती रहें । महात्मा जी ने भी कहा था कि जरूरत होने पर बड़ी इंडस्ट्री चले लेकिन साथ-साथ काटेज इंडस्ट्रीज भी चले । प्रोफेसर गुन्नार ने अपनी वाईफ के साथ दो-तीन जगह स्पीच दी क्लबों में, सेमिनार में और कहा कि हिन्दुस्तान में एक मर्ज है कि "हिन्दुस्तान नेगलेक्टेड गांधी"। पहल भी मैं कह चुका हूं और त्रिपाठी जी ने खड़े होकर कह दिया है कि काटेज इंडस्ट्री, स्माल स्केल इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री भी चले । कोई तो उसूल होना चाहिये । कहां पर बड़े स्केल की और कहां पर स्माल स्केल की इंडस्ट्री होनी चाहिये । लेकिन जो छोटी पर बन सकती है उसको बड़ी पर न बनाओ । गांधी जी का नाम लेते रह और फक्टरियां बराबर खोलते

[श्री चरण सिंह]

चले गये और उधर अनइम्पलायमेंट बढ़ता चला गया । आखिर इस पर विचार करना चाहिये । इस सिचुवेशन की सीरियसनैस के ऊपर कोई रियेलाइजेशन है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय, एक तो आपने यह मशीन लगाई । 6 महीने पहले मैंने अखबारों में पढ़ा कि सरकार दस हजार बेसिक स्कूल बनाने जा रही है, पता नहीं अब स्कीम है या नहीं । अब सारा रुपया उधर चला गया कैसे बनें ? आज एजूकेशन के हमारे यहां पांच मिनिस्टर्स हैं । बेसिक स्कूलों का कौन सा मिनिस्टर है । माननीय राजबिहारी सिंह जी हैं । माननीय त्रिपाठी जी को पता होगा कि वह स्कीम है या नहीं । लेकिन मैं इसे यही छोड़ देता हूं । प्रीफैब्रीकेटेड बिल्डिंग इन बेसिक स्कूलों की बनेंगी । इसके लिये 5 करोड़ रुपया रखा गया है । दस हजार स्कूलों की बिल्डिंग्स के लिये यह रुपया रखा गया है यानी एक बेसिक स्कूल की बिल्डिंग 5 हजार रुपये में बनेगी । प्री फैब्रीकेटेड बिल्डिंग की एक फैक्ट्री देहली में बन रही है और एक चंडीगढ़ में बन रही है । यह बिल्डिंग्स बनिस्बत हाथों से बनाने के कीमती पड़ेगी । क्या हमारे यहां लेबर डेफीसिट है । अगर हमारे यहां लेबर की कमी है तो बेशक आप मिकेनाइजेशन कीजिये । एक तरफ तो लोग खाली बैठेंगे और आप मिकेनाइजेशन खाली मैन्यूफैक्चरिंग का ही नहीं बल्कि सरविसेज का भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस का भी कर रहे हैं । क्या बात है, क्या हमारे यहां बढ़ई नहीं हैं, राज नहीं है, मजदूर नहीं हैं, अगर हैं तो फिर यह क्यों कर रहे हैं । वे भूखे रहते हैं और हमारी गवर्नमेंट उस पर कुछ विचार नहीं कर रही है । गवर्नमेंट मिकेनाइजेशन कर रही है और लोग भूखों मर रहे ह । हमारे यहां के लोगों ने ताज महल तक हाथों से बना दिया और बेसिक स्कूलों की बिल्डिंग्स हाथों से नहीं बन सकेगी ।

अभी मैंने ला ऐंड आर्डर के संबंध में डी0आई0जी0 और आई0जी0 का बयान पढ़ा है कि क्राइम सिचुयेशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है । आज का मैं पायनियर उठा लाया हूं । कल एक नौजवान को छुरा मार दिया गया है । एक सज्जन ज्ञानेन्द्र जी जो एक नौजवान हैं वे बैठे हुये थे और न मालूम कैसे उनके सामने जिक्र आ गया । उन्होंने कहा कि कल दो लाशें मिली हैं । एक तो डी0ए0वी0 कालेज के लेक्चरार की है और दूसरी किसी पढ़े लिखे आदमी की है । यह मुजफ्फरनगर का केस है । शामली में एक साहब टलीविजन देख रहे थे कि उनके यहां लोग घुस गये और उनका सामान लेकर चले गये । आजकल दिन दहाड़े कत्ल और रौबरीज हो रही हैं । यह मुमकिन नहीं हो सकता है और हर जगह पुलिस नहीं रह सकती है लेकिन आजकल बदमाश समझता है कि अगर वह पकड़ा गया तो उसको सजा नहीं मिलेगी । इसलिये वह बदमाशी करता है । यह इम्प्रेशन उन लोगों का हो गया है । क्यों हो गया है ? इसकी वजह है और मैं मुगालते की बात नहीं कहना चाहता हूं बल्कि सही बात कहना चाहता हूं कि बहुत से बदमाशों की सिफारिशें बड़े लोगों के द्वारा पुलिस में होती है । वह उन्हें छोड़ना पड़ता है । यह इसलिये होता है कि वह समझते हैं कि क्यों बदनामी लो और कोशिश करो, इसलिये यह ढील होती है । मेरठ में जो सीरियस क्राइम्स हुये हैं अभी इस पीरियड में उतने कभी नहीं हुए । हमारे हल्के में 5–7 साल में कभी 1 डकैती हो जाती थी, लेकिन अभी 2 पड़ चुकी हैं । उसको चेक करने का क्या हाल है, मैंने उसके संबंध में आई0 जी0 को लिखा तो 19 दिन के बाद उसका उत्तर उन्होंने अपने पी0ए0 से दिलाया । प्रमुख के कत्ल की धमकी दी जाती है और जिस तरह से खेखड़े में पुलिस वालों के सामने 3–4 घंटे तक डकैती पड़ी । एस0पी0 से बात हुई, मैंने कहा मैं उनसे बात नहीं करना चाहता । हमारे खेखड़े के पास के एक गांव समाज के प्रेसीडेंट थे 21 नवम्बर को उनके पीछे बदमाश दिन दहाड़े पड़े हुए थे वह भागते थे और वह रिपोर्ट लिखाते हैं कि फलां लोग हमें मारना चाहते हैं लेकिन कोई ऐक्शन नहीं हुआ । और उन्हीं लोगों ने उस शख्स का कत्ल दिनदहाड़े किया । उसके बाद भी यह डाका पड़ता है । मैंने एस0पी0 से पूछा कि यह सब-इन्सपेक्टर जो थे यह वही हैं

कि जिनके यहां वह रिपोर्ट लिखाई गई थी और जिन्होंने कोई ऐक्शन नहीं लिया, तो मालूम हुआ कि वही हैं । फिर मैंने उनसे कहा कि इतने दिन से तहकीकात हो रही है इस नतीजे पर पहुंचे या नहीं कि उनका हाथ था । उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई कि उनसे तहकीकात न कराई जाय । उनका कहना था कि रिपोर्ट की गई और कोई ऐक्शन नहीं हुआ और उसमें सब-इंसपेक्टर का हाथ था । यह सब हो रहा है, यही नही, न मालूम कितने किस्से हैं, कहां तक सुनाये जायं, एक जिले के ही सुनाऊंगा तो घंटों लग जायेंगे । 6 माह से यह सब हो रहा है और हालत यह है कि बसों और कार्स का अब पश्चिमी जिलों में कनवाय चलता है । हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, रुड़की, मुजफ्फरनगर या गाजियाबाद कहीं भी मेरठ से जायं तो सड़क पर पुलिस वाले गाड़ियों को रोकते हैं, बस और प्राइवेट कार कनवाय बनाकर भेजी जाती हैं और पुलिस साथ में चलती है, इस तरह से रास्ते में कभी एक घंटे कभी 2 घंटे रुकना पड़ता है । वहां कितनी बसें और गाड़ियां लुट चुकी हैं इसलिये यह इंतजाम किया गया है । अब तो यह एक प्रेक्टिस कहिये या नार्मल फीचर कहिये, हो गया है कि कनवाय चलते हैं । 1 दिन की या 15 दिन की बात हो तो दूसरी बात है । मैंने एस0पी0 से कहा कि इसका यह हल नहीं है कि आप हमेशा कनवाय ही चलाते रहें । इसके लिये आप 2–3 कंट्रोल पार्टी बनाइये जिसका प्रोग्राम किन्हीं बदमाशों को मालूम न हो, अगर इस तरह से स्कवैड उन का पीछा करेंगे तो कुछ दिन बाद वह गैंग खत्म हो जायंगे और कनवाय की जरूरत ही नहीं रहेगी । उन्होंने कहा कि आप की बात तो ठीक है और हमने इस संबंध में आई0जी0को लिखा है लेकिन 3–4 माह के बाद आज भी वही स्थिति है और यह एक नार्मल फीचर हो गया है कि कनवाय चलता है । बदमाशों को इस तरह से प्रशासन टेकिल नहीं कर पाता है और रोज कत्ल, डकैती खुले आम बिनदहाड़े बढ़ रहे हैं ।

एक डी0आई0 जी0 कहते हैं कि अब आंकड़े घट गये हैं क्राइम के । आंकड़ों की हालत यह है कि अंग्रेजों के जमाने में पुलिस विभाग की यह कोशिश रहती थी कि क्राइम के आंकड़े कम दिखायें जायं । आप अगर रिपोर्ट देते तो मालूम होगा कि जुर्म कम हो गये और उससे समझा जाता था कि क्राइम सीचुएशन में सुधार हो गया । वही हालत है कि जहां क्राइम कम दर्ज होते हैं समझा जाता है तरक्की हो गई बजाय इसके कि क्राइम जो होते हैं वह सब दर्ज हों और उनको वर्कआउट किया जाय । एक जगह तो यहां तक हुआ कि कहीं क्राइम कम दिखाये गये और उस का होम मिनिस्ट्री पर इतना इफेक्ट हुआ कि एक थाना ही एबालिश कर दिया गया जब कि वह फिर 6 माह के बाद कायम करना पड़ा । होते-होते इस हद तक हुआ कि सन् 18 से 20 तक जितनी क्राइम की संस्था थी वह 58–60 में कम हो गई । मैंने अपने जमाने में एक आर्डर दिया था कि हर क्राइम लिखा जाय चाहे उस पर तहकीकात हो या न हो । गवर्नमेंट का फर्ज है कि वह देखे कि क्राइम या रिपोर्ट लिखी जाती हैं या नहीं ।

लेकिन आज क्राइम को छुपाया जाता है, वह ठीक नहीं है। जनवरी या दिसम्बर में मैं जब गृह मंत्री हुआ तो पूरे सन् 1961 में दूने क्राइम हो गये । रिपोर्ट हो गयी । यह नहीं कि क्राइम बढ़ गये । मार्च, 1961 की बजट स्पीच को पढ़ कर देखें । उसमें है कि दियर इज ग्रेट इम्प्रूवमेंट और होम डिपार्टमेंट को कान्ग्रेचुलेट किया गया लेकिन उनकी तादाद दूनी हो गयी है ।

क्राइम रिपोर्ट कम हुयी लिहाजा इम्प्रूवमेंट हो गयी । 1918–20 में डेकोयटीज 4,325 थी लेकिन 1958–60 में यह संख्या 2,626 हुयी । आबादी यू0पी0 की सन् 1921 में 4 करोड़ 65 लाख थी । यह 6 करोड़ से ज्यादा 7 करोड़ के करीब हो गयी । 60 प्रतिशत आबादी ज्यादा बढ़ गयी और क्राइम कम हो गये सिवाय 2 के जो छिपाये नहीं जा सकते । रौबरी के 1918–20 में 2,722 केसेज थे जो 1958–60 में घटकर 1,523

[श्री चरण सिंह]

हो गये । मर्डर के केसेज 2,736 से बढ़कर 4,987 हो गये । ये केसेज छिपाये नहीं जा सकते । इसी प्रकार से रायट के केसेज 2,331 से बढ़कर 8,658 हो गये । वर्गलरी के 1918–20 में 1 लाख 69 हजार 333 केसेज थे जो 1958–60 में घटकर 47,883 अर्थात लगभग 48,000 रह गये । आर्डिनरी थैफ्ट के केसेज 95,968 से घटकर 1958–60 में 45,951 रह गये ।

फिर एस0पी0 और डी0आई0जी0 को आर्डर हुआ कि आप खुफिया तरीके से देखें कि थानों पर केसेज दर्ज करते हैं या नहीं, तो दून क्राइम हो गये । सिवाय रायटिंग और मर्डर के । जैसे ही मने 1962 में होम डिपार्टमेंट का कार्यभार छोड़ा फिर क्राइम घटने लगे । 1963 में, 1964 में, 1965 और 1966 में फिर घटे । 1967 में फिर संविद की सरकार आयी । 1969 में फिर घटे । 1970 में फिर बढ़े और अब फिर घट रहे हैं । फीगर्स ये नहीं बतलाते हैं, सही बात नहीं बतलाते हैं, फीगर्स से यह साबित नहीं होता है कि क्राइम कम हो गये । जैसे उनको इशारा किया जाता है वे कहते हैं कि काहे को फजीते में पड़ो । तो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और हरिजनों के साथ तो जो इस गवर्नमेंट में हुआ, 1946 के बाद पहली बात है नया फीचर, नया डेवलपमेंट नया तोफा माननीय त्रिपाठी जी की सरकार का है । श्री भटनागर ने एक आर्टिकिल लिखा है, दिनमान में भी सभी जिलों की जो स्थिति है, निकला है । मेरे पास दसियों मिसालें रखी हैं माननीय त्रिपाठी जी के जिलों में कितने जुल्म हुए हैं । धर्म तक त्यागने को तैयार हो गये । कहां क्या नहीं हुआ ? बांदा में क्या क्या हुआ ? बलिया में जब मैं गया हुआ था तो जो हरिजनों ने कहा, वह पेपर में भी आया है । यह सब हुआ । मैं तो बायस्ड आदमी हूं, विरोधी दल का होने के नाते गलत इत्तिला मिल गयी होगी लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया का क्या ख्याल है । ये लब्ज ह मैं सुनाये देता हूं "

"Offences against Harijans are rapidly increasing because the tormentors and crim nals know that nothing will happen to them. The union Deputy Minister for Home Affairs told the Lok Sabha on February 28, Last that the maximum number of cases relating to untouchability offences and harassment of Harijans were reported from)Uttar Pradesh viz 262, in 1972, 164 in 1971 and 94 in 1970"

164 हरिजनों के खिलाफ 71 में, और 72 में हुए 262, इन्होंने खुद बयान दिया । गवर्नमेंट आफ इंडिया से लोग आये । वे सब इस नतीजे पर पहुंचे कि 'हरिजन-द डु नाट फील सेक्योर्ड' क्या कारण है इसका । एक कारण इसमें हमारे त्रिपाठी जी का ख्याल है कि उनकी बिरादरी के अलावा और जो दूसरी बिरादरी के लोग हैं, उनको बराबरी का हक नहीं है । कान्स्टीट्यूशन में तो लिख दिया है, वह दूसरी बात है । तो जब आपका यह एटीट्यूड है तो बड़ी जाति वाले जो अपने आपको ऊंचा समझते हैं, उनमें भी यही इनफेक्शन हो गया है । तो इसका कारण यह है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि 20-22 सालों के बाद भी यह कास्ट फीलिंग क्या है। हमारे माननीय टंडन जी नोट कर रहे हैं ।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन––

मैं आपकी हर बात नोट कर रहा हूं और जवाब भी दूंगा.....

श्री चरण सिंह––

वह तो मुझे मालुम है आप जैसे जवाब देते हैं । तो मान्यवर, इनके दृष्टिकोण की वजह से–इनकी इनएफीसियेंसी की वजह से नहीं, क्योंकि वह तो सभी के प्रति है इनमें–यह है । जो आदमी कास्ट सिस्टम में विश्वास करता हो, छोटा-बड़ा समझता हो, वह सबको एक दृष्टि से देख ही नहीं सकता । उसका असर ऐडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ेगा ही । मेरी तो यही

रीडिंग है । आप दूसरी बात कोई बतावें तो वह दूसरी चीज है 22 साल के बाद इसका यही कारण है।

अब हरिजनों के लिये कहते है कि हाउस साइट दिला देंगे । यह कौन सा नया काम कर रहे हैं ? यह तो पहले ही कान्सालीडेशन आफ होल्डिंग ऐक्ट, जो हमने बनाया था, उसमें रूल है कि हरिजनों के लिये जमीन छोड़ी जाय । वही जमीन उनको मिल रही है । मैं जानता हूं कि जमीन उनको मिलना मुश्किल है । फिर आप क्रेडिट किस लिये ले रह हैं इसकी । आप कह रहे हैं कि मकान बनाने के लिये कर्ज और ग्रांट दे रहे हैं । और बिजलीकरण हो रहा है हरिजन बस्तियों का । उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय तिवारी जी से कहूंगा कि मकान का मिलना उनके लिये उतना जरूरी नहीं है, मकान तो वे गारे और छप्पर डालकर बना लेंगे । बिजली भी उनके लिये उतनी जरूरी नहीं है । उनके लिये जरूरत है प्रोडक्शन और इम्प्लायमेंट की । उसकी बाबत क्या किया ? कुछ नहीं । लेकिन हरिजनों की समस्या को हल करने का आज यही एक इलाज है । वह इलाज है काटेज इंडस्ट्री । इसके बारे में आपकी कैबिनेट विचार करे कि किस तरह से इसको करें । काटेज इंडस्ट्री पनप नहीं सकती जब तक गवर्नमेंट आफ इंडिया का इसमें एटीट्यूड नहीं बदलेगा । आप प्रोप्रोगेंडा कर लें । लेकिन रियल बेनीफिट इन गरीबों को होने वाला नहीं है।

अब मुसलमानों की बात है । इनके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है । फिरोजाबाद और वाराणसी में आप देख चुके हैं । रायट हो जाते हैं । लेकिन वहां आपस में हिन्दू-मुस्लिम कन्फ्रंटेशन नहीं था । पुलिस के जरिये हुआ तो कुछ हुआ । उसमें दूसरी बात तकलीफदेह है जो आपने फीगर्स छपाई है कि 23 आदमी वाराणसी में मरे और मैंने कहा था कि 48 मरे, जब कि मरे थे 57 । आप सी0आई0डी0 से इंक्वायरी करा रहे हैं । मालूम नहीं क्या हुई रिपोर्ट । मैंने कहा कि एक आदमी मर जाता है तो जुडीशल इन्क्वायरी हो जाती है और फैजाबाद में 55 आदमी मर गये और वाराणसी में 23 मरे तो क्यों नहीं जुडीशल इन्क्वायरी कराई, आप क्यों नहीं राजी हुए ? आपने कहा कि डिप्टी सेक्रेटरी, सेंटर के आये हैं और यहां से भी आपने एक आफीसर को भेज दिया इसके लिये, मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जुडीशल इन्क्वायरी क्यों नहीं कराई । ऐसी एक बात नहीं अनेकों बातें हैं ।

मुझे तो यह भी मालूम हुआ कि उर्दू का जो गजट निकलता था उसके पब्लिकेशन को भी आप बन्द करने जा रहे हैं । इसमें क्या हर्ज था, उनके लिये एक सेंटीमेंटल बात थी जहां गवर्नमेंट के और भी खर्च होते हैं, यह भी होता । अगर यह डिस्कन्टीन्यू हो गया है तो मैं यह चाहूंगा कि इस पर फिर से विचार किया जाय । इसी तरह से उर्दू अकादमी में आप जो पैसा रखते हैं वह कम हो जाता है ।

अब मैं आता हूं प्राब्लम आफ स्टूडेंट पर । मान्यवर, अगर पैदावार घट जाती है, तो अगले साल या 10 साल में बढ़ जायगी, एडमिनिस्ट्रेशन अगर खराब है किसी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की वजह से या आफीसर की वजह से, वह भी ठीक हो सकता है, लेकिन जिस कौम की एजूकेशन बिगड़ जाय, तो इससे बड़ी हानि और कोई नहीं हो सकती । आप अखबारों को उठाकर देख लें बराबर 2–3 सालों से बराबर यह खबरें मिलेंगी कि अपने गुरुजनों के प्रति बुरा व्यवहार, अपने वाइस चांसलर के प्रति, अपनी गवर्नमेंट के प्रति अपनी बहनों के प्रति जो साथ पढ़ती हैं, इन्वीजिलेटर्स के प्रति, खराब व्यवहार हुआ । मैंने जो किया वह यह कि कम्पलसरी यूनियन को समाप्त कर दी। यह नहीं कि सब लोगों से पैसा लिया जायेगा, जो बनाना चाहे वह बनाये । उसके बाद कुछ और संशोधन हुए वी0एन0 सिंह की गवर्नमेंट ने किये । उसमें उन्होंने फर्स्ट क्लास स्टूडेंट के लिये किया था जो पढ़ाई की ओर ध्यान देते थे । त्रिपाठी जी ने तो उसे कैंसिल ही कर दिया । यही नहीं त्रिपाठी

[श्री चरण सिंह—]

जो ने वह हर चीज मन्सूख की जो मैंने की। जिस अफसर के खिलाफ विजीलेंस कमीशन हो, सस्पेंड हो, उसके खिलाफ रिपोर्ट हो, उसको बहाल कर दिया। आई० जी० की 15 पेज की रिपोर्ट है, रिटिन डाकुमेंटरी एविडेंस सहित, एक डी० आई० जी० के खिलाफ, सस्पेंड होता है, आपने उसको फिर से बहाल कर दिया। एक आफीसर रिटायर होता है, रिटायर होने की एप्लीकेशन देता है, वह अपना सारा प्रावीडेंट फंड का पैसा ले लेता है, बिजलेंस की न्क्वायरी होती है, उसके 5–7 महीने 58 वर्ष में रह गये थे, आप उसको फिर से रख लेते हैं। मुझे यहां तक मालूम हुआ है कि उसकी एप्लीकेशन भी नहीं है कि 'आई वांट टु कम बैक'। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग डिस्मिस हो गये, जिन्होंने सुचेता जी को गालियां दी हजरतगंज के सेसन में संविद की गवर्नमेंट में मुझको गालियां दी, मिनिस्टर को गालियां दी, चीफ सेक्रेटरी को गालियां दी, उनके खिलाफ ऐक्शन लिया गया, उनको हाईकोर्ट में जाने का मौका भी मिला, सब कान्स्टीट्यूशनल प्रोसीजर उन्होंने एक्जास्ट कर लिये, उनको डिस्मिस कर दिया, और आपने उन्हें रिएप्वाइन्ट कर लिया 'विद रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट। दुनिया में कहीं भी मिसाल नहीं मिलेगी। वही बेसिस है एडमिनिस्ट्रेशन की और वही 'डिस्प्लन आफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसएपियर्ड"। जो लोग डिसिमिस हो गये उनको आपने रिएपाइन्ट कर दिया, क्या आपका कोई आफीसर ऐसे माहौल में काम कर सकता है? जो सबार्डीनट्स हैं उनकी सीधे चीफ मिनिस्टर तक पहुंच है। जिनको आपने इस तरह से एपाइंट किया वही आज आपकी जान को आये हुए हैं। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं। आखिर कोई मिसाल है निया में।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लड़कों के बारे में कह रहा था। पूछिये गार्जियन्स से, ये पूछिये टीचर्स से और पूछिये उधर के लोगों से अलग-अलग बुलाकर कि आपने जिस चीज को हमने किया उसको रद्द कर दिया तो उससे कोई फायदा हुआ एजूकशन को। और क्या इन लड़कों की जिन्दगी बेहतर हुई। आज का ही अखबार है। इसमें लिखा है स्टुडेंट्स अगेन डिस्टर्ब क्लासेज इन इलाहाबाद। क्या यह लड़के आगे चलकर मुल्क को चलायेंगे? यह शिक्षा हासिल नहीं करेंगे, अपने मां-बाप का पैसा खर्च करेंगे और स तरह से इतने बड़े सूबे की जिन्दगी बिगड़ जायगी। अब रह गयी वाराणसी जिले की बात। आपका बर्ताव ऐसा हो रहा है कि आप यू०पी० के चीफ मिनिस्टर नहीं, केवल वाराणसी के ही चीफ मिनिस्टर हों और वहां भी केवल चंदौली के। मुझे तो ज्यादा नहीं मालूम। लेकिन 17-18 को जो काम किये हैं उन्हें सुनाये देता हूं। आपने बनारस में पांच सौ से एक हजार बैड्स के अस्पताल का उद्घाटन किया। और जगह क्यों नहीं किया। वहां तो आलरेडी अस्पताल है। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का है, शायद रामकृष्ण मिशन का भी है। जहां आबादी के लिहाज से मेडिकल एड कम है वहां करते तो एक बात समझ में आती। बरेली या फैजाबाद में करते। इतना ही नहीं, यह भी एनाउन्स कर दिया"

Another Medical College proposed and a second mental hospital proposed For God sake, why?

श्री मोहम्मद असरार अहमद(जिला बदायूं)—

वहां मेंटल हास्पिटल की जरूरत है।

श्री चरण सिंह—

मैं ऐसी बात कहने वाला नहीं हूं।

एक सदस्य—

मेरठ में भी जरूरत होगी।

श्री चरण सिंह---

डा0 राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि सबसे पहले यूनीवर्सिटी मेरठ में खुले। लेकिन गोरखपुर में खुली। हमने ऐतराज नहीं किया। उसके बाद मेरठ का नम्बर आया। आपने भी क्या जवाब दिया। वल्लाह, मैं मेरठ की बात नहीं करता। बरेली में खुले, फैजाबाद में खुले, देहरादून में खुले। जरूरत तो हर जगह है। आपके लिये सभी जगह एकसा है। लेकिन जहां आलरेडी फैसीलिटीज हैं वहां दूसरा मेडिकल कालेज खोलने जा रहे हैं। बनारस में तो बनारस हिन्दू यनिवर्सिटी का है। इसी तरह से दूसरा सरकिट हाउस बना रहे है। वहां आलरडी सरकिट हाउस है। पी0 डब्लू0 डी0 का और शायद इरीगेशन का इंस्पेक्शन हाउस मौजूद है। इसके अलावा वहां महाराजा बनारस का भी है जिसमें लोग ठहरते हैं। दूसरे सरकिट हाउस का पत्थर पंडित जी ने जी ने रख दिया। बाद में आने वाली औलाद पढ़ेगी कि यह पत्थर पंडित कमलापति द्वारा रखा गया। इसी तरह से तीन हास्पिटल्स 24–24 बैड्स के चंदौली में कायम कर दिये। उपाध्यक्ष महोदय, लाइट तो ऊपर होनी चाहिए, झुक कर बोलना पड़ता है।

इस अखबार में लिखा है :---

'वाराणसी 17 फरवरी---उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी ने आज वाराणसी जिले के विभिन्न भागों में 3 करोड़ 67 लाख रुपय की 7 योजनाओं का कार्य आरम्भ किया और अमड़ा तथा सयदराजा में नलकूप का उद्घाटन किया।'

आप कहते है कि आपके पास वक्त नहीं है। ट्यूबवैल का उद्घाटन चीफ मिनिस्टर करेगा। वहां भी संगमरमर का पत्थर लग गया होगा त्रिपाठी जी।

आगे लिखा है 'मुख्य मंत्री ने चन्दौली क्षेत्र के लगभग 25 टेस्टवर्क देखे।' ठीक है निरीक्षण किया जिले में।

'आपने यहां से लगभग पचास मील दूर गाजीपुर जिले तथा बिहार की सीमा पर स्थित ओयर चक में 24 शय्याओं के जन चिकित्सालय का शिलान्यास किया जिस पर लगभग आठ लाख रुपया व्यय होगा। अमेड़ा में जिस 24 शैय्या के अस्पताल का शिलान्यास 27 मई, 1972 को हुआ था उसका शुभारम्भ किया गया।'

तो फाउन्डेशन भी रखेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। 8 लाख रुपये की योजना है और पौने चार लाख रुपये खर्च हो चुके ह। 22 कमरे बन कर तैयार हो चुके हैं। मामूली अस्पताल नहीं है 2 वार्ड पुरुषों के लिए और 2 महिलाओं के लिए हैं। डाक्टर ने कार्य आरम्भ कर दिया है। उनका कार्य मुख्य मंत्री द्वारा प्रशंसित हुआ। यहां से चल कर बरहनी में मुख्य मंत्री जी ने प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र के भवन का शिलान्यास किया जिस पर लगभग एक लाख रुपया व्यय होगा। चन्दौली में आकर पंडित जी ने 100 शैय्याओं के चिकित्सालय का शिलान्यास किया।

श्री भानु प्रताप सिंह---

बीमार ज्यादा रहते हैं।

श्री चरण सिंह---

परमात्मा करे जल्दी अच्छे हो जाएं।

27 लाख रुपये की योजना है जो 48 वार्ड महिला, 48 वार्ड पुरुष और 4 आइसोलेशन वार्ड्स के लिए है।

[श्री चरण सिंह---]

उपाध्यक्ष महोदय, सवाल चिकित्सालयों और चिकित्सा केन्द्रों का नहीं है बल्कि सवाल तो यह है कि आप चीफ मिनिस्टर सारे सूबे के हैं। आप सिर्फ कांग्रेस के लोगों को वोट देने वालों के ही चीफ मिनिस्टर नहीं हैं बल्कि कांग्रेस के विरुद्ध वोट देने वालों के भी हैं। आप को तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सबको एक दृष्टि से देखना है। पहली बात तो मैं कहना नहीं चाहता चन्दौली की बड़ी खुशकिस्मती है। आप मुझसे चेंज कर लीजिए। आप देखिएगा कि वहां क्या--क्या हो रहा है और हमारे यहां क्या हुआ है। आप मुझे वहां से जितवा दीजिए ताकि मेरे जिले और तहसील का भी भाग्य खुल जाए। कमाल हो गया साहब। क्या और कोई तहसील और कांस्टीटुएन्सी नहीं है ?

It should have been thought of thousand times before launching schemes in your own tahsil or constituency.

हजारों बार सोचते। हम जैसे लोग तो मूर्ख होते हैं। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि त्रिपाठी जी चीफ मिनिस्टर हैं या जागीरदार हैं। पहले बड़े-बड़े जागीरदार होते थे। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके साहबजादे जब जाते हैं तो अफसरान हाजिरी देते हैं। मुझे बताया गया कि नौचन्दी मेले में जब आपके साहब जादे गये थे तो डी0 आई0 जी0 और कमिश्नर साथ थे। मुझे मालूम हुआ है कि छोटे मोटे मिनिस्टर्स को भी इस तरह से रिसीव नहीं किया जाता है जैसे कि उनको किया जाता है। एक मील पहले से पुलिस लग जाती है और सर्किट हाउस में ठहरते हैं। मुझे यही मालूम है कि जब आप नहीं रहते हैं तब भी पुलिस गार्ड रोज रात को जाता है। कोई विशेष बात हो तो आप आर्डर दे दें, ठीक है, लेकिन आपके लड़के को वही हक है जो छोटे से छोटे आदमी के लड़कों को है। यह आपके लड़के की खुशकिस्मती है उसका आप जैसा बाप है लेकिन यह डेमोक्रेसी है। आपके चीफ मिनिस्टर होने की वजह से उसको जो एक आरडीनरी सिटीजन को अधिकार है उससे अधिक नहीं हो सकता है। मैंने यह छोटी बात कह दी लेकिन इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं वही बात कह रहा हूं जिसे लोग कहते हैं और आपके नाम को यह शोभा नहीं देता है।

मैं 25 तारीख को इटावा गया था। लौटते समय मैंने एक साइन पोस्ट देखा। उसमें लिखा था, "प्रधान मंत्री, इन्दिरा गांधी, द्वारा चालित त्वरित कार्यक्रम।" मैंने मतलब पूछा तो पता लगा कि इसका मतलब क्रेस प्रोग्राम से है जो कि इन्दिरा गांधी के डायरेक्शन से लागू किया गया है। ठीक है यह प्रधान मंत्री का विचार है लेकिन वह सरकारी प्रोग्राम है। सारी चीजें चीफ मिनिस्टर्स तय करते हैं लेकिन उनका नाम तो नहीं लिखा जाता है। मुझे इसी तरह का साइन पोस्ट, सीतापुर में भी मिला। क्या यह प्रोपेगेन्डा नहीं है ? उनके नाम की क्या जरूरत है ? मैं तो कहता हूं कि प्रधान मंत्री भी नहीं होना चाहिये। सरकारी आदेश तो सभी प्रेसीडेन्ट और गवर्नर के नाम से होते हैं। प्रधान मंत्री और चीफ मिनिस्टर का नाम तो उसमें नहीं आता है। वहां कांग्रेस की लीडर भी हैं। तो उनका इसमें नाम रखना तो प्रचार करना है। यह ठीक नहीं है। आपके नोटिस में यह बात नहीं आई होगी लेकिन अब आप इस पर अवश्य विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब राज्य कर्मचारियों की इन्टेग्रिटी, इफीशेन्सी और अनुशासनहीनता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं कितना ही कहूं वह नाकाफी होगा। मैं सभी चीजें नहीं कहूगा केवल आम बातों पर कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, पहले मैं कह चुका हूं कि सरकार में कुछ मम्बरान ह जिनके लिये यह कहा जाता है कि वहां पैसा आफिसर्स से लेते हैं। बात गलत होगी लकिन क्योंकि आपन हमारा प्रपोजल नहीं माना है कि हाई कोर्ट के जज से इन्क्वायरी करा ली जाय, तो मुझे मानना पड़ता है कि उसमें कुछ सत्य है। अगर ऐसा है तो प्रशासन कैसे चलेगा। उनको लीडरशिप कौन प्रोवाइड करेगा और अगर मिनिस्टर स्वयं ईमानदार नहीं होगा तो

अधिकारी और कर्मचारी कैसे होगा । अब इस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, जितनी इसकी व्याख्या की जाय वह थोड़ी है ।

ट्रांसफर्स आप करते है तो डिपार्टमेंटल हैड्स और सुपीरियर आफिसर्स से बिना पूछे कर देते हैं । कोई कांग्रेस-मैन या गैर-कांग्रेस मैन आपका जानने वाला हुआ, उसने शिकायत की तो ट्रांस्फर कर दिया । और दूसरा कोई आ गया तो कैंसिल । न पहले डिपार्टमेंटल हैड से पूछा , न बाद में पूछा तो कैसे डिसिप्लिन रहेगा ? दुनियां में कहीं ऐसा होता है ? अगर शिकायत करने वाले की बात को आप सही समझते हैं तब भी मोटे तौर से लिख दो कि हमारे पास शिकायत आई है , देख लो । जब वह आप पर ट्रस्ट करेगा तो जरूर ऐक्शन लेगा और गलत बात होगी तो लिख देगा । हर नीचे का सुबार्डिनेट आफिसर अगर यहां आ सकता है तो फिर वह नहीं चल सकता मामला । मुझे तो एक अफसर ने बताया कि एक कर्मचारी के 13 ट्रांस्फर हुए । ट्रांस्फर हुआ, फिर कैंसिल । फिर हुआ, फिर कैंसिल फिर ट्रांस्फर हुआ, ऐसे ही 13 बार हुआ । 3–4 तो नाम बताये थे मैंने । तो ऐडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से नहीं चलना है ।

तीसरी बात यह देखने में आयी कि अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़े ईमानदार भी अफसर नहीं हैं, इनएफिश्यैंट हैं उनको आप प्रिफरैंस देते हैं । ईमानदार आदमी के प्रति ऐक्शन इस तरह का आपका होता है कि वह आपको नापसंद है । फिर कास्ट कंसीडरेशंस भी रहते हैं । इस प्रकार की बहुत लोगों को और अफसरान को और राज्य कर्मचारियों को शिकायत है । पुलिस में जो आपने पोस्टिंग्स, ट्रांस्फर्स और प्रोमोशंस किये हैं उसके बारे में किसी निष्पक्ष आदमी से पूछिये कि किस खयाल से किये गये और क्या उससे एफिश्यैंसी, इम्पार्श्यलिटी और इंटिग्रिटी पुलिस के मुहकमे में घटेगी या बढ़ेगी तो पता चल जायगा ।

चौथी बात "इंटरफियरैंस बाई कांग्रेसमैन ऐट एवरी लेविल" । मैं नाम नहीं लेना चाहता । एक जिले के एक सुपरिटेंडेंट पुलिस के पास तीन कांग्रेसमेन पहुंच गये । एक बी० के० डी० का भी उनसे मिलना चाहता था, इत्तफाक से उसको भी उनके सामने ही बुला लिया । एक साहब ने कहा कि इसको एस० ओ० बना दिया जाय, उन्होंने कहा कि नहीं बनाऊंगा । तब उन्होंने एक मिनिस्टर का नाम ले लिया, तो भी सुपरिटेंडेंट ने कहा कि अब भी नहीं बना सकता, चाहे कोई क्यों न हों क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस तरह का अफसर है, यह मेरी जिम्मेदारी है, नहीं बनाऊंगा । उन्होंने कहा कि नहीं बनाओगे तो यह हो जायगा । तो उन्होंने जबाव दिया कि कुछ करा लीजिये, मैं तो अपना ट्रांस्फर करा लूंगा यहां से । और भी कुछ बातें कहीं जो मैं कहना नहीं चाहता । कौन होते है कांग्रेसमैन एस० पी० से कहने वाले कि फलां एस० ओ० हो, फलां न हो । वह तो किसी के अचीवमेंट्स को और रेकार्डस को नहीं जानते, आफिसर्स ही जान सकते हैं । कुछ आफिसर्स ने कहा कि हमारे बस का डिस्ट्रिक्ट में काम करना नहीं है, हम सैक्रेटेरियट में आना चाहते हैं क्योंकि वहां उस तरह का इंटरफियरैंस तो नहीं होगा ।

पांचवीं बात यह कहता हूं कि बहुत सी दफा जो आप लोगों के आर्डर्स होते हैं मिनिस्टरों के, वह उस सब्जेक्ट को या कैस की मेरिट से ज्यादा वास्ता नहीं रखते और अफसर के पास जो जवाब का आर्डर जाता है तो वह अपना मत्था ठोकता है कि क्या करूं ? और ऐसे भी अफसर हैं कि उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे आर्डर्स कैरी-आउट नहीं करेंगे । अभी चार दिन हुए, एक आदमी मिनिस्टर साहब का आर्डर ले गया सेक्रेटरी के पास । उसने उनको देख कर सौ सुनाई और कहा कि नहीं करूंगा । वह मिस्टिर के पास गया और कहा कि यह हुआ तो मिनिस्टर ने कहा कि मैंने तो लिख कर दे दिया, और मैं क्या करूं ? कर लीजिये बात ! कहते हैं मैं क्या करूं ? वह आया मेरे पास ! मैंने कहा कि मैं तो किसी भी सूरत में कुछ नहीं कर सकता और अगर तुम इससे पहले आते कुछ न करके, तो शायद मैं सैक्रेटरी को लिख देता कि इस पर विचार कर लो, तो मुमकिन है कि कुछ हो जाता । लेकिन जब मिनिस्टर को 10 सुनायीं और तुम को 10 सुनायीं तो तुम अब बैठा घर । अफसरान के मन में आपके

[श्री चरण सिंह]

प्रति आदर क्या रहेगा ? और केवल पोलिटिकल अथारिटी से कोई गवर्नमेंट नहीं चलती है, मोरल अथारिटी चाहिये मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का काम लेने के लिये अफसरों से जबकि वह इन्टेलेक्चुअली किसी बात में भी आप से कम नहीं हैं। एनएफिशेन्सी का एक बड़ा कारण यह है कि सात बड़े महकमे त्रिपाठी जी ने अपने हाथ में ले रखे हैं हैं, वैसे तो 11 है। अब 7 महकमों का काम कैसे देखते होंगे ? काम करते हैं राधाकृष्ण गोस्वामी। और उनकी बड़ी खुशकिस्मती है कि न मालूम कितने महकमों के वह स्टेट मिनिस्टर हैं---एजूकेशन के भी, पावर के भी, होम के भी। अब इनमें से जिस काम के लायक आप समझते हों उसका फुल पलेज्ड मिनिस्टर उनको बना दीजिये। कुछ स्टेट मिनिस्टर तो ऐसे ह जिनके पास कुछ काम ही नहीं है। दे आर सिम्पली कूलिंग देयर हील्स। गोस्वामी जी, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, आपका कैबिनेट मिनिस्टर बनाने की सिफारिश कर रहा हूं। तो आप जरा देखिये कि त्रिपाठी जी के पास कितने महकमे हैं। सामान्य प्रशासन, गृह, उद्योग, चीनी मिलें, होम गार्ड, शिक्षा असल-- में 5 तो इसकी ब्रांचेज हैं, नियोजन, क्षेत्रीय विकास, श्रम। इतना उलझा हुआ मामला है श्रम का कि मैं तो इसको अकेले भी तैयार नहीं था लेने को। और गन्ना विकास। ये 11 विभाग हैं। इनमें से 7 मेजर हैं। कौन आदमी कर सकता है ? स्टेट इतनी बड़ी है कि एक आदमी एक महकमे के साथ पूरी जस्टिस नहीं कर सकता और अगर मैं 54 जिलों के नाम गिनवाऊं तो बहुत से मिनिस्टर फेल हो जायंगे। तो इनएफिशेन्सी का एक यह कारण है। इस पर विचार करना चाहिये आपको। स्टेट मिनिस्टर्स को पावर दीजिये, अपने पास थोड़े रखिये। आपकी बीमारी की वजह से मामला इतना उलझा नहीं है बल्कि आप ओवरबर्डेन्ड हैं।

इन्डिसिप्लिन में आपने प्रीमियम तो तभी दे दिया जबकि उन लोगों का रिएप्वाइन्मेंट किया। स्ट्राइक चली तो हर तरफ स्ट्राइक। अगर मैं कहूं कि गिना दो कि कितने डिपार्टमेंट वालों ने धमकी दे रखी है या कर रहे हैं स्ट्राइक तो आप नाम नहीं बता सकते हैं। अब तो यह कहना होगा कि फलां डिपार्टमेंट के आदमी स्ट्राइक पर नहीं हैं। और तो और, वकील स्ट्राइक पर हैं। और उनका कहना यह है कि हमसे वायदा कर लिया था। वकील जो बड़ा कंजर्वेटिव होता है, मैं भी वकील रहा हूं थोड़ा सा इस लिये कंजर्वेटिव हूं, रिऐक्शनरी हूं वह भी स्ट्राइक पर है। गवर्नमेंट सर्वेन्ट को स्ट्राइक नहीं करना चाहिये। ट्रांसपोर्ट में जो स्ट्राइक हुई है वह उन्होंने की है जिन पर मुकदमे चल रहे थे जो वापस ले लिये, करोड़ों का नुक्सान उन्होंने किया था। आज वही लीडर हैं। यह स्थिति तो आपने खुद पैदा की है। जब आप पावर में नहीं थे तो आपका काम था स्ट्राइक को फोस्टर करना और आज जब पावर में हैं तो स्ट्राइक को हैंडिल करना नहीं जानते। व्हाट नानसेन्स ? क्या मतलब हुआ इसका ? जब तक स्ट्राइक वापस नहीं लोगे बात नहीं करेंगे, यह कहने से क्या मतलब है आपका ? इसका क्या यह अर्थ नहीं है कि स्ट्राइक वापस लेने पर कुछ तो मांगे आप मान ही लेंगे ? मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से सीचुएशन खराब होती जा रही है हो सकता है मेरा विश्लेषण गलत हो। मगर यह सही है कि आज सारा काम ठप्प हो रहा है।

आपने खुद यह माना है कि इन राज्य कर्मचारियों वगैरह को यदि इनके वेतन और भत्तों आदि में इजाफा करके पूरा पैसा दे दिया जाय तो विकास के कार्यों के लिये पैसा नहीं बचेगा। मैं भी यही कह रहा आ रहा हूं। मगर एक ओर आप कहते यह है, मगर दूसरी तरफ आपने यह 74 करोड़ रुपया दे भी दिया। फिर विकास के कामों के लिये रूपया बचेगा कहां से ? एक तरफ आप कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ आप कुछ करते हैं।

बिजली वालों की स्ट्राइक हुई। बहुगणा जी जलूस का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने कहा स्ट्राइक करो। क्या इस तरह से सूबे और मुल्क की सरकारें चल सकती हैं ? इन सबकी

जड़ में एक चीज है और वह यह है कि हमारे बहुत से मिनिस्टरों की दक्षता, ज्ञान और इन्टेग्रिटी की कमी। इसके लिये मैं एक मिसाल दे रहा हूं।

6 जून के नेशनल हेराल्ड में एक यह खबर छपी थी--"यू० पी० गवर्नमेन्ट जुबली गिफ्ट"। इसमें यह छपा है कि यह सरकार हर लैंडलेस हरिजन को एक दूध देने वाला जानवर देगी। 15 अगस्त को 25 वर्ष स्वतंत्रता के पूरे होने वाले थे इसलिये यह निश्चय सरकार का छपा था कि सरकार यह करने वाली है। अनेक बार इसको रिपीट भी किया गया। अब यह चीज कैबिनेट में जरूर डिसकस हुई होगी और पास हुई होगी। मैं कैबिनेट के लोगों से, माननीय त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं कि आपके यहां कितने लैंडलेस हरिजन हैं? क्या हर एक को या हर परिवार को एक एक गाय या भैंस देने का डिसीशन है? अगर एक परिवार को देने का डिसीशन है, तो प्रदेश भर में कितने ऐसे परिवार हैं? फिर हर एक को हरियाणा फर्स्ट क्लास गाय देंगे। आपके यहां कितनी ऐसी गायें हैं? शायद एक परसेंट हैं। फिर आप कहां से इनको लाओगे? खरीदोगे, या क्या करोगे? क्या आप की डेरी म इतने जानवर हैं? अब इनको दोगे तो क्या मुफ्त दोगे? वे तो बहुत कीमती आते हैं, हजारों के आते हैं। अब फिर वह गरीब आदमी जो है, वह उन्हें दाना और चने का बिनौला वगैरह कैसे कहां से खिला पाएगा। एक सवाल है कि वह मर गये तो फिर क्या दूसरे दोगे? इस तरह से 6 महीने में फिर दोगे? तो क्या मजाक बना रखा है। इस तरह से क्या वोट मिल सकते हैं? यह तो आपको एलेक्शन से दो महिने पहले कहने की बात थी। एक बार कोई गल्ती से निकाल देता है तो वह दूसरी बात है, लेकिन वह प्रस्ताव तो कैबिनेट से तय किया हुआ होगा। आप बताएं कि यह कैबिनेट का फैसला है या मिनिस्टर का। और यदि मिनिस्टर का है, उसने इतना गलत और अनप्रेक्टिबेल स्टेटमेंट दिया है तो क्या मुख्य मंत्री ने उसे बुला कर पूछा है कि क्या कोई ऐसी स्कीम हो सकती है, जिसमें इस तरह से हर हरिजन को गाय-भैंस दिये जा सकें। जब सब आदमियों को आपने अपने चारों तरफ सारी प्राब्लम्स को समझने वाले इकट्ठा कर लिये हैं तो फिर कहना ही क्या है। तो फिर बदल जाती है गवर्नमेंट।

अब करप्शन के बारे में आता हूं। इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा सिवाय उसके जो पेश्तर कह चुका। कुछ लोगों के बारे में खयाल है कि वह पैसा लेते हैं। वह बुरा खयाल है। मैं भी चाहता हूं कि वह सच न हो। हमें भी शर्म आती है। वह कहते हैं कि गलत बात है, मैं मुखालिफ पार्टी वाले हमारी कुर्सी की तरफ देख रहे हैं इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मान लो गलत है और आप यकीन करते हैं कि वह गलत है, लेकिन चरण सिंह, जायसवाल और भानुप्रताप जैसे तमाम लोग कहते हैं और उसे बार-बार कहते हैं और जब हम लोग कहते हैं तो कुछ लोग विश्वास भी कर रहे हैं, तो आपको इसे अवश्य सीरियसली लेना चाहिये।

श्री अनन्त राम जायसवाल--

खुद कांग्रेस वाले भी कहते हैं, जो इनके साथ बैठे हैं।

श्री चरण सिंह--

इसलिए, फार दि सेक आफ गुड नेम आफ योर आर्गनाइजेशन यू हैव टू डू दि इंक्वायरी। इस सम्बन्ध में, करप्शन के सम्बन्ध में आपके सामने श्री चैथम, जो कि एल्डर पिट के नाम से भी जाना जाता है और जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, उसकी कहीं कुछ लाइंस आपके सामने रखना चाहता हूं :--

"When the people complain, they must, either be right or in error. If they be right, we are in duty bound to inquire into the conduct of the Ministers and to punish those who appear to have beenmost guilty

[श्री चरण सिंह---]

If they be in error, we ought still to enquire into the conduct of our Ministers in order to convince the people they have been misled."

अर्थात् जब जनता का कोई आदमी कोई शिकायत करे तो वह गलत हो सकती है या सही हो सकती है। उसकी जांच करानी चाहिए। यदि सही हो तो मंत्री के चरित्र की जांच करनी चाहिए और उसे सजा दी जानी चाहिए, जो गिल्टी सिद्ध हो। यदि जांच के पश्चात शिकायत गलत पाई जाय तब भी मिनिस्टर की जांच होनी चाहिए और जनता को समझाना चाहिए कि तुम इतने गलत थे, तुमको गलत फहमी थी। यही बात मैं पहले कह रहा था, जांच के लिए हाई कोर्ट के जज को तय कर दें, मंत्री गिल्टी पाया जाए तो उसे सजा दो कांग्रेस को चार चांद लग जाएंगे और यदि सिद्ध हो जाएं कि हम लोग गलत काम कर रहे थे, गलत कर रहे थे, तो भी आपके चार चांद लग जाएंगे। यह तो दोनों तरफ से आपके हाथ में लड्डू हैं। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर जी बंशीलाल के बारे में कह रही हैं। बड़े सीरियस चार्जेज हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कहे गये है, लेकिन कुछ नहीं। आप उसमें स्वयं एक्यूस्ड है, तो क्या आप अपने मामले में स्वयं जांच कर लेंगे ? लेकिन नहीं यही आप कर रही हैं, आप लोग सब वही कर रहे हैं।

ठीक है, इस समय आप पावर में है जो करें सो ठीक है। जो हमारे दोस्त जायसवाल जी अभी कह रहे थे। 65 कांग्रेसमैन सितम्बर में इंदिरा जी से मिले थे। क्या कहा उन्होंने कुछ शिकायत की होगी। हमें नहीं मालूम। दूसरे रमेन्द्र वर्मा आपके सेक्रेटरी हैं आपके खिलाफ बयान दे चके हैं। तीसरी बात यह है कि 40 लोग अभी इकट्ठे हुए, अगर्चे एक साहब ने इनकार कर दिया, लेकिन हमने अखबारों में यही पढ़ा कि इकट्ठे हुए खन्ना साहब के मकान पर। अब एक खबर कल निकली है कि 100 आदमी उपाध्याय जी ने इकट्ठा कर लिया है 22 तारीख को मिलने के लिए। तो उसका कारण कुछ है। मेक हेस्ट टू क्लियर दि गुड नेम आफ योर पार्टी ऐंड आफ योर मिनिस्टर्स।

मैंने बहुत समय लिया। बहुत कोशिश की बात अनपार्लियामेंटरी कुछ न कहूं। गलत, जानबूझ कर कहा नहीं होगा। अगर हो गया होगा तो मैं गलती मान लूंगा। हो सकता है कि फिर भी किसी साहब को तकलीफ हुई हो। मैं माफी चाहता हूं। आई हैव सिम्प्ली डन माई ड्यूटी। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या इस प्रकार का स्वराज्य था जिसके लिए अंग्रेजों के जमाने में हमने काम किया था। इज इट दिस काइंड आफ स्वराज्य वी हैड बारगेंड। लाखों लोगों ने अपनी जिन्दगी लगा दी, मैंने बहुत थोड़ा काम किया। सैकड़ों वर्ष के बाद देश आजाद हुआ। इस तरह की गवर्नमेंट हमें यहां मिली। इसके लिए मुझको और मेरे साथियों को बहुत अफसोस है। इन शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं अपने दोस्तों से फिर माफी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय रियासत हुसैन।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

उपाध्यक्ष जी, माननीय टंडन जी बोलेंगे। जवाब अच्छा मिलेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, फरमाया है टंडन साहब के लिए

(श्री पुरुषोत्तम दास टंडन बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री उपाध्यक्ष---

उनको बुला चका हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

फरमायशी चले गये ।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, टंडन जी को सुनना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

उनको मौका दिया है । अगर यह न चाहें तभी हो सकता है ।

(श्री रियासत हुसैन बैठ गये ।)

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

आपने पहले उन्हें बुलाया था । तो पानी रखवा दीजिये ।

एक सदस्य---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । पानी का प्रबन्ध कर दिया जाय ।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

माननीय सभापति जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं . . . .

श्री नित्यानन्द स्वामी---

उपाध्यक्ष जी, जरा आपको बताइये, यहां सभापति नहीं होते ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष---

बात यह है कि काउंसिल में कहने के अभ्यस्त हैं । इस लिए निकल गया ।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मुखालिफ लोगों ने जो बात कही, मैं उसका आदर करता हूं । अगर सुनने की इच्छा है तो मैं. . . . .

श्री अनन्तराम जायसाल---

फरमायश की . . . .

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

आपकी फरमायश को हमेशा मानता हूं । अपने फर्ज को अदा करना चाहता हूं । मैं आपके आदेश का पालन कर रहा हूं (व्यवधान) आप मुझे ध्यान पूर्वक सुन लें । जो बातें माननीय चरण सिंह जी ने कही हैं उनका जवाब आप शान्तिपूर्वक सुनें । शोरगुल होता है तो बड़ी मुश्किल होगी । शोर करने से काम बनेगा नहीं । (व्यवधान) माननीय चरण सिंह जी ने कहा कि क्या मुख्य मंत्री ने कभी यह देखा है कि जो बड़े बड़े बंगले तथा महल हैं उनके पीछे कितनी डर्ट तथा फिल्थ है । आपने भी देखी है तथा मैंने भी देखी है । लेकिन मुझे एक बात का अन्दाजा नहीं है कि माननीय चरण सिंह के नेतृत्व तथा उनकी स्कीमों में कितनी हेटरेड तथा हिपोक्रेसी भरी होती है । (व्यवधान) चौधरी साहब ने जो कुछ भी कहा उसे सारे सदन ने शान्ति से सुना और मैं अपोजीशन के आर्डर पर बोल रहा हूं और मैं उनका आदेश मान रहा हूं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

आप तो चोर दरवाजे से आये हैं। पानी पी पीकर बोलते हैं।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

आप सुनेंगे तभी मैं अपनी बात सफाई से कह सकूंगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

आप बजट पर बोलिये।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

इस तरह से शोरगुल किया जाय और दूसरों की बात को न सुना जाय यह कहां तक उचित है। माननीय चरण सिंह जी ने कुछ तवारीख की चर्चा की होगी उनकी नालेज कोआपरेटिव फार्मिग के बारे में ज्यादा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वह चार्ज लगायें तो नाइदर एक्सप्लेन नार कम्प्लेन। चौधरी साहब जब चार्ज लगाते हैं तो उस पर एक्स्प्लेन करना या कम्पलेन करना गैर मुनासिब होता है। कुछ लोगों का पेशा होता है हमेशा चार्ज लगाते रहना।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

आप बजट पर नहीं बोलेंगे। चौधरी आपको खटकते हैं।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

चौधरी साहब ने जो तर्क दिये उनके हर तर्क का उत्तर दूंगा। आप इत्तिफाक करें तो मानियेगा और नहीं मानेंगे तो मेरी बदनसीबी है। लेकिन मुझे कहने का मौका तो दीजिये।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

माननीय सदस्य चौधरी चरण सिंह पर बोल रहे हैं अथवा बजट पर बोल रहे हैं?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

टंडन जी के बाद हम असरार साहब को सुनना चाहेंगे।

श्री परुषोत्तम दास टंडन---

चौधरी साहब ने हाई कोर्ट के जज की मांग का चार्ज लगाया और कहा कि उसका जवाब क्यों नहीं दिया और वहां पर इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? सीधी सी बात है अगर माननीय चरण सिंह जी के लगाये हुए चार्जेज के मुताबिक इंक्वायरी करना शुरू कर दें तो सरकार के पास दूसरा कोई काम नहीं रहेगा। (व्यवधान) उपाध्यक्ष जी इनको बिठाइये ताकि मुझे बोलने दिया जाय। मानतीय चरण सिंह जी, जिस तरह से शिकायतें करते हैं उनकी जांच कराते रहें तो फिर तो और गवर्नमेंट का कोई काम रह ही न जावेगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

जरा-जरा से मामले को लेकर तो इन्क्वायरी होवे और सत्तर-सत्तर लोग मर जावें तो इनके कान पर जूं न रेंगे तो आज उनका खून चीख रहा है पुकार रहा है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

तो क्या आप टंडन जी से पहले बोलना चाहते हैं । (हंसी)

एक सदस्य—

इन दोनों का एक दंगल करा दीजिये । (हंसी)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

टंडन जी के बाद असरार साहब को जरूर बुलवा दीजिये ।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राज बिहारी सिंह)—

श्री बंशीधर जी पांडेय, मुख्य सचेतक, कांग्रेस (ओ) की बात मैं मानता हूं । मेरा निवेदन है कि हाउस का काम ठीक ढंग से चल सके इसलिये पहले रियासत हुसेन साहब को बुलवा दीजिये । और, 5 बजे के बाद असरार साहब और टंडन जी को मैदान में छोड़ दीजिये । (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—

जो आपका सुझाव है उसमें मैं यह और जोड़ दूं कि 5 बजे के बाद टंडन जी और असरार साहब साथ-साथ बोलेंगे । (अधिक हंसी)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मैं तो स्वीकार करता हूं, वह भी तो स्वीकार करें ?

श्री राम बिलास पांडेय—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । असरार साहब खड़े हुये, इसलिये टंडन जी बैठ गये । मान्यवर, आपने टंडन जी को इजाजत दी थी । टंडन जी लगभग सात मिनट बोले हैं, आप रिपोर्टर से पछ लीजिये, अभी वह बोल रहे थे, इसलिये वे अपने भाषण को जारी रखें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो टंडन जी बोलना चाहते हैं उसको लोगों को सुनना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

मिनिस्टर की हैसियत से उनको अधिकार है कि वह बोलें और वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या सदन में आप किसी विदूषक को इजाजत देंगे कि वह अपना पार्ट अदा करे । (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—

अब इसकी परिभाषा आप पर नहीं छोड़ी जा सकती (अधिक हंसी)

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । सरकार की तरफ से तो अब टंडन जी बोल चुके और इस तरफ से असरार साहब या और कोई बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

कभी-कभी आपको हम दो-दो तीन तीन चांसेज देते हैं ।

श्री वंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, टंडन जी अब अपना भाषण समाप्त कर चुके । अब आप असरार साहब को इजाजत दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उपाध्यक्ष जी, इस वक्त हाउस फुल है । टंडन जी का भाषण चल रहा था उसको चलने दिया जाय हम लोगों को उससे बड़ा अनुभव हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके और टंडन जी के आनन्द के बीच में उपाध्यक्ष नहीं आना चाहेंगे लेकिन अगर टंडन जी बोलना चाहें तब ।

(श्री पुरुषोत्तम दास टंडन के न खड़े होने पर)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

इससे पहले कि, श्रीमन् मैं अपना भाषण शुरू करूं . . . .

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब टंडन जी बोल चुके तब बारी इस तरफ की है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें आपका नुकसान है । अगर हम यह उसूल कठोरता से पालन करेंगे तो आपका नुकसान होगा क्योंकि आपके दो-दो और तीन-तीन को हम एक साथ ही समय देते हैं ।अभी तो हमारी दृष्टि इधर ही है, आपकी तरफ भी जायगी । (हंसी)

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इसके पहले कि मैं अपना भाषण शुरु करूं, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी की तारीफ करने के बगैर नहीं रह सकता हूं । जिन हालात में उन्होंने इतने बड़े सूबे के साल भर के बजट को समय पर तैयार किया जब कि उनके पिता जी बीमार थे और यह दुखद घटना भी घटी कि उनके पिता जी का स्वर्गवास हो गया, उन परिस्थितियों में माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस प्रदेश का 900 करोड़ रुपये का बजट सदन के समक्ष निश्चित समय पर प्रस्तुत किया ।

माननीय चौधरी साहब ने अपने पौने तीन घंटे के भाषण में इस प्रदेश का कोई भी भाग चाहे वह पश्चिम के हो या पूर्व का हो उसके सम्बन्ध में तथा प्रदेश के शासन के मुताल्लिक कोई भी विषय नहीं छोड़ा और इस प्रदेश की ही नहीं बल्कि दिल्ली की सरकार से इस प्रदेश का जो भी सम्बन्ध है, उन सभी विषयों को एक साथ लेकर उन पर रोशनी डाली है। मैंने उनका पौने तीन घंटे लगातार भाषण सुना और इस नतीजे पर पहुंचा जिससे कि मुझे बड़ी खुशी हुई और वह यह है कि कम से कम आज इस सदन के अन्दर दो पक्षों के बीच साफ तौर से दो विचारों के

(इस समय 3 बजकर 2 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगवीर सिंह पीठासीन हुए ।)

का बंटवारा देखने में आया । इधर बैठने वाले लोग जो कांग्रेस के हैं, समाजवादी लक्ष्यों की पूर्ति के लिये तथा उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिये जहां उन्होंने अपने कार्यक्रम और प्रोग्राम तैयार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किये हैं वहीं दूसरी तरफ माननीय चौधरी साहब ने साफ तौर से उनकी नीतियों और पालिसियों का विरोध किया है। सोचने की बात यह है कि जब यह सदन दो हिस्सों में बंटा हुआ है — एक सरकारी पक्ष और दूसरा विरोध पक्ष—तो उस हालत में जब नेता विरोधी दल ने अपनी सारी नीति सदन के सामने रख दी है जिसमें कि उन्होंने प्रगतिशील पालिसियों का विरोध किया है उस परिस्थिति में माननीय जायसवाल जी और उनकी पार्टी क्या करेगी और क्या सोचेगी। यह परेशानकुन बात है। आखिरकार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी विरोध पक्ष का एक अंग ही तो है जिसके नेता माननीय जायसवाल जी हैं। बहरहाल, उन्होंने सबसे पहले एक एतराज यह किया कि इस प्रदेश के अन्दर 241 करोड़ रुपया प्रशासनिक तनख्वाहों आदि में खर्च किया जाता है। श्रीमन्, इस प्रकार की 650 करोड़ रूपये की आमदनी है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

उन्होंने गांधी दर्शन की भी तो बात कही है।

श्री रियासत हुसैन—

जैसा मैंने निवेदन किया था कि परेशानी जो आयेगी वह तो माननीय जायसवाल जी के सामने आयेगी और शम्भूनाथ जी चौधरी तो इस पार्टी से अब अलग हैं...

श्री अधिष्ठाता—

चौधरी साहब भी आपका रास्ता अपनायेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

यह रास्ता तो उन्हें अपनाना पड़ेगा क्योंकि यही एक समाजवादी रास्ता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या गांधी जी का रास्ता आप ठीक नहीं समझते हैं?

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि प्रदेश की आमदनी साढ़े छः सौ करोड़ रुपये की है जिसमें से 240 करोड़ रुपया सरकारी खर्चों में चला जाना है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि क्या माननीय चौधरी साहब 5/6 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को जो इस देश और प्रदेश का एक अंग है, एक सिटीजन नहीं समझते हैं। उनको तनख्वाह के जरिये से जो पैसा मिलता है वह कहीं दूसरी जगह से आये। क्या उन्होंने यह समझ लिया कि इस प्रदेश की आमदनी में चाहे वह सेल्स टैक्स के रूप में हो, या प्रोफेशनल टैक्स के रूप में हो या इन्कम टैक्स के रुप में हो, वे उसमें नहीं आते। यह जो 241 करोड़ रुपये का खर्चा इन कर्मचारियों पर है उसे क्या यह सरकार अपने घर रखकर खर्च करती है और प्रदेश की इन्कम में पुलिंग नहीं है। तो मेरी समझ में उनकी यह दलील नहीं आती है। उन्होंने एक बात कही, मेरी समझ में नहीं आयी कि वह फीगर कहां से आ गयी। मैं इस बात को मान कर चलता हूं कि चौधरी साहब बहुत ही पुराने तजुर्बेकार हैं और करीब-करीब कोई भी विभाग इस प्रदेश का ऐसा नहीं रहा होगा जिसे उन्होंने देखा न हो और कोई भी फाइल ऐसी न होगी जिस पर उनके दस्तखत न हों चाहे उस विभाग के मन्त्री की हैसियत से या मुख्य मन्त्री की हैसियत से। उन्होंने यह फीगर दिया कि इस प्रदेश में जितना एग्रीकल्चरेबिल लैंड है उसका 20 प्रतिशत ही इर्रीगेटेड एरिया है। लेकिन अभी तक जो मेरे मालूमात हैं उसके मुताबिक तो इस प्रदेश में कल्टिवेबिल लैंड का 33 प्रतिशत अन्डर इरगेशन है और उसमें से केवल 27 परसेंट एरिया ऐसा है जिसमें डबल क्रापिंग होती है।

श्री चरण सिंह—

मैंने यू0 पी0 की नहीं बल्कि आल इंडिया फीगर दी थी।

श्री रियासत हुसैन—

चौधरी साहब मुझे मांफ करेंगे, मैंने यही समझा था कि चौधरी साहब ने इस सूबे की फीगर बतलायी । जहां तक स्टेट ट्रेडिंग का सम्बन्ध है उसके बारे में चौधरी साहब ने जिक्र किया और उस पर अपनी राय दी । यह एक बहुत बड़ा विषय है लेकिन सोचना यह पड़ेगा कि जब से मल्क आजाद हुआ और प्रदेश के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में शासन की बागडोर आयी, उस वक्त से लगातार हर साल यह देखने में आया कि किसान जो कुछ भी पैदा करता है वह मिड्ल मैन को बेचता है और मिड्ल मैन फिर उसको साल भर तक अपने बुखारी में रखकर, भाव बढ़ा कर 8—9 महीने बाद उसको बेचता है ताकि उसको अधिक से अधिक फायदा हो । नतीजे के तौर पर यह हुआ कि इस प्रदेश की सरकार ने जिसके चौधरी साहब भी अंग रहे, कई बार कंट्रोल किया, डिकंट्रोल किया, टोटल राशनिंग की और ब्लेक मारकेटिंग व बढ़ते हुए भाव को रोकने के लिये तमाम सारे कार्य-क्रम किये लेकिन आज तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका । आज मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि स्टेट ट्रेडिंग कम्युनिस्ट डिक्शनरी की बात है या सोशलिस्ट डिक्शनरी की बात है बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि यह न कम्युनिस्ट डिक्शनरी की बात है और न सोशलिस्ट डिक्शनरी की बात है बल्कि यह समूचे देश और प्रदेश की जनता की डिक्शनरी की बात है जिसे सब को अपनाना पड़ेगा । यह एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है जिसके आधार पर कांग्रेस को सारे देश के लोगों ने वोट दिया है और सारे देश के लोगों ने उसे तसलीम किया है और मजबर किया है । मसला बहुत बड़ा है, सोचना जरूर पड़ेगा कि आया शासक दल इस स्टेट ट्रेडिंग के सारे कार्यक्रम को मजबूती के साथ और ईमानदारी के साथ चला पायगा या नहीं । अगर चला पायगा तो जैसा कि इस बजट के अन्दर सारा इन्तजाम किया गया है, उसको कामयाबी होगी और अगर नहीं चला पायगा तो जिस जनता को आपने विश्वास दिलाया था कि हम स्टेट ट्रेडिंग को सफल बनायेंगे और उसने आपको वोट दिया था, वही जनता आने वाले चनाव में आपके खिलाफ वोट देगी कि आप उस पालिसी को नहीं चला पाये इसलिये आप नाकाबिल हैं ।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

बम्बई नगरपालिका में इसी आधार पर जो चुनाव हुआ उसके नतीजे पर आपको क्या कहना है ?

श्री रियासत हुसैन—

इसका वास्ता शहर से नहीं है । इसका वास्ता और ताल्लुक तो देहात की 85 प्रतिशत उस जनता से है जो जरूरत के वक्त गल्ला बेचती है और जरूरत के वक्त खाने के लिये खरीदती है । लेकिन आज बदकिस्मती है कि जरूरत के वक्त किसान से 76 या 80 रुपये, या जो कुछ भी भाव हो उसके हाथ बेचने के बाद वह मजबूर हो जाता है और वह बड़े व्यापारी के फंद में फंसा रहता है और वह जिस भाव चाहे बेचे, किसान परेशान होता है और कन्टमर परेशान होता है । यह खाली बम्बई का मामला नहीं बल्कि सारे देश का मसला है ।

कीमतों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि गल्ले का भाव क्या हो। अब तक गेहूं का भाव 74/76 रुपये क्विंटल है। लेकिन मन्त्री जी घोषित कर चुके हैं कि हम समझते हैं कि आज किसान का खर्चा बढ़ गया है, समय पर उसको बिजली नहीं मिल पा रही है, किसान को मजदूरी भी ज्यादा देना पड़ रही है, इसलिये प्रदेशीय सरकार ने जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि हमने सेन्ट्रल गवनमेन्ट से मांग की है कि हमारे यहां गेहूं का भाव 85 रुपये क्विंटल से कम नहीं होना चाहिये। भविष्य में इसका क्या भाव होगा इसके लिये हमारे सूबे की सरकार पूरजोर का सरकार से लड़ाई लड़ रही है कि किसान को बढ़े हुए भाव मिलने चाहिये।

इंडस्ट्रीज के लिये कहा गया कि जो हमारी सरकार इंडस्ट्री लगाने जा रही है वह पब्लिक सेक्टर में लगाने जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं लगा रही है। (लाल बत्ती होने पर) कितना समय मुझे बोलते हुए हो गया है ?

श्री अधिष्ठाता—

15 मिनट आपको बोलते हुए हो गये हैं। आप कितना समय और लेना चाहते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

इतना तो नहीं मिल सकता। आप जारी रखिये।

श्री रियासत हुसैन—

आज हमारी सरकार इसलिये पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्री लगाने जा रही है क्योंकि आज सारे देश में मांग हो रही है कि देश की सारी पूंजी केवल 76 आदमियों के हाथ में ही जमा होकर रह गई है। क्या उसको रोकने के लिये सूबे की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? इस पूंजी का वितरण कैसे होगा अगर इस तरह से इंडस्ट्रीज पब्लिक में नहीं लगाई जायेंगी। अगर इस पालिसी को नहीं माना जायगा तो कैसे किया जायगा? माननीय चौधरी साहब ने यह बात रखी कि हमारे यहां दिन ब दिन क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं। आबादी बढ़ती चली जा रही है और हर शासन में ढिलाई पैदा हो रही है। इसकी जिम्मेदारी शासन पर डालना उचित नहीं होगा। इसको मान कर चलना होगा कि इसका जिम्मेदार हर वह आदमी है जो अपनी समझ बूझ रखता है। जो माननीय सदन में सदस्य बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी इसकी जिम्मेदारी आती है। जो वकील प्रेक्टिस करते हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि किस तरह से इनको बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके जिम्मेदारी सबके ऊपर है। शासक दल के ऊपर ही यह जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं होगा। रोजाना अखबारों में खबरें छपा करती हैं जिनको पढ़कर माननीय चौधरी साहब खुश होते हैं कि 40 विधायकों ने क्या कह दिया। अगर ऐसी खबरें न छपें तो अखबार कौन देखेगा? जिस दिन ऐसी गरम खबरें छपती हैं उस दिन अखबार की सेल दुगनी तिगुनी हो जाती है और जिस दिन ऐसी खबरें नहीं छपतीं हैं तो लोग पढ़ने का भी प्रयास नहीं करते हैं।

आज जो बड़े नारे चल रहे हैं कि आय का जो अनुपात है वह एक और दस से ज्यादा न होकर, उसको एक और तीस से घटाकर हम 1 और 12% के अनुपात पर ला रहे हैं। क्या यह इस सरकार का प्रोग्रेसिव कदम नहीं है? क्या यह इस बजट की खास क्वालिटी और अच्छाई नहीं है? बजट के अनुमानों को देखने और उनकी स्क्रूटिनी में बड़ी देरी लगती थी उसके लिये इस बजट में यह कोशिश की गई है कि फाइनेंस विभाग का एक अधिकारी हर विभाग में रहे ताकि किसी स्कीम को पूरा करने में देरी न हो। क्या यह अच्छी बात इस बजट की नहीं है? बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने केन्द्रीय सरकार से कहा कि जो रुपया ओवरड्राफ्ट लिया गया है उसको लोन की शक्ल में तब्दील किया जाय और वित्त मन्त्री जी अपने इस प्रयास में सफल हुए हैं। क्या यह तारीफ की और सूबे के लिये अच्छाई की बात नहीं है?

हरिजनों के ऊपर अत्याचार की चर्चा की गई। इस बात पर गौर किया जाय कि क्या यह मामूली बात है कि किसी बजट में इनके लिये एक कमीशन की नियुक्ति का प्राविजन किया गया है और जहां पर उन के ऊपर ज्यादती होती है वहां के रहने वाले दूसरे लोगों पर यूनिटिव टैक्स लगाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा 7 करोड़ रुपया हरिजनों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिये इस बजट में रखा गया है। क्या यह अच्छी बात नहीं है?

उर्दू के लिये बड़ी परेशानी जाहिर की गई। लेकिन जिन लोगों को उर्दू के बारे में शिकायत है वह यह देखें कि सरकार ने उर्दू एकेडमी बनाकर क्या किया है? उर्दू एकेडेमी

[श्री रियासत हुसैन]

ने साल भर में यहां क्या किया है उन्हें उस पर गौर करना चाहिये। सरकार की तरफ सारे अरबन एरियाज में जितने स्कूल हैं उन में उर्दू के लिये अलग टीचर रखने के आदेश जारी किये गये हैं। इसके अलावा सूबे में जितनी भी लायब्रेरीज हैं और जो उर्दू के अखबार मंगाती हैं उनको क्या लाखों रुपया की इमदाद उर्दू एकेडमी के जरिये से नहीं दी गई है? जहां तक गजट की बात है सेक्रेटेरीएट में ट्रान्सलेटरों की जगह को खत्म कर दिया गया था, अब दोबारा उनको रखा गया है और गजट फिर उर्दू में निकलेगा। यह सारे इकदाम किये गये हैं जिससे उर्दू को सही स्थान सूबे में दिलाया जा रहा है और सरकार चाहती है कि जितनी भी उर्दू को तरक्की दी जा सकती है वह दी जाय। बुन्देलखंड में जो जमीन के अन्दर खनिज वेल्थ है उस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है और वहां जो थोड़ा सा तांबा मिला है उसके बारे में अन्वेषण हो रहा है। यह क्या कम उपलब्धि की बात है?

(लाल बत्ती होने पर) अभी श्रीमन्, हमें दस मिनट और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

2 मिनट में अब आप समाप्त कर दें।

श्री रियासत हुसैन—

मैं जल्द ही अपनी बात समाप्त करूंगा, इस बजट में हर ब्लाक में एक जयन्ती ग्राम नमूने के तौर पर बनाने के लिये एक कमेटी बनाने का प्राविजन किया गया है। सूखे तथा बाढ़ के क्षेत्रों में जो लोन 9 प्रतिशत पर दिया जाता है वह ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद देने के बाद केवल साढ़े 6 1/2 प्रतिशत सूद पर दिया जायगा। क्या यह गरीब लोगों की इमदाद नहीं है? इसी तरह से एक वाटर बोर्ड का प्राविजन किया गया है। इसके अलावा इन्टर बोर्ड को आगे नेशनेलाइज करने के संबंध में इस बजट में संकेत है। फ्रीडम फाइटर्स का बोर्ड बनाया गया है। इन सारी चीजों क होते हुये विरोधी दल के लोगों को भी इस बजट की तारीफ करना पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि यह प्रोग्रेसिव बजट है। मैं केवल 2-4 सुझावों के बाद अपनी बात खत्म करूंगा।

लगातार 25 साल से प्रदेश में डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी का एक संघर्ष चल रहा है। यहां डेमोक्रेटिक शासन है और सभी लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वह जनतन्त्र को यहां ठीक से चलावे। जो हुक्म मंत्रीजी के यहां से निकले वह पालन होने के लिये निकले और ब्यूरोक्रेसी उसे माने वह टालमटोल क लिये न जाय। इसका पालन बहुत सख्ती से शासन को कराना होगा। ट्रान्सफर के बारे म एक बड़ी बीमारी यहां लग गई है। और प्रदेश में कहीं भी उस से मुक्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि तबादलों के संबंध में सरकार की एक मुस्तकिल पालिसी हो। जब से कोई सर्विस में दाखिल हो उसके लिये रूल्स में प्राविजन कर दिया जाय कि हर कर्मचारी की 30 साल की सर्विस होगी और 5 जोन्स में सूबे को बांट दिया जाय। और उसके लिय रूल प्रोवाइड कर दिया जाय कि 6 साल तक हर जोन में जरूर रहना पड़ेगा। पहला पोस्टिंग उसका घर से सबसे अधिक दूर कर दिया जाय, फिर दूसर जोन में और इस प्रकार से आखीर के 6 सालों में अपने घर वाले जोन में पोस्टिंग किया जाय और आखरी 2 सालों में उसके जिले में पोस्टिंग किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

क्या आप बटवारे की बात कर रहे हैं?

श्री रियासत हुसैन—

जी नहीं, आपने शायद हिन्दुस्तान में बटवारे की बात नहीं कर रहा हूं। जोन की बात कर रहा हूं। बंटवारे का जो नारा लगाया जा रहा है, उसके पीछे अधिकारियों का हाथ है जो

पश्चिमी जिलों के रहने वाले हैं, वे, पूर्वी जिलों में पर्वतीय जिलों में और बुन्देलखंड के जिलों में जाना नहीं चाहते हैं। तो अगर प्रदेश का बंटवारा भी हो जाय तो इसके पीछे उनका भी हाथ है। जैसा मैंने जोन्स के बारे में निवेदन किया अगर ऐसे आदेश हो जांय तो अधिकारी यह समझ लेंगे कि उन्हें भी 30 साल में हर जिले में, हर जोन में रहना पड़ेगा।

जहां तक हाई कोर्ट की बैंच की खुलने की बात है मैं जरूर चाहता हूं कि पश्चिमी जिले में बेंच हो लेकिन उसके लिये सबसे उपयुक्त जगह रामपुर है। वहां पर हाई कोर्ट की एक बैन्च जरूर होनी चाहिये।

जहां तक सदन द्वारा पास किये हुये बजट का प्रश्न है कि 31 मार्च तक अवश्य खर्च होना चाहिये, मेरी प्रार्थना है कि इसके लिये सख्ती से आदेश होने चाहिये और जो अधिकारी उस पैसा का सदुपयोग समय से न करे उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए। अन्त में मेरी माननीय सदन के सदस्यों से यह भी गुजारिश है कि अगर शासन इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रयास करता है तो कोई माननीय सदस्यों को उस अधिकारी के लिये कोई हमदर्दी या सिफारिश करने का प्रयास नहीं करना चाहिये। इन शब्दों के साथ माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं।

*श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो सन् 1973–74 का बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका विरोध करने के लिये और माननीय चौधरी साहब द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

अधिष्ठाता महोदय, बजट के सम्बन्ध में जब बजट भाषण हो रहा था तो सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर माननीय नारायण दत्त तिवारी और कैबिनेट ने किस आधार पर तय करके 74 करोड़ रुपये का घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में यह नहीं बताया कि यह घाटा कहां से पूरा होगा, इसके लिये कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है। जब यह बजट आया तो मैं तो यह मान कर चला कि कोई नया टैक्स नहीं लगा या गया, इसके भाषण में भी कोई संकेत नहीं किया। मैं तो इसको यही मानता हूं कि सन् 1974 के चुनाव आने के कारण इस तरह का बजट रखा गया है जिसमें कोई रूपरेखा नहीं है। केवल यह कहा गया है कि टैक्स नहीं लगेगा लेकिन घाटे को कहां से पूरा किया जायगा, केन्द्र देगा या पब्लिक से आयेगा ?

यही नहीं, अधिष्ठाता महोदय, जो बंगला वेश का 1 अप्रैल से टैक्स हटाने की बात थी उस कर को भी दूसरे रूप में सूखे और बाढ़ के रूप में लाकर जनता के ऊपर वैसे का वैसा ही रखना चाहते हैं। कितना बड़ा प्रचार हुआ लेकिन जो पहली अप्रैल को हटने वाला टैक्स था उसको दूसरे रूप में लागू करने जा रहे हैं। क्या वह टैक्स उन गरीबों पर नहीं लगता जो कोई चीज बाजार में जायेगा खरीदने ? लेकिन ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि कोई नया कर नहीं है। बड़ी होशियारी से रख दिया कि अप्रैल के बाद में कोई नहीं लगेगा, जबकि वह बराबर लगता रहेगा।

अधिष्ठाता महोदय, समय ज्यादा नहीं है। मैं इतना बता देना चाहता हूं कि यहां जितनी सरकारें बनी हैं, लेकिन इस तरह की निकम्मी सरकार, जिसमें कोई प्राण न हो, इस डेमोक्रेसी के इतिहास में कोई नहीं बनी। यही नहीं आज अधिकारी इतने निरंकुश होते जा रहे हैं कि अभी-अभी उधर से कहा गया कि मिनिस्टर आदेश देते हैं और उनका एक्जीक्यूशन नहीं होता है। यह शर्म की बात है। इस हाउस में कहा जाय कि मंत्री का आदेश हो और उसको एक्जीक्यूट न किया जाय, यह कितना बड़ा निकम्मापन है। यह इस सरकार के लिये चुनौती है। जैसा कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मलिखान सिंह–]

चौधरी साहब कह रहे थे कि हम दो आधार पर ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ में कर सकते हैं। एक तो यह कि हमारा मोरल करैक्टर इतना अच्छा हो कि मेरे मुंह से जो शब्द निकले, उनके दिमाग में यह बात हो कि वह सही है, तब वे उसको एक्जीक्यूट करेंगे। दूसरे कि हमारी नीति सही हो। अगर हमारी नीति गलत होगी तो हम चाहें कितने योग्य हों, वे उसको एग्जीक्यूट करने में हिचकिचायेंगे। मोरल के बल पर जो आदेश किये जाते हैं, उनका पालन किया जाता है। उसको वे रोक नहीं सकते चाहे कितना ही भ्रष्ट अफसर क्यों न हो। लेकिन जहां आदेशों में गड़बड़ी हुई, वह कितना बलशील हो, वे फिर तर्क करते हैं, उन नियमों का पालन करने के लिये जो इस विधान सभा में पास किये गये हैं। उन सब पर अपनी राय रखते हैं मंत्री के सामने कि जिनक आधार पर मंत्री महोदय को विचार करना चाहिये। तो इस आधार पर मंत्री को आदेश देना चाहिये, तभी उनका एग्जीक्यूशन होगा, अन्यथा नहीं।

मान्यवर, किसी विभाग में ये सफल नहीं हुये। बिजली के बारे में बहुत कुछ कहा गया। में केवल संकेत देना चाहता हूं। आज किसान परेशान है बिजली के कारण। रात में खेत में बिजली नहीं, दिन में बिजली नहीं। इधर पानी ट्यूबवेल से जाता है और जैसे ही इंजिन स्टार्ट हुआ कि बिजली चली गयी। लेकिन किसान को खाद और बिजली का टैक्स तो देना ही पड़ा, हालांकि फसल सूख गयी। अभी भाई रियासत हुसैन जी ने कहा कि 33 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है। शर्मा जी यहां बैठे हैं। हमीरपुर में यह केवल 10 प्रतिशत है। जालौन में 25 प्रतिशत है। मध्य यू0 पी0 में कोई ऐसा जिला नहीं जहां 33 प्रतिशत से ज्यादा हो। सीतापुर में जरूर 45 प्रतिशत है। बुन्देलखंड में 25 प्रतिशत है। जो सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव क्षेत्र हैं, वहां भी 70/72 से अधिक नहीं है। जब आप 20/25 सिंचित क्षेत्र को 50 प्रतिशत न कर पाये। तो आप क्या मिरेकल कर देंगे कि इस प्रदेश में जब कहीं सूखा पड़ेगा तो उसका मुकाबला कर लेंगे ? 33 प्रतिशत में आप फसल करते हैं लेकिन 70 प्रतिशत में क्या होगा ?

अधिष्ठाता महोदय, पिछली बार फरवरी में मैंने कहा था कि गल्ले के भाव 76 रुपय कर रहे हैं लेकिन दिसम्बर तक 100 रु0 क्विन्टल से अधिक आ जायेगा। लोगों ने पूंछा क्या कारण है ? मैंने कहा कि हमारा प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। हमरे यहां गल्ला सरप्लस हुआ। बुन्देलखंड का और जो नदियों का इलाका था उसमें ऐसी खेती हुई जैसी सिंचित क्षेत्रों में होती थी और बम्पर क्राप हुई और इस कारण हम 3 साल तक सरप्लस रहे। मान्यवर, इस साल के आंकड़े मैं बताये देता हूं। यह सरकार 76 रु0 गल्ले की कीमत रखने जा रही है। मैं कहता हूं कि इनको यह कीमत बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि जिसके अन्दर ताकत गल्ले को रखने की नहीं है, ऐसे गरीब लोगों का गल्ला तो यह सरकार खरीद लेगी, लेकिन जिसके अन्दर भी 6 महीने रखने की ताकत है गल्ले को वह रखेगा और गल्ले की कीमत 100 रु0 के ऊपर जायेगी और यह सरकार इसको रोक नहीं पायेगी क्योंकि अगर गल्ला नहीं आयेगा तो यह सरकार लायेगी कहां से ? इसलिये इस सरकार को सुबुद्धि दे और वह कम से कम 90 रुपये से कम गल्ले की कीमत न रखे और अगर इससे कम की गई तो किसान मर जायेगा। मान्यवर, मैं कहता हूं कि यह सरकारी आंकड़े उठाकर देख लें, चाहें किसी भी संस्थान के आंकड़े उठाकर देख लें, प्रति एकड़ प्रति क्विन्टल जो प्रोडक्शन कास्ट आती है उससे 10 रुपया बढ़ाकर कीमत रख दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पन्तनगर यूनीवर्सिटी ने यह आंकड़ा निकाला है कि उनके यहां 80 रुपया प्रोडक्शन कास्ट आती है। मैं तो कहता हूं कि यूनीवर्सिटी के आंकड़े के हिसाब से किसान के गल्ले की कीमत रख दें। अगर 76 रुपये रखेंगे तो न्याय नहीं होगा। अक्सर यह कह दिया जाता है कि कपड़े पर या किसी भी चीज की बात क्यों न हो, कन्ट्रौल गवर्नमेंट पर है। जब किसी भी चीज की कीमत सेन्ट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है तो आप पिछले 7–8 वर्ष आंकड़े उठाकर देख लें, उस चीज की कीमत तिगुनी और चौगुनी हो गई है तो फिर गल्ले की कीमत क्यों 76 रु0 रखी जा रही है ? आजकल शहर आजाद हो रहे हैं और किसान मर रहा है। मैं तो कहता हूं कि आप कोई कमेटी

बना दें जो गांवों में जाकर देखें कि अगर बाबा जिस घर में रह रहा होगा तो उसका नाती भी उसी घर में रह रहा होगा और उसी खेत पर काम कर रहा होगा, यदि उनके पास कोई दूसरा साधन पैसा कमाने का नहीं है। वही मकान होगा और वही छप्पर होगा।

आपने इस साल नहरों को पानी न देकर किसान को मार दिया। जब बिजली कर्मचारियों की हड़ताल थी तो ठीक था कि माताटीला में पानी नहीं रहा, लेकिन पश्चिम की नहरें जहां बराबर पानी रहता था, जो सिंचाई की साधन थीं, उसमें भी पानी नहीं गया और फसले बरबाद हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूं कि नहर में कौन सी हड़ताल रही। यही नहीं अधिष्ठाता महोदय, कि केवल प्रोडक्शन की बात हो, इसके भुगतान की बात है। चूंकि अब तो सरकार गल्ले का व्यापार अपने हाथ में ले रही है तो जब यह प्रदेश के किसानों के बीच में जायेंगे तो मालूम होगा कि प्रदेश का किसान कराह रहा है और इनको गाली दे रहा है। वह यह जानता है कि इनके ऊपर अफसरशाही सवार हो गई है और वह उनके बोझ से दबे जा रहे हैं। नहर के इंजीनियर पर इनका अंकुश नहीं है। आप इनके एडमिनिस्ट्रेशन को देख लें।

आंकड़ों के आधार पर मैं बताता हूं कि जहां सड़क पर ट्रक झुंड के झुंड चलें, फिर भी जान और माल की रक्षा न हो लोग मारे जायं, राजनैतिक हत्यायें हों यही नहीं विधायकों के मडर, हों और उनकी रक्षा के शैडो दिये जायं। सरकार की यह स्थिति आ गयी है कि विधायकों को सैडो दिये जा रहे हैं। यही नहीं श्वेत दिसम्बर और ब्लैक दिसम्बर की एक और बीमारी चल पड़ी है। हमारे प्रदेश का इंटीलीजेंस विभाग यही पता नहीं लगा सका कि यह धमकी भरे पत्र कौन लिखता है। वह भी इस तरह के पत्र लिखता है कि मुख्य मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो वाटर वर्क्स फूंक देंगे या उनमें जहर डाल देंगे। मान लीजिये यह सब गलत ही हो लेकिन यह पत्र लिखता कौन है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को कोई जानकारी नहीं कि यह धमकी भरे पत्र कौन लिखता है। उनका कहना है कि यह फर्जी चिट्ठी डाल दी जाती है। यह फर्जी ही चिट्ठी सही लेकिन यह आती कहां से हैं। इनका मन्तव्य क्या है। अगर कोई ऐसा गिरोह पनप रहा है तो क्यों पनप रहा है। आया इसके पीछे पाकिस्तान, चीन, अमेरिका या रूस की मशीनरी काम कर रही है यह हमारे देश में ही कुछ ऐसे गलत तत्व हैं जो इस प्रकार के गिरोह बना रहे हैं। इसकी जानकारी होनी चाहिये।

आज हमारे प्रशासन में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको हम दूर नहीं कर सकते क्योंकि आज जहां बिरादरी के आधार पर पोस्टिंग्स हो रही हैं वहां सेभ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता। अगर कहीं एस० पी० पंडित है तो वहां एस० ओ० भी पंडित ही होगा और अगर कहीं ठाकुर है तो वहां एस० ओ० ठाकुर होगा। इससे प्रदेश में इतनी शिथिलता आ गयी है कि जो काम करने वाला व्यक्ति है वह भी निराश हो गया है और सोचता है कि जब सिफारिशी लोगों को ही प्रोमोशन पाना है तो हम क्यों रिस्क लें। इसी कारण पुलिस विभाग में इस तरह का वातावरण फैलता जा रहा है जिसकी वजह से डकैतियां और चोरियां बढ़ती जा रही हैं। आज जन जीवन की भी सुरक्षा नहीं है। जन जीवन की सुरक्षा करने का काम सरकार का है क्योंकि जनता सरकार को इसीलिये टैक्स देती है कि उसके जीवन की सुरक्षा की गारन्टी हो। लेकिन आज जनता परेशान है। दिन दहाड़े चोरियां और डकैतियां होती हैं।

इसी तरह से न्याय के बारे में बताना चाहता हूं। पश्चिमी जिलों में हाई कोर्ट की बैंच खुलने की बात थी। वह तो बात दूर रही लेकिन न्याय भी सस्ता नहीं हुआ। आज समाजवाद का नारा लगाया जाता है। जब चौधरी साहब बोल रहे थे तो वह कह रहे थे कि पब्लिक सेक्टर जब नुक्सान पर चलता है तो फिर आप पब्लिक सेक्टर में क्यों खोलते जाते हैं। उन्होंने एक रूपरेखा रखने की कोशिश की थी लेकिन इसके पीछे यह भाव कतई नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर को खुली छूट दे दें। हम तो चाहते हैं कि प्रदेश में ही नहीं सारे देश में एक एक व्यक्ति सुखी हो, उसे पूरा भोजन मिले, कपड़ा और मकान मिले। हम तो मानवता सिद्धान्त के आधार पर मानव मानव में प्रेम चाहते हैं। नेहरू जी रूस की तरफ भले ही जा सकते हों लेकिन वहां भी कोआपरेटिव

[श्री मलिखान सिंह]

फारमिंग फेल रही। आज रूस को भी अमेरिका से गल्ला लेना पड़ा। जरूरी है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों और अपनी योजनायें अपनी भौगोलिक सीमा के हिसाब से चलावें। चारों तरफ से सहायता लेकर हम अपनी योजनायें चला रहे हैं। जब तक व्यक्ति-व्यक्ति को काम नहीं देंगे और खेत-खेत को पानी नहीं देंगे तब तक प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। आप ट्यूबवेल लगवाइये और बांध बनवाइये। ट्यूबवेल चाहे बिजली से चलें या डीजल से, मगर उनका होना जरूरी है। बिना इसके प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है।

अधिष्ठाता महोदय, यह कहा गया कि हम करदाता कहां से लायेंगे। राज्य कर्मचारियों की इतनी तनखवाह बढ़ने के बाद यह बात सही है कि आप कहां से इतना पैसा लायेंगे। प्रदेश का प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब कि हैवी इन्डस्ट्री और कुटीर उद्योग प्रदेश के अन्दर खुलेंगे। प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स टैक्स व इनकम टैक्स भी नहीं आयेगा। टैक्स तब आ सकता है जब हैवी प्रोडक्शन करें। हम तो घाटे की तरफ जा रहे हैं---आगे बढ़ नहीं रहे हैं। कोयले की बहुत बड़ी समस्या है। कोयले को अभी-अभी सरकार ने अपने हाथ में लिया है। कोयला नहीं होगा तो फैक्टरियों नहीं चलेंगीं और फैक्टरियां नहीं चलेंगीं तो प्रोडक्शन कैसे होगा? फिर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स कहां से आयेगा? अधिष्ठाता महोदय, थोड़ा समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता---

आप जारी रखिये।

श्री मलिखान सिंह---

जितनी भी योजनायें बनीं वे कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाईं। एक नयी मिसाल दे दूं। इन्होंने राजनीतिक लाभ के लिये नेहरू ब्रिगेड चलायी है। इन्दिरा जी ने अपनी पार्टी की की हुई सब करतूतों को एक भाषण में साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि योजनायें तो सब अच्छी हैं और हम उन्हें पूरा करना चाहते हैं लेकिन नौकरशाही पूरा नहीं होने देती। नेहरू ब्रिगेड नाम की सेना हर जिले में नारे लगाती है कि नौकरशाही मुर्दाबाद। मैंने कहा कि आप जो सब मंत्रियों की हेड हैं उन्हें क्यों नहीं कहते कि मुर्दाबाद। कलेक्टर को गाली देने से, एस0 पी0 को गाली देने से या यहां पर चीफ सेक्रेटरी को गाली देने से तो काम नहीं चलेगा कि हमने इतना काम किया मगर ब्यूरोक्रेसी ने सहयोग नहीं दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। अफसरों का और जन प्रतिनिधियों का जब कोआर्डिनेशन होगा तब काम होगा और तभी प्रदेश और देश आगे बढ़ सकता है। यह प्रदेश कितना बड़ा है। बहुत से मंत्री नाराज हो जायेंगे। टंडन जी को तो जिलों के नाम नहीं मालूम होंगे और उनको विभाग दे दिया है एजूकेशन। इस 54 जिले के प्रदेश में अगर आप बराबर ६ महीने दौरा करें तो सब अफसरों के मुंह देख पाएंगे और जब तक अफसर को जानेंगे तब तक मंत्रीशिप से अलग हो जायेंगे। होता यह है कि सेक्रेटरी ने फाइल पर लिख दिया और आपने दस्तखत कर दिये। इसलिये प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये 2 हिस्सों में कर दिया जाय तो मैं इसको बुरा नहीं मनता हूं। आज की स्थिति यह है कि जितने छोटे-छोटे प्रदेश है वे आगे बढ़ते जा रहे हैं जैसे हरियाणा व हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश तो पहाड़ी क्षेत्र है। वहां पर साधन भी ज्यादा नहीं हैं, परन्तु वह हमसे ज्यादा विकसित हैं। तो इस आधार पर हमें इसमें कोई संकोच नहीं है। हम तो यह मान कर चलते हैं कि इस सरकार की यही धारणा रही तो यह मांग प्रबल हो जावेगी और प्रदेश को चार भागों में बांटना पड़ेगा। आप इसलिय चेत जाइये और अपना रवैय्या ठीक कीजिये जिससे प्रदेश में अलग-अलग भावना न आवे और एक रूप होकर काम हो। मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, जो आशा लेकर मैं आज सुबह चला वह साहब के भाषण से पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कोई इस सदन में रचनात्मक सुधार नहीं दिये और केवल व्यक्तिगत बातें ही कही हैं। मैं आज से नहीं बहुत समय से देख रहा हूं कि जब चौधरी साहब विरोध में बैठते हैं तो करीब करीब वही भाषण वह करते हैं। इस कारण मैं चौधरी साहब को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह अपना भाषण टेप रिकार्ड करवा लें और जब उनका नम्बर आये लगा दें। इस तरह से उनको दो तीन घंटे भाषण नहीं देना पड़ेगा। मान्यवर, जिस कठिन परिस्थिति में हमारे वित्त मंत्री जी ने मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में बजट पेश किया है वह सराहनीय है। कौन यह बात नहीं जानता कि प्रदेश सूखे की चपेट में है देश का 2/3 भाग राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात आदि जिस हालत में चल रहे हैं उनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो इन परिस्थितियों में बजट पेश किया गया है वह सराहनीय है और मैं वित्त मत्री जी को इसलिये बधाई देता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में इकोनामी करने की कोशिश की है और एक नया पसा भी टैक्स नहीं लगाया है।

यहां पर हरिजनों पर अत्याचार की चर्चा की गई। अब 69 में बी0 के0 डी0 की सरकार थी तो हरिजनों पर जो अत्याचार हुये थे और डंडे के जोर से वोट डलवाया गया था उसको कहा नहीं जा सकता है। हरिजनों की सुख सुविधा के लिये आयोग गठित किया जा रहा है इसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है। हरिजनों पर जो अत्याचार होते हैं उसके बारे में सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश दे दिये गये हैं कि वह उनके बारे में जांच करें। चौधरी साहब ने कहा कि जब वह होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने आदेश दिये थे कि सभी अपराधों की रिपोर्ट लिखी जाय। आज जब हमारी सरकार ने यह आदेश दिये तो कहते हैं कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है। उनके समय में रिपोर्ट्स की संख्या बढ़ गई तो एतराज नहीं किया लेकिन अब हम कहते हैं कि अपराधों की संख्या बढ़ गई हैं। हमारी सरकार निश्चित रूप से हरिजनों के प्रति सजग है और इस सम्बन्ध में वह समुचित कार्यवाही हो रही है। आप देखें तो मालूम होगा पिछले वर्षों में सरकार ने बहुत ही समाजवादी कदम उठाये हैं। अधिकतम जोत सीमा को ला दिया है और शहरी सीमा को भी करने जा रहे हैं। यही नहीं, हरिजनों के आवासों की व्यवस्था भी हमने की है।

पी0 डब्लू0 डी0 विभाग को ले लीजिये, केवल एक ही विभाग ने कितनी प्रगति की है? 1969 से 71 तक केवल 24.13 लाख रुपया खर्च हुआ था लेकिन हमारी सरकार ने साल भर में 34.21 लाख रुपया खर्च कर दिया। जो फाइनेनसेज के रास्ते में रोड़े आते थे उसको हमने सफाई की। पी0 डब्लू0 डी0 मिनिस्टर ने निर्माण कार्य की सब बाधाओं को दूर किया और आज आप देखें कि दो हजार किलोमीटर पक्की और 3 हजार किलोमीटर कच्ची सड़कें बनायी जा रही हैं। यही हालत उद्योग-धंधों में भी है।

माननीय चरण सिंह ने कहा कि लघु उद्योगों के लिये कोई प्रयास नहीं हो रहा है। उन्होंने शायद पढ़ने का कष्ट नहीं किया। लघु उद्योग के लिये हमारी सरकार ने एक अलग निदेशालय करघा उद्योग के लिए स्थापित करने की कोशिश की है और बेरोजगारी को दूर करने के कई प्रयास किये जा रहे हैं। टेक्निकल प्रशिक्षा के लिए उसमें कर्ज लेने की सुविधा दी जा रही है। अगर हम योजनाओं को देखें कि किस तरह से वे रोजगार-परक बनी हैं तो छोटी छोटी कई योजनाएं आ रही हैं।

आज सरकार ने देखा कि शिक्षा के स्तर पर गिरावट बढ़ती जा रही है तो इस प्रदेश की विशालता, आवश्यकता को देखते हुए 3–4 निदेशालय प्रायमरी, बेसिक, जूनियर और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम प्यारे]

यूनीवर्सिटी स्तर पर अगर सरकार ने कायम करने की बात की तो कौन सा जुर्म किया? यही नहीं कि प्रायमरी शिक्षा में सख्यात्मक बढ़ावा हम देने जा रहे हैं, बल्कि उसमें गुणात्मक यानी उसके स्तर को सुधारने की कोशिश की जा रही है और जो मांग आप लोगों की थी उसी को पूरा करने की कोशिश हो रही है। यही नहीं, आज शिक्षा के संबंध में भवन की, साज-सज्जा की, पढ़ाई की सामग्री की व्यवस्था होने जा रही है और शिक्षा के माध्यम से बेरोजगारी दूर करने के लिए 3 हजार ऐसे नवयुवकों को जो बेकार पड़े हुए हैं उसमें रखने जा रहे हैं।

श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)—

यह बिड़ला के दलाल हैं।

श्री रामप्यारे—

तो आप दलालों के दलाल हैं?

श्री अधिष्ठाता—

आपस में बात न करें।

श्री रामप्यारे—

जब विरोधी दल ने देखा कि अगले साल चुनाव कराने जा रहे हैं तो इनको आलोचना करने की कोई चीज नहीं मिल रही है। क्योंकि हम तो समाजवादी रास्ते पर चल रहे हैं। सिंचाई के लिए चौधरी साहब ने कहा कि 3 परसेंट बढ़ गयी। आज वह प्रदेश के बजट पर बोलते हुए हिन्दुस्तान के बजट पर ही चर्चा कर रहे थे। उन्होंने यह नहीं देखा कि किस प्रकार इस सरकार ने अधूरी योजनाओं को पूरा किया, 2–3 योजनाओं को पूरा किया और आज 3–4 हैक्टेयर भूमि बढ़ने जा रही है। सिंचाई मंत्री और मुख्य मंत्री ने जो प्रयास किये हैं वह उल्लेखनीय हैं। कई हमारे विवाद दूसरे प्रदेशों से, बिहार से, मध्य प्रदेश से चल रहे थे उनको माननीय मुख्य मंत्री जी ने तय किया और आप जानते हैं कि मिर्जापुर की जैसे सोन लिफ्ट की योजना पर काम हो रहा है इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की बान-सागर योजना बन रही है। बिजली का प्रश्न गम्भीर है, बिजली की कमी है, लेकिन क्या हमारी सरकार या बिजली मंत्री सजग नहीं है। ओबरा में 400 मेगावाट का इंस्टालेशन जल्दी लगने वाला है। माता-टीला के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। सुल्तानपुर में 400 मेगावाट की व्यवस्था की जा रही है और सी कार से कानपुर में 400 मेगावाट की करने जा रहे हैं। क्या इस कठिन परिस्थिति में जब कि संयोजन लिमिटेड हैं, उनके अन्तर्गत भी एक सरकार इतने अच्छे ढंग से कार्य करती है तो क्या वह सजग नहीं है। हमारे चौधरी साहब बीसियों बार कह चुके हैं कि हिंडालको की वजह से प्रदेश को घाटा है। मैं कहना चाहता हूं कि 1968 में जब वह चीफ मिनिस्टर थे उस समय प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। क्या उन्होंने उस ऐग्रीमेंट को कैंसिल किया था। बिड़ला वालों ने यह कहा था कि जैसी डीलिंग चरण सिंह सरकार के साथ हुई वैसी किसी और सरकार के साथ नहीं हुई।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या राम प्यारे जी को मालूम है कि चौधरी साहब ने कटौती कर दी थी। और चौधरी साहब न खुद कहा था कि जब ऐग्रीमेंट होने लगा था तो उन्होंने उसका विरोध किया था।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे—

आप तो अभी चार रोज से यहां गये हैं। मेरा सिर शर्म से झुक जाता है जब वह जाति बिरादरी की बात करते हैं। मैं मानता हूं कि उनको प्रशासन का अनुभव है। लेकिन जब जातिबिरादरी की बात आती है तो उनकी सारी ईमानदारी ताक पर रखी रह जाती है। आज किसी व्यक्ति पर ऐसा आरोप लगा देना मै नहीं समझता कि संसदीय प्रणाली में उचित है। आज कांग्रेस में किसी जाति बिरादरी या धर्म की बात नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

आपके यहां चुनाव में 10 में 8 ब्राह्मण थे और यहां 5 में एक भी जाट नहीं था।

(व्यवधान)

श्री रामप्यारे—

चरण सिंह जी ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एस० एन० सिंह को नियुक्त किया था इसलिये कि वह जाट थे। उसका करक्टर रोल कितना खराब था। हमारे विरोधी दल के नेताओं ने कहा था कि ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर को चेयरमैन न बनाओ। उसकी बड़ी प्रशंसा कर दी चौधरी साहब ने क्योंकि वह जाट था।

क्या आज हम उन नीतियों पर नहीं चल रहे है जो गरीबी मिटाने के लिये हैं। आज मिर्जापुर में 50 हजार आदमी टेस्ट वर्क्स में काम कर रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं पाड़ी थी कि 1 रुपये से 2 रुपये की मजदूरी टेस्ट वर्क में कर दें। लेकिन आज सभी लोग 3 रुपये मजदूरी पा रहे हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

पांच मिनट हमें और दे दीजिये, श्रीमन्।

श्री अधिष्ठाता—

जी नहीं। आप खत्म कीजिये।

श्री राम प्यारे—

आज जो हम बिजली और सिंचाई पर रुपया खर्च कर रहे हैं क्या वह कृषि के लिये नहीं है? उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिये केवल ढाई करोड़ का खर्च है। मैं उस साल का बजट देखना चाहता था कि कर्मचारियों के लिये उन्होंने कितना रुपया दिया था। आज हमारी सरकार जिस समाजवादी कदम की ओर बढ़ रही ह उसको देख कर विरोधी दल के लोगों म खलबली मच गयी है।

(व्यवधान)

आज ग्राम सभाओं के चुनाव में 90 प्रतिशत वोट कांग्रेस के पक्ष में आये हैं और जहां नहीं दिये हैं वहां लाठी डंडे के डर से। कहीं सभापतियों को बन्द कर दिया, कहीं घूस दे दिया। यह सरकार समाजवाद की ओर चल रही है इसमें कोई शंका नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त ।

*श्री महातम प्रसाद तिवारी (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, अभी हमारे रामप्यारे जी ने जो ड्रामा खेला और जो बात कही, वे अपनी उन बातों को शायद भूल गये जब वे इधर विरोध पक्ष में बैठक करते थे। (व्यवधान) पता नहीं वे अपनी उन बातों को कैसे भूल गये। यह हरिजन हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने हरिजनों के लिये क्या किया ?

मान्यवर, 25 अगस्त, 1972 को पौने 9 बजे रडियो से यह एलान हुआ कि हरिजनों को मकान बनाने के लिये रुपया और ऋण बांटा जायेगा। 26 तारीख को बदली थी, बरसात थी, एक भी किसान घर से बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन किसी प्रकार तमाम किसान भीगते हुये उस दिन तहसील में गये और वहां जाकर एक एक रुपया देकर फार्म खरीदा इस लालच से कि उनको मकान बनाने के लिये रुपया मिलेगा। एक एक विधायक के क्षेत्र में साढ़े 6 हजार दरख्वास्तें इन लोगों की आयी थीं और एक एक दरख्वास्त पर 10–10 रुपये खच आये थे। अब लगा लीजिये हिसाब कि सार प्रदेश में कुल दरख्वास्तों पर कितना रुपया इन गरीबों हरिजनों का खर्च हुआ होगा। लेकिन इसके बाद इस समाजवादी सरकार ने दिया क्या ? एक एम0 एल0 ए0 के क्षेत्र में इन्होंने 3 हजार रुपया केवल दिया 3 आदमियों के लिये। 6 कुओं क लिये 6 हजार दिया। कुल 9 हजार दिया। 2,500 रुपये 5 मशीनों के लिये दिये। अब देखिये कि कितना भारी प्रचार और एलान किया गया, कितने हरिजनों ने पसा खर्च करके अपनी दरख्वास्तें दीं, और उनको मिला क्या ? यह सरकार एक एक हरिजन तथा एक एक मुसलमान के नाम को बेचकर यहां कुर्सी पर बैठी हुई है। मैं तो पूछता हूं कि हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बतायें अगर उन्होंने किसी भी क्षेत्र के लिये कुल मिला कर 13 हजार रुपये से यदि अधिक दिया हो ? मगर हरिजनों की बड़ी दुहाई दी जाती है इस सरकार के द्वारा।

जमीन बाटने की बात भी सुन लीजिये। हमारे जिले में एक सरकार साहब हैं इन्डीकेट के मेम्बर, उनके पास तमाम जमीन पड़ी हुई है। 10 हजार एकड़ जमीन वहां होगी, मगर एक धुर जमीन भी यह सरकार नहीं निकाल सकी। कहां से जमीन बाटेगी यह सरकार ?

बिजली किसान को मिल नहीं रही है। पानी का अकाल पड़ा है। नहरें सूखी पड़ी हैं। इलाके सूखे पड़े हैं। यह सरकार ही बेपानी हो गयी है। पहले बेईमान सरकार के जमाने में 22 रुपया सिंचाई रेट था, अब इस ईमादार सरकार के जमाने में उसका रेट 69 रुपया हो गया है।

खाद पहले 40 रुपये में थी, इस समय 65 रुपये में है। तो यह कौन देखता है ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है, कौन मंत्री जिम्मेवार है ? दूसरी बात इस समय बाजारों का हाल सुनिये। एक किसान दो डलिया चावल लेकर जाता है, तो उसमें वह मिट्टी का तेल भी नहीं पाता है। किसान ढिबरी जलाता है। उसके पास न पानी है, न मिट्टी का तेल जलाने को है। जिस देश में किसान को चिराग जलाने का पैसा नहीं मिल रहा ह, जिस देश में पानी नहीं मिल रहा ह, उसमें समाजवाद कैसे आएगा ? एक अजीब बात और है, आप कहते हैं कि चौधरी जी गलत बोल गये, लेकिन 76 करोड़ का घाटा आपके बजट के अनुसार है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो आपने दिया है, चौधरी साहब का वह नहीं है, तो फिर गलत क्या है। आप टैक्स कहीं लगाते नहीं हैं तो फिर यह घाटा कैसे पूरा होगा। आज चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आप टैक्स लगाने का साहस नहीं कर पाते हैं, धीरे-धीरे इसमें बढ़ा देंगे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जितनी सड़कें बनी हैं, आप बताएं कहां बनी हैं। 3 रुपये की मजदूरी का जिक्र किया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक हरिजन को कहीं भी यह नहीं मिली है। मैं चुनौती देकर कहता हूं, पैन्योली जो हरिजनों के बड़े हमदर्द हैं बताएं वह हरिजनों को कहां मिली है। उन्होंने हरिजनों के लिए कोई काम नहीं किया है, वह कभी यहां बैठकर गाली देते थे और अब वहां पर बैठ कर गाली देते हैं। लेकिन वह कोई बात नहीं करते हैं, हरिजनों के लिए कुछ नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग कहते हैं कि महंगी नहीं है। शहर में जो राशन की दुकानें हैं, उनको समय पर राशन नहीं मिल रहा है देहाती आदमी हों या शहरों के, किसी को भी अनाज नहीं मिल पाता है।

(इस समय 4 बजकर 9 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पुनः पीठासीन हुए।)

12 हजार क्वींटल चीनी यह मेरठ में देते हैं और 6 हजार क्वींटल देते हैं गोरखपुर में। तो यह मतभेद क्यों है, जब कि जनसंख्या दोनों की करीब करीब बराबर है यही हाल देवरिया का है। आप दोनों तरफ एक नीयत से देखें। जो काम अच्छा करेंगे उसका मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं जनता का दुश्मन नहीं हूं, वह दुश्मन हैं जनता के। उनकी नीति दुश्मन का काम कर रही है। 25 तारीख को जो रेडियो से ऐलान किया गया है, वह व्यर्थ है, किसी को मिली नहीं। कागज पर मकान बना दिये गये, लेकिन मौके पर बने नहीं हैं। हरिजनों की दुहाई दी जाती है, जो बिलकुल असत्य है। 13–14 हजार किसी विधायक क्षेत्र में दिया गया जो आप हरिजन-हरिजन चिल्ला रहे हैं। यह जो सिंचाई और बिजली का सवाल है। आपने सिंचाई के लिए एक बार पानी दिया है अगहन महीने में, लेकिन सिंचाई का पैसा चार बार का पूरा वसूल कर रहे हैं? तो किसान ने पानी पाया एक बार, जब आपने समाजवाद का ठेका लिया है तो ठेकेदार को ठेका का काम सोचना चाहिए, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय इनसे कहिए कि एक दफा पानी दिया है तो दो दफा पानी का रेट न वसूल करें, बाकी जो रुपया वसूल कर रहे हैं वह बन्द करें।

दूसरी बात यह है कि हमारे जिले में एक गांव को बिजली नहीं मिल रही है। किसान ने पैसा खर्च करके बिजली लगवाया, बिजली लेकर मोटर बैठाया, लेकिन बिजली उसको मिलती नहीं है। और यहां कहा जा रहा है कि कटौती करके बिजली किसान को दे रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, आप भी किसान हैं। इनसे कहिए जांच करवाएं। गोरखपुर जिले में महराजगंज तहसील में इनकी बिजली नहीं दी जा रही है जिससे वह खेत की सिंचाई करे, गन्ना बोयें। अब जब खेत कटने को है तो नहर में पानी आया है। अब आप बताएं अगर इस समय गेहूं में पानी छोड़ देंगे तो खेत भर जायगा। किसान काटने से मजबूर हो जायगा।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय तिवारी जी ने कहा है, पानी आ गया है नहर में। हमारे यहां से सूचना आयी है कि फैजाबाद जिले में घाघरा कनाल में एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। गेहूं की फसल नष्ट हो रही है। माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करवा दीजिये।

श्री महातम प्रसाद तिवारी—

इस समय पानी हमारे यहां आ गया है। अगर यह पानी डढ़ दो महीने पहले आया होता तो किसान की पैदावार अवश्य बढ़ी होती। लेकिन पानी नहीं आया। इसके लिए

[श्री महातम प्रसाद तिवारी]

पचासों बार लिखा गया। लेकिन सुनता कौन है? समाजवाद-समाजवाद सुनते सुनते जनता मरी जा रही है, किसान अलग मरा जा रहा है और हम लोग 425 अपने मरे जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

आप माननीय मंत्री जी से पूछिए किधर पानी बहता है।

श्री महातम प्रसाद तिवारी—

अधिकतम जोत सीमा की जो बात चल रही है मेरे जिले में जितनी जमीन है, पपलू, टपलू, काकी, नानी के नाम से, जैसे सरदार साहब हैं, राधारमण हैं, इन लोगों की जितनी जायदादें हैं, सारी जमीन की जांच करायी जाय। जो जमीन हिसाब से आती ह वह हरिजनों को दी जाय। किसी हरिजन को एक धुर जमीन नहीं मिलगी।

हमारे यहां हालत ऐसी है, जितनी नहरें हैं, एक चमखा नगरहा नहर है। आज पांच वर्ष से नहर बनी है। लाखों एकड़ जमीन सिंचाई होती। चार फर्लांग जमीन एक बड़े आदमी के नाम पर छोड़ी गयी है। नहर नहीं खोदी जा रही है। किसान पानी नहीं पा रहा है। इसके लिये मैंने गवर्नमेन्ट को, क्लेक्टर को नोटिस दिया है कि 24 तारीख को उसके विरोध में सिंचाई दफ्तर पर सत्याग्रह करने जा रहे हैं। अगर चार फर्लांग नहर खोद कर नहीं चलायी गयी तो 24 तारीख को जिला हेडक्वार्टर पर जो मुझसे होगा वह करूंगा।

दूसरे एक गलत काम कर रहे हैं। आप समझा दें। चमखा रबहा तीन फर्लांग दे रहे हैं। चार फर्लांग में एक बड़े आदमी की जमीन न खोद कर, इसमें से खोद कर इसमें मिलाते हैं। यह समाजवाद के पुजारी बने हुए हैं और समाजवाद की ठेकेदारी लिये हुए हैं तो उसकी व्यवस्था करो। हरिजन क्या पायेगा? तीन फर्लांग खोदी जायगी तो कितने आदमियों की जान जायेगी। 4 फर्लांग खोदी जायगी तो बड़े आदमियों की जमीन जायगी? इन शब्दों के साथ मैं बजट का घोर विरोध करता हूं।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं आपका बहुत अनुग्रहीत हूं कि जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं वित्त मन्त्री के बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बजट प्रदेश की जनता क हित में है। इससे अच्छा बजट आज तक किसी भी वित्त मन्त्री ने पेश नहीं किया। बजट में जो चतुर्मुखी उन्नति की बात कही गयी है वह किसी से छिपी नहीं है।

श्री भगेलू सिंह—

इसी वकालत से मालूम होता है कि बिक गये हो।

श्री प्यारे लाल—

ठाकुर साहब जो जैसा होता है वैसा दूसरे को समझता है। आप अपने दिल के आइने में स्वयं का चेहरा देखकर मुझे कह रहे हैं।

श्री भगेलू सिंह—

असेम्बली का हर सदस्य जानता है कि तुम बिक चुके हो।

श्री प्यारे लाल—

जो चतुर्मुखी उन्नति हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। लेकिन प्रदेश में 8 करोड़ की आबादी है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में आशातीत उन्नति हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में जो उन्नति

पिछले दो तीन सालों तक नहीं हुई थी, वह इस साल 1972–73 में हुई। बिजली की कमी दूर करने के लिये टेहरी डेम, बुलन्दशहर में नरोरा अणुचालित पावर हाऊस बनाया जा रहा है। तथा अनेक और भी छोटे-छोटे। यह काफी उन्नति के सूचक हैं। इसके साथ बिजली पैदा करने के लिये जो मशीनें व यंत्र खरीदे जा रहे हैं वह भी किसी से छिपा नहीं है। जैसा वित्त मन्त्री ने बतलाया प्रदेश की उन्नति के लिये कानपुर में रक्षा उत्पादन मन्त्रालय द्वारा दो फक्टरियां खोली जा रही हैं––रायबरेली में टेलीफोन, लखनऊ में स्कूटर, मथुरा में एक रिफाइनरी, अल्मोड़ा में मेगनेसाइट प्लांट बनाया जा रहा है। प्रांत को कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहां सरकार की तरफ से फैक्टरी न लगाई जा रही हो। कहां तक गिनाऊं आज तक इतनी फैक्टरीज सरकारी क्षेत्र में कभी नहीं लगी।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)––
गाजियाबाद में क्या हो रहा है?

श्री प्यारे लाल––

गाजियाबाद में अगर कोई सरकारी फैक्टरी नहीं लगाई गयी तो उसके लिये आप भी उतने ही दोषी ह जितनी दोषी कि यह सरकार है। गाजियाबाद ने अपने पैरों पर खड़े होकर उन्नति की है लेकिन देखना यह है कि सारे प्रदेश में फैक्टरियां लगाई जा रही हैं ताकि उन्नति हो। प्रधान मन्त्री जी ने रोजगार देने हेतु धन देकर सड़कें प्रदेश में बनवायी ह। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुछ जितनी सड़कें बनीं उतनी अकेले 72–73 में बन गयीं यह प्रदेश की उन्नति का सूचक है। सिंचाई के क्षेत्र में झांसी में जमनिया बांध तथा हमीरपुर में चन्द्रावल बांध बनाये जा रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा जमीन में सिंचाई हो सके। हजारों ट्यूबवेल प्रति वर्ष लगाये जाते हैं।

इस तरह से प्रदेश की उन्नति किसी से छिपी नहीं है यहां की गई आलोचना तथ्यहीन है। लेकिन जहां तक बेरोजगारी गरीबी का सवाल है उसके लिये मैं माननीय मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। प्रदेश की जनसंख्या आज 9 करोड़ है। सरकार द्वारा लगाई गई इन फैक्टरियों से सारे बेरोजगारों को रोजगार मिलना संभव नहीं है। प्रदेश में लगभग 66 फीसदी आदमी ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं हैं यानी करीब 6 करोड़। नयी फैक्टरियों के खुलने से कुछ को कार्य अवश्य मिलेगा लेकिन यह जो भयंकर बेरोजगारों की तादाद है उनको जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक अशांति बनी रहेगी।

डाक्टर लोहिया कहा करते थे "जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा।" मैं उनके कथन से पूर्णतया सहमत हूं और इसी को दूर करने के लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वे सुझाव यह हैं कि प्रत्येक गांव को बिजली और सड़क से जोड़ा जाय, प्रत्यक खेत को पानी दिया जाय। आप कहेंगे इसके लिये पैसे की जरूरत है। तो पैसे के लिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जितना बकिया टैक्स करीब 40 करोड़ के पड़ा हुआ है उसको सख्ती से वसूल किया जाय क्योंकि हर साल वसूली ना होने के कारण कर की धनराशि बट्टे खाते में पड़ जाती है। क्योंकि टैक्स की वसूली में ढील होती है और जब अनेक साल हो जाते हैं तो वह धन बट्टेखाते में पड़ जाता है। वह सख्ती से वसूल होना चाहिये। इसी तरह से नलकूपों से प्रत्येक वर्ष 9 या 10 करोड़ रुपये का घाटा रहता हैं। यदि नलकूपों को प्रदेशीय सरकार ठेके पर किसानों को द दे तो जो यह हर साल 9 या 10 करोड़ का घाटा होता है वही पूरा न होगा उसके साथ-साथ जो ठेके से कर्ज दो करोड़ की आमदनी आयेगी उससे 12 या 13 करोड़ रुपय तक आमदनी बढ़ जायगी।

इसी तरह से भूमि संरक्षण विभाग है यानी जिस खेतों का वर्षा से कटाव होता है और जो उनकी मड़बन्दी के लिये बनाये गये हैं लेकिन वह कहीं मेड़बन्दी नहीं करते और पैसा बरबाद

[श्री प्यारे लाल]

जाता है। उस पैसे को भी 10, 15 साल के लिये रोका जाय। इसी के साथ साथ यू0 पी0 स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, एग्लो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन याइस प्रकार की अन्य कारपोरेशन जो सफेद हाथी पले हुए हैं जैसे इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ये सब जनता पर भार हैं। इन पर धन का अपव्यय होता है। ये आज सरकार और गरीब जनता के बीच में रोड़े बनी हुई हैं। इसी तरह से विद्युत परिषद और दूसरी परिषदें जितनी भी हैं उन सब में जो सफेद हाथी पल रहे हैं जब तक उनको समाप्त नहीं किया जाता तब तक गरीब लोगों को राहत नहीं मिलेगा। इससे भी करोड़ों रुपये की बचत होगी। प्रान्त में जितनी भी बार हैं, स्प्रिट की दुकानें हैं उनको भी देशी शराब की तरह ठेके पर दिया जाय। इससे भी करोड़ों रुपये की आमदनी बढ़ेगी। आज जो मोटरों के परमिट दिये जाते हैं उससे आमदनी नहीं होती है। लेकिन इससे भी आमदनी हो सकती है। आज प्रदेश का ऐसा कोई भी रूट नहीं है जिसकी कीमत तीस चालीस हजार रुपये से कम हो। अकेले जिले मेरठ में दिल्ली और गाजियाबाद तथा गढ़ और गाजियाबाद के रूटों की कीमत ढाई लाख प्रति परमिट है तो इससे भी करोड़ रुपये से ऊपर की आमदनी होगी। इसी तरह से बिक्री कर उत्पादन पर लगा कर सख्ती से वसूल किया जाय और एक जैसे कर लगाया जाय तो बिक्री कर से भी आमदनी दुगुनी हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि उच्च सूत्रों से पैसा इकट्ठा किया जावे तो कर लगाने की जरूरत ही नहीं होगी और प्रत्येक गांव सड़क और बिजली से जुड़ सकता है और प्रत्येक को पानी भी मिल सकता। जिससे लगभग काफी बेकारी स्वयं समाप्त हो जावेगा।

इसी के साथ-साथ भूमि का ठीक से बटवारा भी किया जाय। अब जो सीलिंग तय हुई है उससे अधिक भूमि निकलने वाली नहीं है वह तो भूमिहीनों की संख्या देखते हुए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। लेकिन भूमि जहां है अगर सरकार मजबूती से वहां से भूमि निकाले तो करीब 1 करोड़ या डेढ़ करोड़ एकड़ भूमि निकल सकती है। आज भूमि किसके पास है। जो रिटायर्ड आफिसर्स हैं या वर्तमान आफिसर्स हैं उनके पास फार्म्स हैं। मिनिस्टरों और एम0 एल0 एज0 के पास फार्म्स हैं, बड़े बड़े जो सेठ साहूकार हैं उन लोगों ने अपने काले धन को सफेद धन में बदलने के लिये बड़े बड़े फार्म्स बनाये हुए हैं और चौथे जंगलात के पास काफी जमीन पड़ी हुई। इन चारों स्थानों से जमीन यदि इकट्ठी की जावे तो प्रदेश के भूमिहीनों के लिये जमीन निकल सकती है। आज जो सीलिंग से 2 या ढाई लाख एकड़ जमीन निकलेगी वह भूमिहीनों के लिये काफी नहीं है। यदि मेरे ऊपर के बताये गये ऊपायों से सुझावों से भूमि ली गयी तो आधी बेरोजगारी इससे दूर हो सकेगी यदि फिर भी बेरोजगारी रहती है तो मिलों में उत्पादन की आवश्यकता को देखते हुए वहां 6–6 घंटे की चार शिफ्टें कर दी जावें। इसके साथ ही कुटीर उद्योग और लघु उद्योग चालू किये जावें जिससे प्रदेश के गरीब बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा। इन लघु उद्योगों को सरकारी सहायता एवं संरक्षण मिले। जिस तरह से बजट बनाये जाते हैं और कर की रकम बट्टे खाते में डाल दी जाती है, वसूल नहीं की जाती है तो इस तरह से प्रदेश की उन्नति होने वाली नहीं है और न गरीबी मिटेगी तथा न ही बेरोजगारी ही मिट सकेगी गरीब व बेरोजगारी मिटेगी उक्त सुझावों से।

आज जो समाजवाद का नारा हमारा है कि प्रत्येक गांव में बिजली होगी, प्रत्येक गांव में सड़क होगी, प्रत्येक खेत को पानी मिलेगा प्रत्येक व्यक्ति को रोजी, रोटी व मकान मिलेगा। वह वैसे ही रह जायगा। हमारे पश्चिमी जिलों मेरठ व आगरा डिवीजन आदि में लाखों एकड़ जमीन चौया व ओगल से पानी में डूबी रहती है। पूर्व में जरा सी भी एक नाले में बाढ़ आती है तो वे चिल्लाने लगते हैं। हमारे यहां तो लाखों एकड़ जमीन ओगल और चौया से डूबी रहते है, उसमें ऐसा होता है कि जरा सी वर्षा के बाद अपने आप जमीन के अन्दर से पानी निकलना शुरू हो जाता है। इससे उस फसल को तो नुक्सान होता ही है जो कि पकी हुई होती है लेकिन आगे आने वाली फसलों को भी नुक्सान होता है। इस समस्या को सुलझाने का एक ही तरीका

है कि बड़े पैमाने पर नाले खोद दिये जायं और जहां-जहां नहरें हैं वहां-वहां ट्यूबवेल लगा दिये जायं क्योंकि जो नहर से जितना स्तरपानी का जमीन के ऊपर आता है इन ट्यूबवेलों के जरिये से उतना ही पानी का स्तर नीचे जायगा । इस तरीके से भी देश के अनाज के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है । क्योंकि लाखों एकड़ भूमि खेती योग्य ओगल से बचेगी जिससे देश की भुखमरी मिट सकती है तथा ऐसा करने से रोजगार भी लोगों को मिल सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । गाजियाबाद श्रमिकों का नगर है करीब 60 हजार श्रमिक वहां वास करते हैं परन्तु उनके लिये सस्ते किराये के मकान व सस्ते प्लाटों की कोई व्यवस्था नहीं । सरकार को चाहिये उन्हें सस्ते किराये के मकान अथवा प्लाट की व्यवस्था करे । मेरे क्षेत्र गाजियाबाद में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट और मास्टर प्लान में जो कि सन् 60–61 में बना था उसके तहत गरीबों की आबादी को एक्वायर कर लिया गया था । लखनऊ के ठंडे कमरों में बैठकर लाल नीले पेंसिल घुमाने के पश्चात् वहां के गरीबों की आबादी को ग्रीन बैलर व ओपिन स्पैश दिखाकर एक्वायर कर लिया गया । मकानों को नियमित करने की कार्यवाही अभी तक नहीं पूरी हुई है जबकि स्क्रीनिंग कमेटी व कन्ट्रोलिंग अथारिटी उन आबादियों को नियमित करने हेतु रिपोर्ट दे चुकी है परन्तु सरकार की तरफ से उस पर दस्तखत होकर वहां नहीं गये हैं । अनेक सालों से उक्त रिपोर्ट सरकारी फाइलों में दबी पड़ी हुई है, उन्हें निकालने की कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिससे गरीब परेशान है । उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे गाजियाबाद में 7, 8 हजार मकानों के डिमोलिश करने के आदेश हैं । आज गरीब आदमी चैन से नहीं सो पा रहा है जब तक उनके मकानों को नियमित नहीं करा जाता है वह चिन्तामुक्त नहीं होंगे । उनके ऊपर दुधारू तलवर लटक रही है कि उसके मकान एक्वायर कर लिये गये हैं तो वह कैसे चैन से सो सकता है । मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे गाजियाबाद के मकानों को नियमिति करने की कृपा करे । वे स्वयं वहां पर जाकर देखें विभागीय सचिव को वहां जाने के लिये कहें और स्थिति को देखें । यदि वे नहीं जा सकते तो कंट्रोलिंग अथोरिटी को भी उन मकानों को निमिति कराने का आदेश दें ताकि गरीबों को कुछ राहत मिल सके । सन् 62–63 में जो जमीन ली गई थी उसका मुआवजा भी अभी तक बहुत से कृषकों को नहीं दिया गया है । यह कहा गया था कि किसानों के लिये एक लैंड पालिसी बना दी गई है उसके तहत भी कुछ नियम बनाये गये थे जिससे 47 प्रतिशत लैंड पालिसी से कृषकों को देने की बात थी जो कि किसानों के फायदे के लिये आवश्यक थे किन्तु उसकी कोई सूचना का गजेट नहीं किया गया नहीं अखबारों में छपवाया गया कि उसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है । किसानों की दरख्वास्तें सरकार के पास आई लेकिन यह कहकर खारिज कर दी आपका प्रार्थना पत्र समय के बाद में आया है अब चूंकि उसकी अंतिम तिथि समाप्त हो गई है इसलिये उन पर विचार नहीं होगा । अतः मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वे इन दरख्वास्तों पर विचार करें ताकि जिनकी जमीन ली गई है उनको कुछ फायदा हो सके लैंड पालिशी में भूमि प्राप्त कर वह अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सके । सरकार अपनी कथनी और करनी को एक करें तभी समाजवाद आ सकता है वरना समाजवाद की परिकल्पना नहीं की जा सकेगी ।

आज मैं बी0 एल0 डब्लुज0 के अधिवेशन में गया था । वहां यह मालूम हुआ कि माननीय आर्य जी जो कि सामुदायिक विकास मन्त्री हैं, उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि तुम्हारा हम अलग से निदेशालय कर देंगे और तुम्हारे विभाग में होने वाली पदोन्नति में 5 प्रतिशत स्थानों पर तुम्हारी ही तरक्की की जायगी । लेकिन आज तक उनकी इन दो बातों को नहीं माना गया । यह कार्यवाही उनके बारे में आज तक नहीं हो पायी है । इस तरह से जो आश्वासन आप देते हैं गरीबों के बीच में जाकर, उनको अवश्य पूरा करना चाहिये । वर्ना समाजवाद का नारा हवा में रहेगा । गरीब का सरकारी आश्वासनों से व सरकार से विश्वास डोलेगा और जब विश्वास डोलेगा तो असंतोष बढ़ेगा और फिर खूनी क्रांती रूपी दानवता जन्म लेगी ।

[श्री प्यारे लाल]

हां मैं तो इस राय का हूं कि यदि सरकारी आश्वासन पूरे न हुए तो फिर असन्तोष बढ़ेगा और उसकी वजह से सरकार को दुरदिन देखने पड़ेंगे।

इसी के साथ साथ मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि आज सारे प्रदेश में भय का वातावरण व्याप्त है क्योंकि सारे प्रदेश में लूट पाट, राहजनी, डकैती और कत्ल बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। मेरे क्षेत्र गाजियाबाद में ही अकेले फरवरी माह में 20 कत्ल हुए, 25–30 डकैतियां पड़ीं और राहजनी की अनेक घटनायें हुई। 16 फरवरी को शम्भूदयाल कालेज में जो थाने से करीब डेढ़ फर्लांग की दूरी पर है दिन के 12 बजे करीब दो हजार आदमी लाठी, बल्लम, हाकी व रिवाल्वर आदि हथियारों से लैस होकर गये और उनके कालेज में घुसने के पहले पुलिस को टेलीफोन हुआ कि जल्दी आइये वरना यहां गोली चलने का अन्देशा है क्योंकि कुछ लोग रिवाल्वर से लैस हैं। आधे घंटे तक मारपीट होती रही जिसमें एक लड़के की मृत्य हो गयी और एक लड़का मृत्य शैय्या पर पड़ा रहा अनेक घायल हुए। एक घंटे के बाद पुलिस घटना स्थल पर गई। गाजियाबाद माडल टाउन जो पुलिस थाने से पौने दो फर्लांग की दूरी पर है 8 बजे डकैत दो ट्रक लेकर गये और डकैती डाली ट्रकों में सारा सामान लेकर वे चले गये, कोई पकड़ा नहीं गया। विजय नगर में आठ मकानों को लूटा। 28–2–73 को शाम को 7 बजे जोदपुर ग्राम में डकैती 3 घंटे तक डालकर चले गये।

एक सदस्य—

फिर उधर क्यों हैं, उस दल को छोड़ कर इधर चले आइये।

श्री प्यारे लाल—

आप भी कम नहीं है। आपके जमाने में तो इससे भी ज्यादा अनियमिततायें होती हैं मेरे क्षेत्र मसूरी में थाने से मुश्किल से 100 गज के फासले पर शाम को 7 बजे तक एक पेट्रोल पम्प को डाकुओं ने लूट लिया लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंच सकी राहजनी की तो गिनती ही नहीं। इस तरह की वारदातें सारे प्रदेश में हो रही हैं। शाम के 8 बजे से सुबह तक इस तरह की वारदातें होती रहती हैं और कोई पकड़ में नहीं आता कार्यवाही में चला जाता है। कोई सुरक्षा नहीं, समय का अपव्यय होता है। यदि इस प्रदेश की बेरोजगारी खत्म हो जाय, भुखमरी खतम हो जाय गरीबी मिट जाय तो इस तरह की लूटपाट अपने आप खतम हो जायेंगी। फिर न चोरी डकैती होगी, न लूटपाट होगी, फिर साल में कोई एक दो ऐसी घटना देखने को मिल जाय तो भले ही मिल जाय लेकिन आम तौर पर ऐसी वारदातें नहीं होंगी। लेकिन जब तक सरकार इस विषय पर गंभीरता से नहीं सोचेगी और यहां से बेरोजगारी व भुखमरी नहीं मिटेगी तो फिर एक न एक दिन यही गरीबी, बेकारी, भुखमरी की समस्या खूनी क्रांति का रूप ले लेगी। इस सबके लिये मन्त्री दोषी नहीं है। ये जो आपके आई0 सी0 एस0 और आई0 ए0 एस0 आफिसर हैं वे इस तरह के कायदे, कानून व योजना बनाते हैं जिससे जनता में असन्तोष बढ़ता है। और अगर इस बढ़ते हुए असन्तोष को समय से नहीं रोका गया तो पूरे प्रदेश में जनता द्वारा जो भयंकर खूनी क्रांति होगी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर पायेंगे। अगर आप सही माने में गरीबी को मिटाना चाहते हैं और प्रदेश की 9 करोड़ जनता को राहत दिलाना चाहते हैं तो फिर मैं साफ कहता हूं कि इन आई0 सी0 एस0 और आई0 ए0 एस0 आफिसरों को तुरन्त हटाओ जिनके कृत्यों ने इस देश और प्रदेश को नरक बना रखा है, जब तक उनको खत्म नहीं करेंगे तब तक इस प्रदेश की गरीब जनता को राहत नहीं मिलेगी और न बेकारी और न भुखमरी ही मिटेगी। वे इस देश और प्रदेश के लिये एक कोढ़ हैं जो पच्छिमी सभ्यता के उपासक तथा देश की समस्या से अनभिज्ञ हैं इसे जितना जल्दी हो सके इस देश और प्रदेश को छुटकारा दिलाया जाय तब ही इस देश और प्रदेश का जनता तरक्की करेगी तब ही खराबी, गरीबी, बेकारी व दामों की लूट समाप्त होकर समाजवाद आयगा। जब तक इन आफिसरों के द्वारा बनाये गये कायदे कानून व योजना लागू रहेंगे तब तक इस प्रदेश की 9 करोड़ जनता को कोई

फायदा नहीं होने वाला है इसी प्रकार कराहती रहेगी। क्योंकि ये आफिसर भी तो उन्ही पूंजीपतियों और सेठों और जमींदारी के लड़के हैं। वे उसी तरह का कानून बनाते हैं नीति व योजना बनाते हैं जिससे सेठ, साहूकार और जमींदारी को फायदा हो और गरीबों का अहित हो गरीब ऊपर न उठे। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री भगेलू सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम लखनऊ से अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हम से लोग पूछते हैं कि सरकार का क्या हाल है? हमारे मुंह से यही आवाज निकलती है कि सरकार है ही नहीं। अगर सरकार होती तो डाके, चोरी, घूस और लूट वगैरा का कोई खतरा नहीं होता। 25 साल से यह हरिजनों से कहते हैं कि हम तुमको जमीन देंगे। लेकिन खाली बातें ही बनाते हैं। हरिजन और मुसलमान इन दोनों के भरोसे ही यह सरकार टिकी हुई है। लेकिन यह इन दोनों के दुश्मन हैं। हमारे क्षेत्र में एक गरीब से नोट ले लिये और उसको जमीन भी नहीं दी। ग्राम सभा की आराजी गरीब किसान, चमार और मुसलमान को कतई नहीं मिली और यह डींग मारते हैं, "एक हाथ की ककरी और नौ हाथ का बीजा"

यह लोग समाजवाद का नारा लगाते हैं। इन्होंने ऊपर से खाली समाजवाद की खाल ओढ़ ली है। गरीब जनता से इनकी दुश्मनी है। हमारे जिले में जमींदारी खत्म हुई तो जितने कांग्रेसी लोग हैं उन्होंने अपने-अपने फार्म बना लिये। राजा बलरामपुर वगैरा से जमीन लेकर अपने फार्म बना लिये। मन्त्री लोग तो चौपट राज हैं। गरीब मुसलमान प्याज बहुत खाता है। आज जितने लोग उधर से बोले हैं वह सब खरीदे गये हैं और उनका काम है कि वह बोलें और तोते की तरह से पढ़ दें। इंडीकेट से जो चुनकर आये हैं उनमें से कोई नहीं बोला है। अगर ये खरीदे हुए नहीं होते तो इनकी हिम्मत विरोधी दल के लोगों के खिलाफ बोलने की नहीं होती।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र के अन्दर आज भूमिहीन तबाह हैं और तकावी का अनुदान गरीबों को नहीं मिला है। बड़े-बड़े कर्मचारी और चलते पुर्जे कांग्रेसी लोग खा गये हैं। उदितनारायण जी यहां मौजूद हैं। हमने उनको दरख्वास्त दी है कि रामचन्द्र कहार लखनऊ में नौकरी करता है उसके नाम से रुपया निकाल लिया गया है। एक सात साल का लड़का भन्द्रमान नाम का है उसके नाम से रुपया निकाल लिया गया है हमने कई दरख्वास्तें मन्त्री जी को दी और जिलाधीश को दी लेकिन कागज वैसे ही पड़े हैं और कोई जांच नहीं होती है। इनके राज्य में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है। कहां तक बताया जाये सड़कों को देख लीजिये, घरों को देख लीजिये, किसी भी चीज को देख लीजिये, कहीं कुछ नही हो रहा है। यह सरकार टाटा बिड़ला की हिमायती है। यह तो खाली सेखी बघारते हैं। समाजवाद यह क्या जानें समाजवाद इन्होंने देखा भी नहीं है। जब इन्होंने देखा कि डाक्टर लोहिया ग्रुप आगे जा रहा है तो इन्होंने समाजवाद का नारा लगा दिया और सामाजवाद की खाल ओढ़ ली। इसके राज्य में गरीब सुख से नहीं सोता है, थानेदार और तहसीलदार के यहां कोई सुनवाई नहीं होती है। थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। इनके राज्य में कर्मचारी मालिक बने बैठे हैं। धनी गरीब का दुश्मन है। जब से इनका राज्य हुआ है तब से इनको और ओहदा मिल गया है। जितनी झूठी रिपोर्ट कोई दरोगा लिखता है उतना ही वह लायक है। हमारे माननीय बंशीधर शुक्ल जी आये थे। उन्होंने एक कविता सुनाई थी। हमने उसको याद कर लिया है वह इस प्रकार है कि...

"कमलापति के हाथ में बंधी राज सरकार।
जैसे मेहरा के गले फंसी शंखिनी नार।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगेलू सिंह]

इन्दिरा जी को जीत भयी इन्द्री ढील ।
पत्नी पत्नी पर चढ़े पति हो गिरे जलील ।
सब पत्नी कारज सिखें बने सिखंडी बीर ।
सम्भव है सहना पड़े पुत्र प्रसव की पीर ।।"

उपाध्यक्ष महोदय, कहां तक बरनो झबरी गुन तोर । जो कुछ भी इनके लिये कहा जाय वही बात है कि भेंडा मोट भवानी दूबर। आज गरीब के लिये चीनी नहीं । गरीब के लिये कपड़ा नहीं, उसके लिए अनाज नहीं केवल उसके लिए समाजवादी नारा है । जो हरिजन कार्यकर्ता है वह हम कहा करते है कि यह समाजवाद के दुश्मन हैं, यह हरिजनों के, मुसलमानों के दुश्मन है, कहीं उनके लिए गुंजाइश नहीं है । यह गरीब का हाल क्या जानें । इनके अन्दर गलतियों के सिवा और कुछ है ही नहीं । हमारे यहां देहात के नलकूप के लिये प्रार्थना की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ । यह सरकार और इसके सारे कर्मचारी एक हैं, केवल यह समाजवाद का नारा लगाते हैं । हमारे क्षेत्र में मछली का नीलाम होता है सभी जानते हैं कि आज मछली का भाव कितना हो गया है और नीलाम का भाव भी ज्यादा होना चाहिये लेकिन सारा पैसा इनके चेला चापड़ खा जाते हैं। कोई पुछवैया नहीं है । लेकिन जैसे यह आये हैं वैसे ही यह जायेंगे, यह आप निश्चित समझें । हर जगह ढील है । बजट भाषण में चाहे जो कुछ सुना दें लेकिन यह समाजवाद नहीं ला सकते । गरीब तो इनका दुश्मन है और यह तो भी ईमानदारी के दुश्मन हैं । इनके राज में है क्या ? खेत किसी का और पटवारी और तहसीलदार लिखते कुछ हैं । अगर दरखवास्त दी जाती है तो कोई सुनता नहीं । राम शंकर कहार, जो आलमबाग में रहता है और जो डेढ़ साल से घर नहीं गया है उसके नाम से रुपया तकाबी का निकाल लिया गया लेकिन मंत्री जी को 20 दरख्वास्त दी कुछ नहीं हुआ । टकरू साहब हमसे हुकुम सुनाये, हमने उनसे कहा कि अगर 16 आने में यह बात 1 आना भी सच हो तो जीप पर हमारे गांव चलो और अगर वहां 100 में 99 आदमी कह दें कि न रामचन्द्र को न राम शंकर को तकाबी का रुपया मिला है तो हमारी बात मान लें लेकिन कोई कहीं गया और वहीं कागज पर मौजूद हैं, न कोई इंक्वायरी होती है । अगर यह गरीब के दुश्मन नहीं हैं तो फिर इंक्वायरी क्यों नहीं होती ?

बड़े लोगों से कोई रुपया वसूल नहीं करता गरीब पर अगर 2 रुपया भी बाकी है तो उस से जबरदस्ती वसूल किये जाते हैं । आज गरीब के पास खाने को नहीं है, यह चिल्लाते हैं समाजवाद आ रहा है, ऐसे नारों से इन की गाड़ी कितने दिन चलेगी । अनाज मोल लेने जाइये नहीं मिलेगा, चीनी गरीब को कहीं नहीं मिलेगी, सब बड़े लोगों के हाथ बिकती है ? और माननीय मंत्री जी रोज हिसाब किताब बना देते हैं लेकिन गरीबों के लिये कुछ नहीं हो रहा है । आज गल्ले के खेत सूख रहे हैं, न पानी है, न बिजली है गन्ने वाले के दाम भी आज मिल मालिकों पर बकाया पड़े हुए हैं लेकिन वह रुपया उन गरीबों को वसूल नहीं हो पा रहा है । जो कुएं लगाते हैं, वे सब के सब जानते हैं कि वे कितने दिन चलते हैं मेरी तो यह धारणा है कि जहां भी इन इंडीकेट वालों का हाथ लगता है । चाहे कोई भी काम ले लो, सब में बंटाधार हुआ है । आखिर कौन से इनके काम के लिये इन्हें जनता चुनेगी ? क्या इनको हिन्दू और मुसलमान में लड़ाई कराने के लिये चुनेगी ? ये 2–4 आदमियों को इधर से खरीद लेती है और फिर उनसे अपनी वकालत कराते हैं । धोखा देकर, इनको खरीदा गया है । हालत क्या रही ? ये लोग खरीदे गये हैं, ये अब कहते हैं कि इंडीकेट सरकार ही समाजवाद लायेगी । क्या 25 सालों स भूमिहीनों को कोई भूमि मिली ? कुछ नहीं मिली । मंत्री जी के इलाके में 54 एकड़ हुयी और और जगह पर 27 एकड़ । आने वाले दिन बतायेंगे कि कैसा इनका समाजवाद है । इन्होंने कितनी जमीन बांटी ? जमींदारी खत्म हुई और अब हदबन्दी कानून लगाया गया है । जब जब चुनाव आते हैं इनके लोग स्टेशनों पर कहते फिरते हैं कि जो कुछ भी देश में सुधार होगा उसे इंदिरा जी ही करेंगी और कोई करने वाला नहीं है । कुछ यह कहते हैं और कुछ वह कहते हैं। गरीब के पास नहीं जाते हैं । कितनी बिजली, कितने कुएं, कितनी सड़कें इस सरकार ने बना दीं ? मेरे क्षेत्र में सूर्य नदी पड़ती है, उस पर एक भी पुलिया इन्होंने नहीं बनायी है जिससे

क्षेत्रीय लोग अपनी गाड़ी वगैरह लेकर पार हो सकें, शैखी तो बहुत बघारते हैं। हमारे जिल म एक माननीय सदस्य श्री गंगा प्रसाद जी हैं, वे बिना 5 रुपये लिये सार्टिफिकेट तक नहीं लिखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हर्बु चांदपुर में चमार के घर में एक आदमी को जान स मार डाला और उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गयी। वह रिपोर्ट करेगा, तो रिपोर्ट नहीं लिखित। यह समाजवाद है आपका।

अब इन्डीकेट का हाल बताई। बाप बिटिया पैदा किहिस। लड़की इंडीकेट में। पतोहू, वही इन्डीकेट मा। आखिर इंडीकट कै का भाषा है। हमरी समझ मा तो नहीं आवत। आज चुनाव जौन होत हैं वहमा वहै आदमी खड़ा कीन जात है, जेहिके पास लाठी-डण्डा और नोट कै जोर ह्वात है। उनहिन का टिकट द्यात हैं यी। उनसे का देश कै निर्माण हुये वाला है। जब तक हमै अंदर ईमानदारी ना आई, कथनी-करनी में फरक रही, तब तक ई का समाजवाद लइहैं। आखिर इनकी बदौलत देश मां का मिला। गन्ना सस्ता। चीनी तेज। आखिर यह कौन कानून है? चीनी तो बड़े-बड़े मील-मालिक पदा करते हैं। वह तो तेज है। लेकिन काश्तकार गन्ना पैदा करत है, वह सस्ता है। गहूं भी सस्ता है। जब किसान गन्ना कै दाम लियै जात है, तौ वहिका परेशान कीन जात है। जरवल और बाराबंकी वाले जेहिका सरकार लै लिहिस, वै और परेशान करत हैं। जहां-जहां इनके चरण पड़े, हुआं-हुआं चौपट होइगा। चीनी और गल्ला के दाम काहे नहीं बांध देत्यो? काल्हि बजट पेश करि दिहयो, वहिसे सुधार हुवै वाला नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---

अब खतम करें। काफी बोलि लिह्यो . . .।

श्री भगेलू सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, एक कबिता सुनाई के खतम करित है---

त्याग कर त्याग की पवित्र भावना में आज, पाप की प्रवृत्ति में प्रवीन बन बैठे हैं,
पल्टा जमाना तब निठल्ले कांग्रेसी भी, रकम कमाने की मशीन बन बैठे हैं।

कार्य से पतित हो चुके, धर्म सब छोड़ दिया,
तो भी इन्हें शर्म एक बार भी न आती है।

स्वारथ में रत हैं, बिलास में डूबे हुए,
पास अब दीन की पुकार भी न आती है।

ढुलमुल नीति में निपुण इतने हैं कि--
करते न हों, इन्कार भी न आती है।।

यई शब्दन के साथ हम बजट कै विरोध करित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपै का चही कि वहिकै विरोध करैं।

श्री उपाध्यक्ष---

हम आपकी भावना कै कदर करित हैं।

*श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज मैंने माननीय चौधरी साहब का भाषण सुना। उन्होंने जिस अभूतपूर्व शैली

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानु प्रताप सिंह---]

में और जिस मजाक भारी भाषा में जिसमें कि एक विनोद का पट था, अपना भाषण दिया, और साथ ही सदन का ध्यान आकर्षित किया, और हम लोगों को जो ज्ञानोपदेश दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वे हमारे बुजुर्ग हैं मान्यवर, आज सारी दुनिया जानती है जब कि किसी देश के सामने अनेकानेक समस्यायें होती हैं, तो जनता के मन में एक द्वन्द होता है। जब द्वन्द होता है तो बहुत सी बातें खुराफात की जाहिर होती हैं। खाली मस्तिष्क और किसी आदमी का व्यथित दिल की जो भाषा है वह चाहे मर्यादा रहित हो या मर्यादा सहित हो। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिये सदन और शासन के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह अलग अलग बात है कि अपनी अपनी योग्यतानुसार उन चीजों को सदन के पटल पर रखें। चौधरी साहब ने जिन चीजों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, उसमें 1-2 बातें जो कहीं गई हैं वह सच्चाई के विपरीत हैं, उन्हीं की ओर मैं ध्यान दिलाऊंगा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में 50 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्हें दो जून खाना नहीं मिलता। यह बात मैं इस प्रदेश के लिये और सारे देश के लिये मानने के लिये तयार नहीं हूं कि 50 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्हें दो जून का खाना नहीं मिलता। क्या मैं इससे यह समझूं कि आज ही नहीं मिलता या पहले भी नहीं मिलता। अगर आज 50 प्रतिशत नहीं मिलता तो पहले 60 प्रतिशत नहीं मिलता होगा। यह दोनों बातें 60 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की सही नहीं हैं। लेकिन यह सही है कि किसी प्रदेश की जनता जो 71 प्रतिशत खेती करती हो, या अधिकांश भूमि पर वहां के लोग भूख से मरें इस सबके लिये दोषी हैं हम और आप सब, चाहे वह इधर के पक्ष के बैठने वाले लोग चाहे उधर पक्ष के बैठने वाले लोग हों।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

वित्तीय वर्ष 1973-74 के एक भागके लिये लेखानुदान

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1973-74 के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

आज नियम 51 के अन्तर्गत 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना माननीय नित्यानन्द स्वामी की लखनऊ तथा इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों के वकीलों द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल के संबंध में है। यह सूचना पहले भी प्राप्त हुई थी और उसको स्वीकार किया गया था। वक्तव्य के लिये उसका नाम बढ़ा दिया जायेगा।

दूसरी सूचना श्री सुरेन्द्र बिक्रम की राज्य के पी० एम० एस० और मेडिकल कालेजों के डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाने से प्रदेश में विषम परिस्थिति से संबंधित है। इसको हमने अस्वीकार किया है।

तीसरी सूचाना श्री मनोहर लाल, श्री श्रीकृष्ण बाजपयी की केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्ध-तैयार चमड़े का निर्यात आरम्भ करने से कानपुर के चमड़ा उद्योग को क्षतिसे संबंधित है। इस पर आप सवाल कर सकते हैं। यह विषय उतना लोक-महत्व का नहीं है कि स्वीकार किया जाय।

चौथी सूचना श्री सईद मुर्तजा, श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री मोहम्मद असरार अहमद की मुजफ्फरनगर जनपद में मार्च के प्रथम सप्ताह में ओले पड़ने से रबी तथा आम की फसल को गहरी क्षति के संबंध में है। यह बात आप बजट भाषण में कहें और प्रश्न कर लें।

श्री सईद मुर्तजा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मान्यवर, यह बहुत इम्पार्टेन्ट है और हजारों लोगों की रोटी और रोजी का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह मामला एक जनपद से संबंधित है। आप अल्पसूचित प्रश्न करें लें।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)---

वहां बहुत ज्यादा क्षति हुई है, आप वक्तव्य दिलवा दें। मामला बहुत इम्पार्टेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष---

2-3-4 जिलों का होता तो मुनासिब भी था। एक जिले के बारे में वक्तव्य के लिये स्वीकार नहीं किया जा सकता। अल्पसूचित प्रश्न कर लें और अगर उससे संतुष्टि नहीं हो तो हम वक्तव्य दिलवा देंगे।

पांचवी सूचना श्री नेतराम सिंह, सियाराम, हिम्मत सिंह श्री हरिनाथ तिवारी, श्री सूबेदार प्रसाद नें मोहनपुरा बाजार के थाना मारेहरा, जिला एटा में बदमाशों के आतंक से जनता में क्षोभ व्याप्त के संबंध में दी है। यह हमने स्वीकार नहीं किया। केवल आतंक की स्थिति है।

श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)---

मान्यवर, यह बात सुन लें। दिन-दहाड़े एक व्यक्ति को गोली मार दी गयी। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। हो सकता है कि झगड़ा और बढ़ जाय क्योंकि वहां की जनता बहुत असंतुष्ट है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मान्यवर, आप इसको कार्यवाही के लिये मंत्री जी के पास भेज दें।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है, हम कार्यवाही के लिये इसको भेज देते हैं। श्री मलिखान सिंह, श्री मोहनलाल कपूर, श्री सूबेदार प्रसाद का है बिजली कटौती के कारण शीत गृहों के मालिकों द्वारा शीत गृहों में आलू रखने के भाव बढ़ा देने से किसानों में असंतोष। यह स्वीकार नहीं किया है। बजट भाषण में आप इसको उठा सकते हैं। माननीय चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री अब्दुल सलाम शाह, श्री महातम प्रसाद तिवारी का जलालाबाद के नायब दरोगा को गुन्डों द्वारा और सरे बाजार में पीटने से जनता में आतंक से संबंधित है। इसको भी स्वीकार नहीं किया है। अपने भाषण में आप यह चीज कह सकते हैं। श्री सुरेन्द्र बिक्रम और श्री बंशीधर पान्डेय का है म्युनिसिपल बोर्ड का गुड्डा के नव निर्वाचित उपाध्यक्ष को एस0 डी0 एम0 लैन्सडाउन द्वारा तीन महीने में चार्ज न देने से जनता में असंतोष यह भी स्वीकार नहीं किया गया। श्री शम्भू नाथ चौधरी, श्री शफीक अहमद खां, श्री त्रिलोक चन्द्र, श्री राम प्रसाद देशमुख, श्री मोहम्मद असरार अहमद ने फैजाबाद जनपद में जैतपुरा ग्राम के हरिजनों पर स्थानीय विधायक द्वारा किये गये अत्याचार के संबंध में दिया है। यह भी स्वीकार नहीं किया है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

इस पर कुछ निवेदन करने का मौका दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

यह हरिजनों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 23 में बेगार लेना वर्जित है और यह एक तरह से अपराध है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

वहां भूख हड़ताल हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष---

तो इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किये लेते हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

शीत गृह में आलू नहीं रखा जा रहा है। वहां कहते हैं कि हम मुआवजे के जिम्मेदार नहीं होंगे जबकि सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है कि अगर खराब होगा तो कम्पेन्सेशन दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आप बजट में उठा सकते हैं। आप भाषण दें और स्थिति बतलायें।

श्री बलबीर सिंह---

मने एक पत्र मुख्य मंत्री जी को लिखा था और उसी से संबंधित एक अल्पसूचित प्रश्न भी भेजा था।

श्री उपाध्यक्ष---

उसको हम देख लेंगे।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

[इसके बाद सदन 5 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रथल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
14 मार्च 1973।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 589 पर)

प्रश्न संख्या 22 का संलग्नक जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार दोषी समझे गये अधिकारियों तथा कर्मचारियों की तालिका---

राजपत्रित अधिकारी

सर्वश्री

1--के० सी० गोयल, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता
2--डी० एन० काला तत्कालीन अधीक्षण अभियंता
3--भगवान राठी, तत्कालीन स्थानापन्न अधीक्षण अभियंता
4--वीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता
5--अनीस अहमद अलवी, सहायक अभियंता
6--विनय कृष्ण सहायक अभियंता

अराजपत्रित कर्मचारी

सर्वश्री

1--रघुबीर सिंह, अधिदर्शक
2--मुन्शी लाल, अधिदर्शक
3--सूर्य नाथ मिश्र, टिंडेल
4--जगन्नाथ प्रसाद, तारबाबू
5--बेनी बहादुर, ,,
6--अमर्डल हरसिन, टेलीफोन आपरेटर
7--एच० वी लोशाली, सब डिवीजनल क्लर्क

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 19 एल०ए०--1973--835.